सूर्योदय 5:42 सूर्यास्त 7:13

आज का तापमान

शिमला 17.0 न्यू 22.7 अधि
धर्मशाला 21.0 न्यू 28.1 अधि

बाजार

सेंसेक्स 78,581
निफ्टी 24,624

सोना 1,46,000 चांदी 2,25,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | वीरवार, 6 अगस्त 2026 | 22 श्रावण, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 103, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

नितिन गडकरी से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट फौरन हटाएं : बॉम्बे हाईकोर्ट

एजेंसी, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट फौरन हटाने का आदेश दिया। साथ ही पोस्ट करने वाले यूजर्स की जानकारी भी मांगी। हाईकोर्ट ने इन कंपनियों से कहा, 'भविष्य में भी अगर मंत्री की ओर से ऐसा कोई कंटेंट ध्यान में लाया जाता है, तो उसे भी हटाया जाएगा।' गडकरी ने 27 जुलाई को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि सोशल मीडिया पर उन्हें और उनके परिवार को ई-20 इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से होने वाले कथित मुनाफे से जोड़ा जा रहा है। याचिका में कहा गया, 'लोग उनके खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट्स और मीम बना रहे हैं। इससे उनकी इमेज खराब हो रही है।' सुनवाई के दौरान मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम) और एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) के वकील कोर्ट में मौजूद रहे।

पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे : अभिजीत

एजेंसी, नई दिल्ली। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बुधवार को कहा,

'कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी फिलहाल राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। अभी भारत को एक मजबूत प्रेशर ग्रुप की जरूरत है, इसलिए कॉकरोच पार्टी उसी भूमिका में काम करेगी।' दीपके ने कहा, 'अगर हम राजनीतिक पार्टी बनाते, तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होता। आंदोलन इसलिए सफल हुआ, क्योंकि अलग-अलग विचारधाराओं और राजनीतिक दलों के लोग लोकतंत्र को कमजोर करने वाली चीजों के खिलाफ एक साथ आए। आज भारत को किसी नई राजनीतिक पार्टी की नहीं, बल्कि एक मजबूत जन आंदोलन की जरूरत है।' महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी की दो दिवसीय बैठक शुरू हुई। बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में दीपके ने बताया कि इसमें जंतर-मंतर आंदोलन की समीक्षा, ई20 पेट्रोल, शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।

दिल्ली एयरपोर्ट पर एक किलो सोने के साथ दो महिलाएं पकड़ीं

एजेंसी, नई दिल्ली। सीमा शुल्क विभाग ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तस्करी के एक मामले का भंडाफोड़ करते हुए दो महिला यात्रियों को पकड़ा है। उनके पास से लगभग एक किलोग्राम सोना भी बरामद किया गया। विभाग ने बुधवार को एक बयान में बताया कि इस्तांबुल से उड़ान संख्या 6ई-12 से नई दिल्ली पहुंचीं दो महिला यात्रियों को कस्टम्स ग्रीन चैनल पार करने के बाद रोका गया। एडवांस पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एपीआईएस) के आधार पर प्रोफाइलिंग के बाद ऐसा किया गया। उनके सामान की एक्स-रे जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से गुजरते समय दोनों यात्रियों के शरीर पर धातु होने का संकेत मिला। इसके बाद की गई विस्तृत व्यक्तिगत तलाशी में अधिकारियों ने लगभग एक किलोग्राम सोना बरामद किया।

सरकार परिसीमन बिल पर विशेष सत्र बुला सकती है, रिजिजू की राहुल से मुलाकात

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा में भी हुआ पास

एजेंसी, नई दिल्ली। सरकार परिसीमन पर चर्चा के लिए 16 से 18 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को संसद में राहुल, प्रियंका सहित अन्य कांग्रेस सांसदों से मुलाकात की।

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि किरेन रिजिजू ने परिसीमन के मुद्दे पर उनसे बात की। हम इस पर विचार करके उन्हें जवाब देंगे। कांग्रेस और विपक्ष का रुख पहले जैसा ही है। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध-प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकाला। उधर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है। 3 अगस्त को इसे लोकसभा से पास किया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी।

लोकसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल पास, 135 साल पुराने कानून बदलेंगे

लोकसभा ने बुधवार को बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 को मंजूरी दे दी। यह नया कानून 1891 के ब्रिटिश शासन के समय बने पुराने कानून की जगह लेगा। इस बिल का मकसद यह है कि बैंकों के डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, वर्चुअल और क्लाउड में रखे गए रिकॉर्ड भी अदालत में वैध सबूत (एविडेंस) माने जाएं। लोकसभा में शोर-शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल पेश किया। हंगामा नहीं थमने पर बिना चर्चा के ध्वनिमत (वॉइस वोट) से बिल पास कर दिया गया।

आरबीआई ने 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया

एजेंसी, मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7 फीसदी और खुदरा महंगाई दर का अनुमान घटाकर पांच फीसदी कर दिया है।

◆खुदरा महंगाई दर का अनुमान घटाकर 5.0 फीसदी किया

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समीति (एमपीसी) की तीन दिवसीय द्विमासिक समीक्षा बैठक के बाद जानकारी दी कि रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर अपरिवर्तित रखा गया है। उन्होंने कहा कि मौद्रिक समीक्षा में सर्वसम्मति से वित्त वर्ष 2026-27 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.7 फीसदी रहने का अनुमान है। इसमें पहली तिमाही में सात फीसदी, दूसरी तिमाही में 6.4 फीसदी, तीसरी तिमाही में 6.5 फीसदी और चौथी तिमाही में 6.8 फीसदी वृद्धि का अनुमान है। दोनों ओर घट-बढ़ के जोखिम संतुलित हैं। आरबीआई गवर्नर ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी उथल-पुथल का घरेलू आर्थिक गतिविधियों पर भी कुछ असर पड़ सकता है। संजय ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा महंगाई के अनुमान को 5 फीसदी रखा गया है। दूसरी तिमाही में इसके 4.7 फीसदी, तीसरी तिमाही में 5.9 फीसदी और चौथी तिमाही में 5.5 फीसदी रहने का अनुमान है। गवर्नर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2027-28 की पहली तिमाही में खुदरा महंगाई के दोनों ओर घट-बढ़ के साथ 5.3 फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मुख्य महंगाई 4.3 फीसदी रहने का अनुमान है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आरबीआई ने उम्मीद के मुताबिक प्रमुख नीतिगत दर रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर कायम रखा है।

'यौम-ए-इस्तेहसाल' की नौटंकी के बजाए पीओजेके में रक्तपात को रोके पाकिस्तान: विदेश मंत्रालय

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दिन 5 अगस्त को पाकिस्तान के 'यौम-ए-इस्तेहसाल' (शोषण दिवस) मनाने को नौटंकी बताया है। पड़ोसी देश को आईना दिखाते हुए, भारत ने कहा है कि उसे पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर में शासन की ओर से किए जा रहे रक्तपात को रोकना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 'यौम-ए-इस्तेहसाल' को दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार फैलाने का 'व्यर्थ प्रयास' बताया है। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं, रहे हैं और सदा रहेंगे। 5 अगस्त, 2019 को किया गया संवैधानिक परिवर्तन पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) में मौलिक अधिकारों के क्रूर दमन का साक्षी है। प्रवक्ता ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से क्षेत्र के लोगों को अभूतपूर्व सामाजिक-आर्थिक विकास, सुशासन व लोकतांत्रिक सशक्तिकरण प्राप्त हुआ है।

स्पेसएक्स का 4000 किलो वजनी रॉकेट चांद से टकराया

एजेंसी, नई दिल्ली। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक बेकाबू रॉकेट चांद की सतह से टकरा गया। 4 हजार किलो वजनी और करीब 5 मंजिला इमारत जितना बड़ा यह रॉकेट करीब 8,690 किमी/घंटा की रफ्तार से टकराया।

नासा ने कहा कि इस टक्कर से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। हालांकि, इस टक्कर की पुष्टि तस्वीरों के आने के बाद होगी। यह बेकाबू टुकड़ा स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा है। इसे जनवरी 2025 में फ्लोरिडा से अमेरिका व जापान के दो लूनर लैंडर को अंतरिक्ष में भेजने के लिए लॉन्च किया गया था। मिशन पूरा होने के बाद रॉकेट का यह हिस्सा अंतरिक्ष में तैरता रह गया। पिछले 18 महीनों के

◆नासा ने कहा- टक्कर से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं

दौरान पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसका रास्ता धीरे-धीरे बदल गया। खगोलविदों ने डेटा का अध्ययन करके पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह रॉकेट भटककर सीधे चांद की ओर जा रहा है और उससे टकराएगा। यह टक्कर चांद के 'आइंस्टीन क्रेटर' के पास हुई। यह क्षेत्र चांद के उस हिस्से में है, जहां दिन का उजाला रहता है और जो पृथ्वी से दिखाई देता है। हालांकि, वैज्ञानिकों के मुताबिक इसे आम टेलिस्कोप से देखना नामुमकिन था, क्योंकि टक्कर के वक्त बनी रोशनी बेहद हल्की थी।

पीएम की पोस्ट हटाने पर जुकरबर्ग ने माफी मांगी

कंपनी ने माना चाइल्ड पोर्न कंटेंट और डीप फेक रोकने में भी नाकाम रहे

एजेंसी, नई दिल्ली। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बुधवार को पीएम मोदी का फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में भारत सरकार से माफी मांगी है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दी है। कंपनी ने यह भी माना कि उसके प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटीरियल, डीपफेक और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी चूक हुई हैं।

मेटा की ग्लोबल टीम ने कंपनी के ग्लोबल अफेयर्स चीफ जोएल कैपलन के नेतृत्व में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आईटी सचिव एस. कृष्णन से मुलाकात की। यह बैठक पिछले महीने पीएम मोदी का फेसबुक पोस्ट हटने के बाद सरकार की ओर से भेजे गए समन के बाद हुई। दरअसल,

◆सरकार का मेटा को संदेश, केवल इंटरमीडियरी होने का दावा नहीं चलेगा

सरकार पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाने से भी नाराज थी। मोदी ने 23 जुलाई को यह वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने पेपर लीक को बड़ी समस्या बताया था। उन्होंने ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी बात कही थी। यह वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक से हटा दिया गया था। बाद में मेटा ने इसे फिर से फेसबुक पर डाल दिया। बैठक में मेटा ने स्वीकार किया कि कुछ खास तरह के कंटेंट को प्रमोट करने के लिए बड़ी रकम खर्च की गई। इस वजह से प्लेटफॉर्म पर अवैध कंटेंट भी प्रमोट हुआ। हालांकि, सूत्रों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस तरह के कंटेंट की बात की गई। सरकार ने मेटा से कहा कि वह आईटी अधिनियम के तहत खुद को सिर्फ एक इंटरमीडियरी नहीं कह सकती। मेटा यह तय करती है कि कौन-सा कंटेंट किस यूजर तक पहुंचेगा। इसलिए, कंपनी को आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा।

छह तेल कंपनियों ने ईरान जंग में 81 अरब डॉलर कमाए

एजेंसी, वॉशिंगटन। ईरान जंग शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं तो दुनियाभर में महंगाई भी बढ़ गई।

◆यह भारत के रक्षा बजट से भी ज्यादा; इस दौरान कच्चा तेल 23 फीसदी महंगा

इस दौरान अप्रैल से जून के बीच दुनिया की 6 सबसे बड़ी तेल कंपनियों ने रिकॉर्ड 81 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया। अल जजीरा की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। मुनाफे की यह रकम करीब 7.7 लाख करोड़ रुपए होती है, जो भारत के पूरे साल के रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है।

जंग शुरू होने तक कच्चा तेल 70 डॉलर प्रति बैरल था। यह अप्रैल से जून के बीच 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। यानी, तेल कंपनियों ने इस दौरान करीब 23% मुनाफा कमाया।

ओमान से समझौता हुआ, तो भी नहीं खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट

ईरान के सरकारी टीवी आईआरआईबी ने कहा कि ओमान के साथ जहाजों की आवाजाही पर समझौता होने के बाद भी होर्मुज स्ट्रेट तुरंत नहीं खोला जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान और ओमान के बीच चल रही बातचीत सिर्फ दोनों देशों के बीच है और इसका अमेरिका से कोई संबंध नहीं है। समझौता होने के बाद भी होर्मुज स्ट्रेट तभी खुलेगा, जब अमेरिका कथित उल्लंघन करना बंद करेगा।

हिमाचल में जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर के वेतन में 78 प्रतिशत की बढ़ोतरी

अब 60 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेगा वेतन

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) के मासिक वेतन में बड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) का मासिक वेतन 33,660 रुपए से बढ़ाकर 60 हजार रुपए कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह लगभग 78 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2022 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) का वेतन करीब 27 हजार रुपए से बढ़ाकर 33,660 रुपए किया गया था, जो लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि थी।

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा राज्य सरकार की सबसे प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान इन दोनों क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उनके अनुसार कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर के वेतन में की गई यह बढ़ोतरी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेगी तथा लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक तकनीक और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर रही है। इसके साथ ही डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी दूर करने के लिए भी विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इन प्रयासों से प्रदेश के लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

अब मौजूदा सरकार ने उनके वेतन में 33,660 रुपए से सीधे 60 हजार रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। प्रवक्ता का कहना है कि इस फैसले से विशेषज्ञ डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं देने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अन्य वर्गों के लिए भी आर्थिक लाभ बढ़ाए गए हैं।

पंजाब में निजी स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे मनमानी फीस

एजेंसी, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा फीस में मनमानी और अवैध बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026' को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, कुछ निजी स्कूल हर वर्ष अनुचित तरीके से फीस बढ़ा रहे थे, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था। इसी को रोकने के लिए वर्ष 2016 और 2019 के संबंधित अधिनियमों तथा नियमों में संशोधन का निर्णय लिया गया है। बैठक में 'पंजाब स्टेट आउटसोर्सड ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट विधेयक-2026', तीन नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटियों की स्थापना और अन्य नीतिगत प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।

युवाओं की बात सुनना सबसे ताकतवर हथियार : सुप्रीम कोर्ट

कहा- युवक पत्थरबाजी करें, तब भी उन्हें शांत करने की कोशिश करनी चाहिए

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हिंसा को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि युवाओं की बात सुनना सबसे ताकतवर हथियार है।

कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को संयम रखना चाहिए, अगर कुछ भटके हुए युवक पत्थरबाजी भी करें, तब भी उन्हें समझाने और शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार को भी आक्रामक रवैया अपनाने से बचना चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की बेंच ने यह टिप्पणी रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर मनीष कुमार सोलंकी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में 20 जुलाई के 'संसद चलो' मार्च के आयोजकों यानी सीजेपी प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कोर्ट ने इस

◆प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को संयम रखना चाहिए

याचिका को इसी मामले से जुड़ी दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर कुछ भटके हुए युवक पत्थरबाजी करते हैं, तब भी उन्हें समझाने और सलाह देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन्हें काउंसलिंग मिलनी चाहिए। अगर सरकार आक्रामक रवैया अपनाएगी, तो हालात और बिगड़ सकते हैं और हिंसा बढ़ सकती है। इससे बचना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि सबसे जरूरी बात शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बढ़ावा देना है, अगर कोई घटना हो भी जाती है, तो पुलिस को बहुत संयम से काम लेना चाहिए, ताकि हालात नियंत्रण से बाहर न जाएं। जहां भी ऐसी घटनाएं हों, वहां बहुत सावधानी से स्थिति संभालनी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि बहुत सोच-समझकर कदम उठाने होंगे, ताकि युवा हिंसा की राह पर न जाएं। सबसे अच्छा तरीका है उन्हें समझाना और शांत करना। उनकी बात सुनिए और समझिए कि वे आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं। अंत में सीजेआई ने कहा कि ऐसे मामलों से कैसे निपटना है, यह कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर छोड़ देना चाहिए। उन्हें ऐसी परिस्थितियों से निपटने का अनुभव हमसे और आपसे ज्यादा है।

दलित, युवा व विकास विरोधी सपा का सदन में आचरण शर्मनाक : सीएम योगी

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के मानसून सत्र में बुधवार को भी हंगामा जारी रहा। सदन में समाजवादी पार्टी (सपा) के हंगामे और विरोध पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा लोकतंत्र, दलित और समाज विरोधी है। इसका विकास से कोई मतलब नहीं है, इसलिए अनुपूरक बजट की चर्चा में विकास के मुद्दे पर बात नहीं कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की प्रतिबद्धता विकास की है और रहेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी को विकास, युवा, महिला और लोकतंत्र विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 59 हजार करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश

◆कहा- सपा लोकतंत्र, दलित व समाज विरोधी, इसका विकास से कोई मतलब नहीं

किया, लेकिन इसमें भी सपा ने तरह-तरह की अड़चनें लगाईं, जबकि इस अनुपूरक बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, रसोइयों, कोटेदारों, चौकीदारों व आशा कार्यकर्त्रियों के मानदेय वृद्धि व एक्सप्रेसवे निर्माण से जुड़े प्रस्ताव थे। इससे समाज के सभी लोगों का विकास होना है। इतना ही नहीं इस अनुपूरक बजट में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर, संत रविदास, समाज सुधारक ज्योतिबा फुले, लोकमाता अहिल्याबाई आदि की प्रतिमाओं की स्थापना, रखरखाव व बाउंड्रीवाल निर्माण आदि के लिए भी अनुपूरक बजट में व्यवस्था की गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन में अपना दलित विरोधी चेहरा दिखा दिया कि उसमें इन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के हजारों शिक्षामित्रों के मानदेय में भी बाधाएं खड़ी की थी, लेकिन हमारी सरकार ने मानदेय बढ़ाकर 18 हजार रुपए कर दिया है और अनुदेशकों का भी मानदेय बढ़ाया। इसी प्रकार अनुपूरक बजट में प्रदेश के विकास के साथ ही विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों, कार्यों को लेकर योजनाओं व प्रस्तावों को शामिल किया गया है, लेकिन सपा तो विकास और लोकतंत्र विरोधी है।

सुधार 'दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026' के मसौदे पर मंत्रिमंडल ने किया विचार

नए कानून से निवेश, उद्योग व रोजगार को मिलेगी रफ्तार : सीएम रेखा

एजेंसी, नई दिल्ली। 'दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026' के मसौदे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में विचार किया गया।

इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य दिल्ली को देश में उद्यम स्थापित करने और संचालित करने के लिए सबसे आसान स्थान बनाने की दिशा में व्यापक सुधार लागू करना है। इससे दिल्ली में नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों का विस्तार होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल एवं दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन बाद इस विधेयक को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी

◆सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेंगी सभी कारोबारी मंजूरियां, निवेश को मिलेगा बढ़ावा

कि यह प्रस्तावित कानून भारत सरकार के अनुपालन में कमी और विनियमन-मुक्त पहल (चरण-II) के तहत तैयार किया गया है। यह जन विश्वास विधेयक, 2023 की भावना के अनुरूप है। दिल्ली सरकार भी अब उद्योगों व निवेशकों के लिए एक आधुनिक, पारदर्शी और निवेश-अनुकूल व्यवस्था विकसित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून के अंतर्गत कारोबार से जुड़ी विभिन्न मंजूरियां, पंजीकरण, लाइसेंस, एनओसी और अन्य अनुमतियों के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त होगी।

इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से एक ही ऑनलाइन पोर्टल पर अधिकांश व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। भवन निर्माण स्वीकृति, फैक्टरी लाइसेंस, फायर क्लीयरेंस, पानी, सीवर और बिजली कनेक्शन, रेरा पंजीकरण, सहकारी समितियों के पंजीकरण सहित अनेक सेवाएं इसी पोर्टल के माध्यम से तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी।

डीम्ड अप्रूवल से तय समय में मिलेगी मंजूरी

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पूरी व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएसआईआईडीसी) को सौंपी जाएगी। यही संस्था आवेदन प्राप्त होने से लेकर अंतिम स्वीकृति मिलने तक पूरी प्रक्रिया के लिए एकमात्र जवाबदेह नोडल एजेंसी होगी तथा सभी संबंधित विभाग और नागरिक एजेंसियां इसके माध्यम से समन्वय स्थापित करेंगी। इस कानून की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक 'डीम्ड अप्रूवल' की व्यवस्था होगी। यदि कोई सक्षम प्राधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी आवेदन पर निर्णय नहीं लेता है तो संबंधित स्वीकृति, पंजीकरण या एनओसी स्वतः स्वीकृत मानी जाएगी और आवेदक उसे सीधे ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकेगा। इससे फाइलों के अनावश्यक लंबित रहने और निर्णय में होने वाली देरी समाप्त होगी।

न्यूज ब्रीफ

6.2 ग्राम चिट्टे के साथ जम्मू-कश्मीर का युवक काबू

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। पुलिस थाना झंडुता की टीम ने गश्त के दौरान एक युवक को 6.2 ग्राम चिट्टे (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गुरदीप सिंह पुत्र मशूर सिंह, निवासी चिड्डी सिंहपुरा, डाकघर अचावल, तहसील मटल, जिला अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार टीम मंगलवार को क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान बैहनाजड्डा के पास लिंक रोड गेहड़वीं में एक संदिग्ध युवक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें उसके कब्जे से चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी नशा कहां से लाया था और इसकी सप्लाई किसे की जानी थी।

एसएमसी ने नए प्रधानाचार्य का किया स्वागत

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (सीबीएसई) मंडी की स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) ने नवनियुक्त प्रधानाचार्य अनिल कुमार कटोच का स्वागत किया। बैठक में विद्यालय के विकास और विद्यार्थियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। एसएमसी अध्यक्ष लेखराज ने बताया कि 10 अगस्त को आयोजित होने वाली बैठक में सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने, स्वच्छता, नालियों के रखरखाव, पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता, बास्केटबॉल कोर्ट के आधुनिकीकरण और शिकायत-सुझाव पेटी स्थापित करने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ही सीबीएसई मानकों के अनुरूप योग्य शिक्षकों की नियुक्ति पूरी की जाए, ताकि स्कूल खुलने पर पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने कहा कि सरकारी सीबीएसई विद्यालयों में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या अभिभावकों के विश्वास को दर्शाती है। इस अवसर पर एसएमसी सदस्य बंसीलाल, संतोष कुमार, अजय रंगड़ा और मोनू कुमार उपस्थित रहे।

शतरंज संघ की प्रियंका शर्मा बनीं अध्यक्ष

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर शतरंज संघ की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक माहौल में संपन्न हुई। सदस्यों ने प्रियंका शर्मा को अध्यक्ष, जबकि जसबीर सिंह को महासचिव चुना। नई कार्यकारिणी में दिनेश कुमार को उपाध्यक्ष, सुखदेव को कोषाध्यक्ष और कुलदीप सिंह को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर राजकुमार ने की। उन्होंने चुनाव को निष्पक्ष और अनुशासित बताया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रियंका शर्मा ने सभी सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि संघ का उद्देश्य जिले में शतरंज खेल को बढ़ावा देना और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना रहेगा। उन्होंने स्कूल-कॉलेज स्तर पर प्रतियोगिताएं, प्रशिक्षण शिविर और ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने की दिशा में कार्य करने की बात कही। नई कार्यकारिणी से जिले में शतरंज गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

मोबाइल नंबर अपडेट कराने की अपील

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के बिजली उप-मंडल नंबर-1 नाहन ने शहर के सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपने बिजली कनेक्शन के रिकॉर्ड में वर्तमान और सक्रिय मोबाइल नंबर अपडेट कराने की अपील की है। सहायक अभियंता संतोष कुमार ने कहा कि मोबाइल नंबर अपडेट होने से उपभोक्ताओं को बिजली बिल, बिल जमा करने की अंतिम तिथि, बिजली कटौती, रखरखाव कार्य और विभाग की अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर एसएमएस के माध्यम से मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि सही मोबाइल नंबर दर्ज होने से उपभोक्ता तक विभाग की सभी जरूरी जानकारियां समय पर पहुंचेंगी। इससे बिजली सेवा से जुड़ी सूचनाएं मिलने में आसानी होगी और उपभोक्ता समय पर आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे। सहायक अभियंता ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है या बदल चुका है, वे उसे जल्द अपडेट करवा लें। इसके लिए उपभोक्ता किसी भी कार्य दिवस पर रानीताल, नाहन स्थित विद्युत उप-मंडल नंबर-1 के कार्यालय में जाकर अपनी संपर्क जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। बिजली बोर्ड ने सभी उपभोक्ताओं से समय रहते मोबाइल नंबर अपडेट कराने की अपील की है, जिससे विभाग और उपभोक्ताओं के बीच सूचना का आदान-प्रदान सुचारू रूप से हो सके।

22 को विशेष, 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 22 अगस्त, 2026 को जिले के सभी न्यायालयों में विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और चेक बाउंस से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 12 सितंबर, 2026 को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं और झंडुता न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों के साथ बैंक विवाद, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल, वैवाहिक विवाद सहित अन्य मामलों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों को लोक अदालत में लगवाकर आपसी सहमति से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर के नंबर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है।

एनएच किनारे लगेंगे प्री-फेब्रिकेटेड सेल आउट हट

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि जिले में स्वयं सहायता समूहों को स्थायी बाजार उपलब्ध करवाने और स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए कलस्टर स्तर पर प्री-फेब्रिकेटेड प्रोडक्ट सेल आउट हट स्थापित किए जाएंगे। ये हट राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे प्रमुख स्थानों पर बनाए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को योजना का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इन हट में सेब, जैम, जूस, शहद, राजमा, देसी घी, अचार, मशरूम उत्पाद, ऊनी वस्त्र और हस्तशिल्प सहित स्थानीय उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। प्रत्येक हट के साथ फूड वैन भी स्थापित की जाएगी, जिसमें पारंपरिक व्यंजन उपलब्ध होंगे। उपायुक्त ने कहा कि यह पहल स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ाने, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने और 'ब्रांड शिमला' को पहचान दिलाने में सहायक होगी।

प्रदेश के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री सुक्खू

कहा- वाइल्ड फ्लावर हॉल से कड़छम-वांगतू तक, प्रदेश हित में लिए गए अहम फैसले

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश हितों से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों में राज्य सरकार प्रभावी पैरवी कर हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि बीबीएमबी के वित्तीय बकाया, बिजली हिस्सेदारी, शानन जलविद्युत परियोजना सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार मजबूती से अपना पक्ष रख रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से हिमाचल प्रदेश के करीब 4,200 करोड़ रुपए के वित्तीय बकाया और 13,066 मिलियन यूनिट बिजली के अधिकार को लेकर राज्य सरकार विभिन्न मंचों पर आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 15 वर्ष पहले सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हिमाचल के पक्ष में आने के बावजूद राज्य को अभी तक पूरा अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत चंडीगढ़ की भूमि और परिसंपत्तियों में हिमाचल के 7.19 प्रतिशत हिस्से की मांग भी प्रमुखता से उठाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शानन जलविद्युत परियोजना का मामला भी प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी परियोजना हिमाचल को वापस नहीं सौंपी गई है। इस मामले को सरकार विभिन्न स्तरों पर उठा रही है और यह वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 से कानूनी विवाद में फंसे वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में प्रदेश सरकार ने मजबूत पैरवी कर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद यह संपत्ति राज्य सरकार के नियंत्रण में आ गई है। इसके लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपये का भुगतान किया और अब इस संपत्ति से प्रदेश को प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के संसाधनों और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा व राज्य तथा प्रदेशवासियों का हित उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

किशाऊ परियोजना में प्रदेश के हित सुरक्षित

मुख्यमंत्री ने बताया कि कड़छम-वांगतू जलविद्युत परियोजना की रॉयल्टी के मामले में भी प्रदेश को बड़ी सफलता मिली है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इस परियोजना में हिमाचल की मुफ्त बिजली हिस्सेदारी 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है, जिससे राज्य को प्रतिवर्ष करीब 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। उन्होंने कहा कि किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में भी प्रदेश के हितों को प्राथमिकता दी गई है। करीब 15 हजार करोड़ रुपए की इस परियोजना में हिमाचल के हिस्से को लेकर सरकार ने प्रभावी प्रयास किए। केंद्र सरकार ने दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा द्वारा हिमाचल के हिस्से की लगभग 2,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वहन करने पर सैद्धांतिक सहमति दी है।

रेल संपर्क मजबूत होने से पर्यटन, व्यापार रोजगार को मिलेगा बढ़ावा : अनुराग ठाकुर

◆ रेल नेटवर्क का विस्तार तेज अंब इंदौरा बना प्रमुख रेल हब

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में रेलवे अधोसंरचना के विस्तार और यात्री सुविधाओं के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दे रही है।

रेल मंत्री ने बताया कि 70 किलोमीटर लंबा नंगल डैम–ऊना–दौलतपुर चौक–कर्तोली ब्रॉडगेज रेलखंड पूरी तरह चालू हो चुका है, जबकि 52 किलोमीटर लंबे करतोली–तलवाड़ा–मुकेरियां ब्रॉडगेज रेलखंड का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। परियोजना के तहत पुलों, रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नंगल डैम–ऊना–दौलतपुर चौक रेल लाइन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है। इस मार्ग पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2023–24 में 25.77 लाख यात्रियों ने सफर किया, जो 2024–25 में बढ़कर 30.56 लाख और 2025–26 में 31.87 लाख पहुंच गई। रेल मंत्री ने बताया कि अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन हिमाचल का प्रमुख रेल हब बन चुका है, जहां से 20 रेल सेवाएं संचालित हो रही हैं। इससे प्रदेश का संपर्क देश के 13 राज्यों से जुड़ा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंब इंदौरा स्टेशन का आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया गया है। अनुराग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल में रेल संपर्क मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे तथा प्रदेश के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।

कैंसर अस्पताल में लगाए गार्डन अंब्रेला, मरीजों तीमारदारों को मिलेगी धूप–बारिश से राहत

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। आईजीएमसी स्थित कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को अब प्रतीक्षा के दौरान धूप और बारिश से राहत मिलेगी। सामाजिक सेवा के तहत इनर व्हील क्लब शिमला ने अस्पताल परिसर में दो हैवी–ड्यूटी आउटडोर गार्डन अंब्रेला स्थापित किए हैं।

इन अंब्रेला का उद्देश्य अस्पताल आने वाले मरीजों, उनके परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रतीक्षा के समय सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध करवाना है। अस्पताल में इलाज और जांच के लिए आने वाले कई मरीजों व उनके परिजनों को अक्सर लंबे समय तक बाहर इंतजार करना पड़ता है। इस सुविधा से उन्हें मौसम की परेशानियों से राहत मिलेगी। इनर व्हील क्लब शिमला की अध्यक्ष डॉ. कुशा पंडित चावला ने कहा कि मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है। उन्होंने कहा कि कई बार छोटी–छोटी सुविधाएं भी लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होती हैं। क्लब भविष्य में भी समाजहित से जुड़े सेवा कार्यों को जारी रखेगा। यह पहल कैंसर अस्पताल के विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष गुप्ता के मार्गदर्शन में पूरी हुई। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष डॉ. कुशा पंडित चावला और सदस्य रवीना जिंदानी उपस्थित रहीं।

मेडिएशन फॉर द नेशन 3.0 अभियान से लंबित मामलों के निपटारे का अवसर

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि अदालतों में लंबित मामलों को मध्यस्थता, सुलह व आपसी सहमति से निपटाने के लिए 'मेडिएशन फॉर द नेशन 3.0' अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक चलने वाले न्यायिक मामलों से दोनों पक्षों का समय और धन खर्च होता है। ऐसे में मध्यस्थता विवादों के समाधान का सरल और प्रभावी माध्यम है। अभियान के तहत इच्छुक पक्ष संबंधित अदालत में आवेदन कर अपने मामलों का निपटारा करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। उन्होंने बताया कि वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, बीमा, भूमि विवाद और अन्य समझौता योग्य मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।

प्रभावित पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए प्रति योजना दो लाख किए जाएंगे जारी : डीसी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला में आपदा से प्रभावित पेयजल योजनाओं के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्यों के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से प्रति योजना दो लाख रुपए की राशि जारी की जाएगी।

इसके लिए जल शक्ति विभाग के अधिकारी क्षतिग्रस्त योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक दस्तावेजों सहित उपायुक्त कार्यालय को प्रेषित करें। डीसी जल जीवन मिशन के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय जल एवं स्वच्छता अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं पेयजल योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत किया जाएगा, जिनकी क्षति संबंधी रिपोर्ट राजस्व विभाग में दर्ज होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में संबंधित पटवारी के पास तत्काल रिपोर्ट दर्ज करवाना सुनिश्चित करें तथा सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। उन्होंने जल शक्ति विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त योजनाओं के मरम्मत कार्यों के प्रस्ताव जल्द उपायुक्त कार्यालय को भेजे जाएं। प्रस्ताव प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर बजट जारी कर दिया जाएगा, बशर्ते सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हों। बैठक में बताया गया कि जिले में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत 264 योजनाओं में से 203 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वहीं, हर घर जल गांव योजना के अंतर्गत जिले के 2,536 गांवों में से 1,699 गांवों को प्रमाण–पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि 837 गांवों की प्रक्रिया लंबित है। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि जिले में जल सेवा आकलन के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। जिले के कुल 2,536 गांवों में से 2,422 गांवों में जल सेवा आकलन का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे जिले की प्रगति 95.50 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

एबीवीपी ने छात्र हितों को लेकर धर्मशाला कॉलेज में किया प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने छात्र हितों और महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में धरना–प्रदर्शन किया। सुबह 11:30 बजे आयोजित इस प्रदर्शन में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र–छात्राओं ने भाग लिया।

धरने को संबोधित करते हुए एबीवीपी पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा फीस में की गई 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि को छात्र विरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि बढ़ती फीस से विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और इसका सीधा प्रभाव गरीब एवं मध्यम वर्ग के छात्रों पर पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्र संघ चुनावों को जल्द बहाल करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। एबीवीपी नेताओं ने कहा कि छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों की लोकतांत्रिक भागीदारी का माध्यम हैं और इन्हें लंबे समय तक बंद रखना उचित नहीं है। इकाई अध्यक्ष केशव मसंद ने कहा कि प्रदेश सरकार छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ाई जा रही फीस विद्यार्थियों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने सरकार से छात्र हित में शीघ्र निर्णय लेने की मांग की। एबीवीपी ने राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की मांग भी उठाई। संगठन ने कॉलेज परिसर में बेहतर शैक्षणिक संसाधन, आवश्यक सुविधाएं और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और तेज किया जाएगा। संगठन ने कहा कि फीस वृद्धि का फैसला वापस नहीं लिया गया तो भविष्य में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।

संसद में 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत लागू हो : शांता कुमार

◆ कहा- देशभक्तों के त्याग से प्राप्त लोकतंत्र आज कमजोर होता दिखाई दे रहा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने संसद में बढ़ते हंगामे और घटती सार्थक चर्चा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संसद में सार्थक चर्चा कम और हंगामा अधिक देखने को मिलता है। उन्होंने मांग की कि संसद में 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए।

शांता कुमार ने बुधवार को एक बयान में कहा कि कई बार संसद का पूरा सत्र बिना किसी चर्चा के समाप्त हो जाता है, जबकि अनेक महत्वपूर्ण विधेयक भी बिना पर्याप्त बहस के पारित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि देशभक्तों के त्याग से प्राप्त लोकतंत्र आज कमजोर होता दिखाई दे रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद के संचालन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जब संसद में कामकाज ठप रहता है और केवल नारेबाजी, शोर–शराबा एवं हंगामा होता है, तब भी सांसदों को वेतन और भत्ते मिलते रहते हैं। उन्होंने मांग की कि जिन सांसदों के कारण सदन की कार्यवाही बाधित होती है और कामकाज नहीं हो पाता, उन्हें उस अवधि का वेतन और भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए। शांता कुमार ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद केवल दो अवसरों पर पूरी तरह शांत दिखाई देती है—पहला, किसी बड़े नेता के निधन पर शोक प्रस्ताव के दौरान और दूसरा, जब सांसदों के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि से संबंधित विधेयक सदन में आता है। उन्होंने कहा कि इन दो अवसरों को छोड़कर संसद कई बार 'शोर सभा' बनकर रह जाती है।

पानी का टैंकर पलटने से एक की मौत, दो घायल

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। पुलिस थाना तलाई के अंतर्गत सरियाली खड्डु पुल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब पानी से भरा ट्रैक्टर–टैंकर अनियंत्रित होकर पुल के नीचे खड्डु में जा गिरा। जानकारी के अनुसार हादसा दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ। सूचना मिलते ही तलाई थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। ट्रैक्टर में सवार तीनों युवकों को बाहर निकालकर उपचार के लिए बड़सर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने रणजीत सिंह (निवासी गांव वलू डा. सठवीं, तहसील डटवाल, जिला हमीरपुर) को मृत घोषित कर दिया। जबकि अन्य दो घायलों का उपचार जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना तलाई पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

नादौन में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू, 11 जिलों के 190 खिलाड़ी ले रहे भाग

भारतेन्दु संवाददाता, नादौन। हिमाचल प्रदेश बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ नादौन की शिवालिक बैडमिंटन अकादमी में हुआ।

प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने किया। इस अवसर पर एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा, नशा निवारण बोर्ड के संयोजक नरेश ठाकुर, हमीरपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुनील सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में प्रदेश के 11 जिलों से करीब 190 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में आयोजन समिति के वाइस चेयरमैन विजय काचरू, हिमाचल प्रदेश बैडमिंटन संघ के सचिव रमेश ठाकुर, इवेंट सेक्रेटरी राजिंदर शर्मा, चीफ सेलेक्टर चंद्रशेखर तुर्की, संजय कालिया, पंकज शर्मा, ज्ञान ठाकुर और मैच रेफरी विश्वनाथ मलकोटिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक खेल सुविधाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है।

उन्होंने नादौन में निर्माणाधीन अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम को खिलाड़ियों के लिए बड़ी सुविधा बताते हुए कहा कि इसके तैयार होने के बाद क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधा मिलेगी। इवेंट सेक्रेटरी राजिंदर शर्मा ने बताया कि 5 और 6 अगस्त को जूनियर वर्ग के लड़के और लड़कियों के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे, जबकि 7 और 8 अगस्त को पुरुष और महिला वर्ग के मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।

चेतावनी प्रदेश में 11 तक भारी बारिश का अलर्ट, 153 सड़कें बंद, 191 बिजली ट्रांसफार्मर ठप

भूस्खलन से मणिमहेश जा रहे श्रद्धालु की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसून का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राज्य में 11 अगस्त तक अलग–अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रदेशभर में करीब 153 सड़कें बंद हो गई हैं।

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सिरमौर और ऊना जिलों में सबसे अधिक बारिश हुई। सिरमौर के जट्टन बैराज में 135.4 मिलीमीटर, ऊना के रायपुर मैदान में 124.2 मिलीमीटर, बिलासपुर के नैना देवी में 110.6 मिलीमीटर, कांगड़ा के देहरा गोपीपुर में 97.2 मिलीमीटर और हमीरपुर के नादौन में 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के कई अन्य क्षेत्रों में भी भारी वर्षा हुई है। विभाग ने बुधवार और वीरवार को प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। 7 और 8 अगस्त को भी पूरे प्रदेश में व्यापक बारिश होने का अनुमान है, जबकि 9 से 11 अगस्त तक कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

प्रशासन ने लोगों को नदी–नालों के पास जाने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में आवाजाही से बचने की सलाह दी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार बारिश और भूस्खलन के कारण मंडी जिले में सबसे अधिक 51 सड़कें बंद हैं। सिरमौर में 39, कुल्लू में 36 और शिमला में 15 सड़कें प्रभावित हुई हैं।

इसके अलावा प्रदेश में 191 बिजली ट्रांसफार्मर और 58 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब क्षेत्र में 143 बिजली ट्रांसफार्मर बंद हैं, जिन्हें बहाल करने का कार्य जारी है। मौसम की स्थिति को देखते हुए पांवटा साहिब उपमंडल के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को दो दिन के लिए बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।

उधर, चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। मेहला के पास तड़के करीब तीन बजे पहाड़ी से गिरे बड़े पत्थर की चपेट में श्रद्धालुओं की थार गाड़ी आ गई। पत्थर वाहन के सनरूफ पर गिरने से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और पंजाब निवासी एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

किन्नौर जिले में भी लगातार बारिश से बस्पा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड ने बुधवार सुबह कुप्पा बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की सूचना दी। इसके बाद डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में जलप्रवाह बढ़ने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों से बस्पा नदी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है।

आईजीएमसी शिमला को मिला स्कोच पुरस्कार 'हर दिन सेहत' अभियान की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (आईजीएमसी) शिमला को जनस्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं नवाचारपूर्ण कार्यों के लिए प्रतिष्ठित स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान महाविद्यालय द्वारा संचालित 'हर दिन सेहत' जन–जागरूकता अभियान के तहत वर्षभर 365 दिनों तक चलाई गई स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों के लिए प्रदान किया गया।

आईजीएमसी शिमला की टीम ने यह सम्मान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्राप्त किया। अभियान के माध्यम से प्रदेशभर में पोषण, स्वस्थ जीवनशैली, नियमित व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, गैर–संचारी रोगों की रोकथाम और टीकाकरण जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर आमजन के लिए तैयार की गई 'स्वस्थ जीवन की सरल गाइड' पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। पुस्तिका में संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों से बचाव सहित चिट्टा व अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव, बचाव और उपचार संबंधी जानकारी सरल भाषा में दी गई है। आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राहुल राव ने कहा कि 'हर दिन सेहत' केवल जागरूकता कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य को जन–जन तक पहुंचाने का सतत अभियान है। उन्होंने इस सम्मान को पूरी टीम की मेहनत और प्रतिबद्धता का परिणाम बताया। सामुदायिक चिकित्सा विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. अमित सचदेवा ने कहा कि पुस्तिका का उद्देश्य वैज्ञानिक स्वास्थ्य जानकारी को सरल रूप में प्रत्येक परिवार तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि रोगों की रोकथाम के लिए जनजागरूकता सबसे प्रभावी माध्यम है और यह अभियान स्वस्थ व नशामुक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

न्यूज ब्रीफ

बीएलओ करेंगे मतदाता सूची की गड़बड़ियां मौके पर दूर

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य सामान्य त्रुटियों को सुधारने के लिए अब लोगों को निर्वाचन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार बूथ स्तर अधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन कर मौके पर ही छोटी गड़बड़ियों का समाधान करेंगे। इससे मतदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी और प्रक्रिया भी आसान होगी। जिन मामलों में मैपिंग या अन्य जटिल समस्याएं होंगी, उनका निस्तारण निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारियों के स्तर पर किया जाएगा। निर्वाचन विभाग ने पारदर्शिता और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश भी दिए हैं।

'सेवा ही सबसे बड़ी पूजा' का संदेश दे रहे बदरीनाथ धाम के पुलिस जवान

भारतेंदु संवाददाता, बदरीनाथ। श्री बदरीनाथ धाम में दर्शन के लिए प्रतिदिन पहुंच रहे बुजुर्ग, दिव्यांग और असहाय श्रद्धालुओं के लिए चमोली पुलिस सेवा और संवेदना की मिसाल पेश कर रही है। पुलिस जवान ड्यूटी के साथ-साथ स्वयं आगे बढ़कर व्हीलचेयर के माध्यम से ऐसे श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचा रहे हैं और उन्हें सुरक्षित व सुगम दर्शन करा रहे हैं। श्रद्धालुओं का हौसला बढ़ाने के साथ पुलिसकर्मी उनकी हरसंभव सहायता भी कर रहे हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं के चेहरों पर दिखने वाली संतुष्टि और खुशी पुलिस जवानों के लिए सबसे बड़ा सम्मान बन रही है। चमोली पुलिस की यह पहल साबित कर रही है कि वर्दी केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं, बल्कि मानवता और सेवा के सर्वोच्च मूल्यों को निभाने का भी सशक्त माध्यम है।

विश्वविद्यालय कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगों पर शासन समिति ने की समीक्षा

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के पांच राजकीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन द्वारा गठित समिति ने अपनी पहली बैठक में विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की। समिति ने सभी विश्वविद्यालयों से रिक्त पदों का विवरण मांगा है और कर्मचारियों के लिए कॉमन सेवा नियमावली तैयार करने का निर्णय लिया है। बैठक में प्रयोगशाला सहायक और तकनीकी संवर्ग की वेतन विसंगतियों, पदोन्नति प्रक्रिया, एसीपी, समयबद्ध प्रशिक्षण तथा समान सेवा संरचना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया। विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की 11 सूत्री मांगों के निस्तारण के लिए समिति आवश्यक सुझाव तैयार करेगी। बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलसचिव और महासंघ के पदाधिकारी शामिल हुए।

सहकारिता में हरियाणा व उत्तराखंड मिलकर करेंगे काम : डॉ. धन सिंह रावत

कहा- हरियाणा के सहकारी बैंकिंग नवाचारों से सीखेगा उत्तराखंड

- किसान हितैषी योजनाओं में बढ़ेगा हरियाणा उत्तराखंड का सहयोग
- डॉ. धन सिंह रावत ने हरियाणा सहकारी बैंक का किया दौरा, साझा किए किसान हितैषी अनुभव

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने एक दिवसीय चंडीगढ़ दौरे के दौरान हरियाणा स्टेट को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड के मुख्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बैंक की कार्यप्रणाली, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं तथा किसानों, महिलाओं और युवाओं के आर्थिक सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी ली। अधिकारियों के साथ बैठक में सहकारी बैंकिंग के सफल मॉडलों और दोनों राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।

डॉ. रावत ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में हरियाणा ने विशेष रूप से बैंकिंग नवाचार, पारदर्शी कार्यप्रणाली और जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड इन नवाचारों का अध्ययन कर उन्हें राज्य में लागू करने का प्रयास करेगा। दोनों राज्यों के बीच अनुभवों और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देगा और किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।

बैठक के दौरान डॉ. रावत ने उत्तराखंड सरकार की दीनदयाल उपाध्याय अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण वितरण योजना की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इसके तहत किसानों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष भारत भूषण जुयाल को बधाई दी।

बैंक अध्यक्ष भारत भूषण जुयाल ने उत्तराखंड में सहकारिता क्षेत्र में हुए नवाचारों, शून्य प्रतिशत ब्याज ऋण योजना, डिजिटल पहलों और सहकारी संस्थाओं के आधुनिकीकरण की सराहना की। कार्य, में बैंक के प्रबंध निदेशक डॉ. प्रफुल्ल रंजन, महाप्रबंधक उर्वशी गुप्ता, उप महाप्रबंधक सुधा शर्मा, प्रबंधक जसपाल पंवार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

ग्लासगो से कांस्य पदक लेकर लौटी उन्नति शर्मा

कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य जीतने वाली 'उन्नति शर्मा' का देहरादून में भव्य स्वागत

देहरादून

कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक विजेता उन्नति

- उन्नति शर्मा बनीं उत्तराखंड का गौरव

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों की जूडो प्रतियोगिता में 63 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश और उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाली उन्नति शर्मा का बुधवार को देहरादून पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। शहर में खेल प्रेमियों, विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों, सामाजिक संगठनों तथा विद्यार्थियों ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इसके बाद डीएवी पब्लिक स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह में उन्नति को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर उनके कोच पुनेश सिंह ने बताया कि उन्नति ने महज 11 वर्ष की उम्र में जूडो का प्रशिक्षण शुरू किया था और अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन तथा निरंतर अभ्यास के बल पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतने के साथ एशियाई स्तर पर भी रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए हैं।

कॉमनवेल्थ खेलों में कांस्य पदक जीतना उनकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। उन्नति की इस सफलता से उत्तराखंड के खिलाड़ियों और युवाओं में नया उत्साह पैदा हुआ है। खेल प्रेमियों ने विश्वास जताया कि वह भविष्य में भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए और अधिक पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाएंगी।

नैनीताल : 8 से 16 अगस्त तक जिलेभर में चलेगा विशेष स्वच्छता अभियान

भारतेंदु संवाददाता, नैनीताल

जिले को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन 8 से 16 अगस्त 2026 तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाएगा। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला मार्ग, ग्राम पंचायतों, शहरी क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक सफाई अभियान संचालित किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक और अन्य कचरे का चिन्हीकरण कर उसका सुरक्षित निस्तारण किया जाएगा। नगर निकायों, जिला पंचायत, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास तथा वन विभाग की टीमें अभियान में सर्, य भूमिका निभाएंगी। रामनगर, मुक्तेश्वर, धारी, रामगढ़ और अन्य पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान की निगरानी जियोटैग फोटोग्राफ के माध्यम से होगी।

केसरिया रंग में रंगा हरिद्वार, गूंजे हर-हर महादेव के जयघोष

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार

सावन माह की कांवड़ यात्रा ने धर्मनगरी हरिद्वार में पूरी रफ्तार पकड़ ली है। पूरा शहर इन दिनों केसरिया आस्था के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। हरकी पैड़ी, ब्रह्मकुंड, विभिन्न गंगा घाटों, कांवड़ पटरी, मेला क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे स्टेशन और शहर की प्रमुख सड़कों पर हर ओर %बोल बम% और %हर-हर महादेव% के जयघोष गूंज रहे हैं। लाखों शिवभक्त गंगा में स्नान कर पवित्र गंगाजल भरकर अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था से पूरा वातावरण शिवमय हो गया है।

जिला प्रशासन के अनुसार 30 जुलाई से अब तक एक करोड़ 43 लाख 25 हजार से अधिक कांवड़िये हरिद्वार से गंगाजल लेकर प्रस्थान कर चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि पंचक की अवधि समाप्त होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और 5 से 11 अगस्त के बीच यात्रा अपने चरम पर रहेगी। विशेष रूप से 8 अगस्त से 11 अगस्त की सुबह तक सबसे अधिक भीड़ रहने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन तथा भीड़ नियंत्रण के विशेष इंतजाम किए हैं। कई मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है और डायवर्जन योजना लागू की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

हरिद्वार, ज्वालापुर और बहादराबाद सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित कांवड़ शिविरों में दिन-रात चहल-पहल बनी हुई है। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और स्वयंसेवी संस्थाएं कांवड़ियों के लिए भोजन, पेयजल, चिकित्सा और विश्राम जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं।

लाखों शिवभक्तों से गुलजार हुआ हरिद्वार

हाईवे और कांवड़ मार्गों पर आकर्षक और भव्य कांवड़ झांकियां श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों का विशेष ध्यान आकर्षित कर रही हैं। इनमें केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ, शिव परिवार, पवनपुत्र हनुमान, शिवभक्त रावण और श्रीराम मंदिर सहित अनेक धार्मिक झांकियां शामिल हैं। रंग-बिरंगी रोशनी, कलात्मक सजावट और धार्मिक संगीत के बीच यह झांकियां यात्रा को और अधिक भव्य एवं आकर्षक बना रही हैं।

धार्मिक परंपरा की जीवंतता का परिचय दे रहे श्रद्धालु

प्रशासन का अनुमान है कि आगामी एक सप्ताह में करीब चार करोड़ श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। 11 अगस्त को देशभर के शिवालयों में जलाभिषेक के साथ कांवड़ यात्रा का समापन होगा। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभाग भी लगातार सक्रिय हैं, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके। श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से सराबोर हरिद्वार इन दिनों भगवान शिव की आराधना का विशाल केंद्र बना हुआ है, जहां आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। पूरा वातावरण शिवमय है।

राज्य आंदोलनकारियों से संवाद करेगा यूकेडी, देहरादून में जल्द होगा सम्मेलन

- शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने को आंदोलनकारियों को लामबंद करेगा उत्तराखंड क्रांति दल

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्य आंदोलनकारियों से व्यापक संवाद शुरू करने का निर्णय लिया है। पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि प्रदेशभर के राज्य आंदोलनकारियों को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण पत्र भेजे जाएंगे, ताकि उनसे सीधे संवाद स्थापित कर आगामी चुनाव और संगठन की रणनीति तय की जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के वर्षों बाद भी आंदोलन के शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का निर्माण नहीं हो पाया है।

जयप्रकाश उपाध्याय ने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार पलायन जारी है तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड अब भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन और जलविद्युत परियोजनाओं पर बाहरी लोगों का प्रभाव बढ़ा है, जबकि अपराध भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। उन्होंने सरकार पर राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि वास्तविक आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण अब तक पूरा नहीं हुआ है और आंदोलनकारियों के वर्गीकरण के नाम पर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और आंदोलनकारियों के आश्रितों को प्रमाण-पत्र जारी करने जैसे अपने वादे भी पूरे नहीं किए हैं।

उपाध्याय ने बताया कि इन सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श और आगे की रणनीति तय करने के लिए शीघ्र ही देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसकी तिथि जल्द घोषित की जाएगी। सम्मेलन के संयोजक की घोषणा भी शीघ्र होगी। उन्होंने कहा कि उ,ंद प्रत्येक आंदोलनकारी तक अपनी बात पहुंचाने और सभी आंदोलनकारी शक्तियों को एकजुट कर उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों के सपनों के अनुरूप राज्य निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

'सतपाल महाराज' ने महाभारत सर्किट के विस्तार का रखा प्रस्ताव

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून/जयपुर

उत्तराखंड के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री **सतपाल महाराज** ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से जयपुर स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड और राजस्थान के बीच पर्यटन संभावनाओं को बढ़ाने तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सतपाल महाराज ने बताया कि दोनों राज्यों का पौराणिक और सांस्कृतिक संबंध काफी गहरा है। महाभारत काल में पांडवों का उत्तराखंड और राजस्थान के कई क्षेत्रों से जुड़ाव रहा है।

इसी को देखते हुए दोनों राज्य मिलकर महाभारत सर्किट के विस्तार की दिशा में काम करेंगे, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने राजस्थान के प्रसिद्ध गणगौर उत्सव का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पर्व का संबंध माता गौरी से जुड़ा है। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती हिमालय की पुत्री हैं और उनका मायका उत्तराखंड का हिमालय क्षेत्र माना जाता है। इसलिए उत्तराखंड और राजस्थान के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान की अपार संभावनाएँ हैं। बैठक में दोनों राज्यों की साझा विरासत को पर्यटन के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।

नंदप्रयाग में बाइक फिसलने से 19 वर्षीय युवक की मौत

ऋषिकेश बदरीनाथ हाईवे पर हादसा, हेमकुंड यात्री की मौत

- हेमकुंड यात्री की मौत से परिवार में पसरा मातम

भारतेंदु संवाददाता, थराली

ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में हेमकुंड साहिब की यात्रा से लौट रहे 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा नंदप्रयाग हाईवे पर बगड़ चौराहे के समीप हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार करनाल हरियाणा निवासी साहिल बाबा अपने दोस्तों के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा पूरी कर बाइक से कर्णप्रयाग की ओर लौट रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई। हादसे में साहिल गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद साथ चल रहे दोस्तों और राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। नंदप्रयाग चौकी प्रभारी जतन सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल युवक को अस्पताल भेजा, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। प्रारंभिक जांच में बाइक फिसलने को हादसे का कारण बताया जा रहा है। युवक की मौत से उसके परिवार और दोस्तों में शोक की लहर है।

रुद्रप्रयाग पुलिस ने केबल चोरी गिरोह का किया भंडाफोड़, सात गिरफ्तार

- 147 कॉपर प्लेट और दो मोटर हुए बरामद

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

रुद्रप्रयाग पुलिस ने पम्प हाउसों और हॉटमिक्स प्लांटों से केबल, कॉपर प्लेट, मोटर और अन्य सामान चोरी करने वाले गिरोह का महज छह दिन में खुलासा करते हुए सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें चार मुख्य आरोपित और चोरी का माल खरीदने वाले तीन कबाड़ी शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 147 कॉपर प्लेट, 50.28 मीटर समरसीबल केबल व तांबे की तार, दो इलेक्ट्रिक मोटर तथा वारदात में प्रयुक्त दो स्कूटियां बरामद की हैं।

पुलिस के अनुसार 31 जुलाई और एक अगस्त को दर्ज दो अलग-अलग चोरी के मामलों की जांच के दौरान कोतवाली रुद्रप्रयाग पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपितों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपितों की निशानदेही पर बद्रीनाथ हाईवे स्थित तिलणी और रुद्रप्रयाग बस अड्डे के पास कबाड़ी की दुकानों से चोरी का सामान बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। सभी आरोपितों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जबकि गिरोह से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि चोरी की घटनाओं में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून में जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

- उत्तरकाशी के 40 किसान देहरादून में ले रहे जैविक खेती का प्रशिक्षण

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड (उत्तराखंड जैविक उत्पादक परिषद) द्वारा किसान भवन, देहरादून में जैविक एवं प्राकृतिक खेती विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्य, म का शुभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों को आधुनिक जैविक एवं प्राकृतिक खेती की वैज्ञानिक और व्यवहारिक तकनीकों से अवगत कराना तथा राज्य में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना है। कार्य, म के माध्यम से किसानों को जैविक खेती की नई पद्धतियों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, उन्नत कृषि प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन संबंधी जानकारी दी जाएगी।

जैविक कृषि के विस्तार में मिलेगी मदद

श्री बर्फाल ने बताया कि परिषद समय-समय पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है, जिससे प्रदेश के अधिक से अधिक किसान जैविक एवं प्राकृतिक खेती की नवीन तकनीकों को अपनाकर रासायनिक खेती पर निर्भरता कम कर सकें। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ किसानों को जैविक खाद, प्राकृतिक कीटनाशक, फसल प्रबंधन, विपणन तथा प्रमाणन की प्रक्रिया की भी जानकारी देंगे। यह कार्यक्रम किसानों के कौशल विकास, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और उत्तराखंड में जैविक कृषि के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

आपदा | मानसून सक्रिय, तीन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, धामी ने दिए हाई अलर्ट के निर्देश

उत्तराखंड में अगले सात दिन जारी रहेगा भारी बारिश का दौर

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सर्, य हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले सात दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। बुधवार के लिए देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चंपावत और ऊधमसिंह नगर जिलों में भी भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा कुछ स्थानों पर अत्यंत तीव्र वर्षा होने की आशंका व्यक्त करते हुए लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन सचिव को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तथा सभी जिला प्रशासन को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने और राहत एवं बचाव कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतने को कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और राज्य में आए पर्यटकों से मौसम की गंभीरता को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करें तथा नदियों, बरसाती नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। साथ ही प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

तीन जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी

बुधवार को देहरादून सहित राज्य के कई हिस्सों में सुबह से रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। आसमान घने बादलों से ढका रहा और बीच-बीच में हल्की धूप निकलने के बाद फिर बादल छा गए। बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़कें बाधित होने की आशंका भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा और कई क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। लगातार हो रही वर्षा के कारण नदियों और बरसाती नालों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है।

अलकनंदा चेतावनी स्तर पर पहुंची

रुद्रप्रयाग जनपद में अलकनंदा नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर पर पहुंच गया है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार बुधवार सुबह सात बजे अलकनंदा का जलस्तर 626.00 मीटर दर्ज किया गया, जबकि मंदाकिनी नदी का जलस्तर 624.98 मीटर रहा, जो चेतावनी स्तर से थोड़ा नीचे है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों और श्रद्धालुओं से नदी तटों पर न जाने की अपील की है। नगर क्षेत्रों में लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार सतर्कता संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके।

बढ़ते जलस्तर से सड़क योजनाएं हुईं प्रभावित

बारिश के आंकड़ों के अनुसार ऊखीमठ में सर्वाधिक 32.50 मिलीमीटर तथा जखोली में 26.00 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि रुद्रप्रयाग मुख्यालय में वर्षा नहीं हुई। जिले में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खुले हैं, हालांकि दो राज्य राजमार्ग, दो लोक निर्माण विभाग के मार्ग, छह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्ग तथा एक एनपीसीसी मार्ग अभी भी अवरुद्ध हैं। संबंधित विभागों द्वारा मार्ग खोलने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है।

गनीव कौर से अभद्रता के आरोप पर सुखबीर बादल ने 'आप 'सरकार को घेरा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब विधानसभा में मजीठा से अकाली विधायक गनीव कौर मजीठिया के साथ कथित अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि दोषी लोगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो शिरोमणि अकाली दल इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएगा और सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करेगा।

सुखबीर सिंह बादल ने इंटरनेट मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि उन्हें मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान गनीव कौर मजीठिया ने सदन के वेल में पहुंचकर स्पीकर कुलतार सिंह संधवां और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि गनीव कौर ने उस टिप्पणी का विरोध किया, जिसमें कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व और समर्थकों की तुलना 'संगत' से करते हुए 'संगत' को 'गुरु' से ऊपर बताया गया। बादल ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा गंभीर विषय है और इसका विरोध करना स्वाभाविक था।

अकाली दल अध्यक्ष का आरोप है कि विरोध के दौरान आम आदमी पार्टी के कई मंत्री और विधायक भी सदन के वेल में पहुंच गए। उन्होंने दावा किया कि वहां गनीव कौर मजीठिया के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया, उन्हें धमकियां दी गईं और अपमानजनक टिप्पणियां भी की गईं। उन्होंने कहा कि एक महिला विधायक के साथ इस प्रकार का व्यवहार लोकतांत्रिक परंपराओं और विधानसभा की गरिमा के अनुरूप नहीं है।

एयरोट्रोपोलिस प्रभावितों के लिए गमाडा ने तैयार किए दो प्लॉट मॉडल

अधिग्रहित जमीन के बदले रिहायशी और व्यावसायिक प्लॉट आवंटन का नया फॉर्मूला तैयार

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली

ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने एयरोट्रोपोलिस परियोजना के तहत अधिग्रहित की गई जमीन के बदले प्रभावित भूमि मालिकों को विकसित प्लॉट आवंटित करने के लिए बहुप्रतीक्षित फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इसके लिए दो अलग-अलग मॉडल बनाए गए हैं। पहले मॉडल में केवल रिहायशी प्लॉट देने का प्रावधान रखा गया है, जबकि दूसरे मॉडल में कुछ श्रेणियों के पात्र भूमि मालिकों को रिहायशी प्लॉट के साथ व्यावसायिक प्लॉट देने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। गमाडा का मानना है कि इस नई व्यवस्था से पुनर्वास प्रक्रिया में तेजी आएगी और लंबे समय से प्लॉट आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे किसानों व अन्य भूमि मालिकों को राहत मिलेगी।

इस संबंध में मुख्य प्रशासक की अध्यक्षता में पुड्डा भवन, सेक्टर-62 में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में एयरोट्रोपोलिस परियोजना के पॉकेट ई से जे तक के लिए प्लॉट आकार निर्धारित करने और विभिन्न श्रेणियों के भूमि मालिकों को मिलने वाले प्लॉटों के संयोजन पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों ने परियोजना के लेआउट, पुनर्वास नीति और भविष्य की विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों मॉडल तैयार किए हैं।

पहले मॉडल के तहत केवल विकसित रिहायशी प्लॉट देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें 200, 300 और 500 वर्ग गज के प्लॉटों का अलग-अलग संयोजन तैयार किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार एक कनाल भूमि के बदले 200 वर्ग गज का एक रिहायशी प्लॉट दिया जाएगा। दो कनाल जमीन के बदले 200-200 वर्ग गज के दो प्लॉट मिलेंगे। तीन कनाल के बदले 300-300 वर्ग गज के दो प्लॉट प्रस्तावित हैं। इसी प्रकार चार से आठ कनाल तक भूमि रखने वाले पात्र लोगों के लिए भी 200, 300 और 500 वर्ग गज के प्लॉटों का अलग-अलग संयोजन तैयार किया गया है, ताकि प्रत्येक श्रेणी के भूमि मालिक को उसकी पात्रता के अनुरूप विकसित रिहायशी प्लॉट उपलब्ध कराया जा सके।

दूसरे मॉडल में कुछ पात्र श्रेणियों के लिए रिहायशी प्लॉट के साथ व्यावसायिक प्लॉट देने का विकल्प रखा गया है। इसके तहत चार कनाल भूमि के बदले 300 और 200 वर्ग गज के दो रिहायशी प्लॉटों के साथ 100 वर्ग गज का एक कॉमर्शियल प्लॉट देने का प्रस्ताव है। छह कनाल भूमि के लिए 500, 200 और 200 वर्ग गज के रिहायशी प्लॉटों के साथ 100 वर्ग गज का व्यावसायिक प्लॉट दिया जाएगा। सात कनाल भूमि रखने वाले पात्र लोगों को 500, 300 और 200 वर्ग गज के रिहायशी प्लॉटों के साथ 100 वर्ग गज का कॉमर्शियल प्लॉट मिलेगा। वहीं, आठ कनाल भूमि के बदले 500 और 300 वर्ग गज के रिहायशी प्लॉटों के साथ 200 वर्ग गज का व्यावसायिक प्लॉट देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कुछ विशेष श्रेणियों के लिए स्पेशल एलओआई (लेटर ऑफ इंटेंट) का प्रावधान भी रखा गया है।

गौरतलब है कि एयरोट्रोपोलिस परियोजना के लिए बड़ी संख्या में किसानों और अन्य भूमि मालिकों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। अब तक यह स्पष्ट नहीं था कि अलग-अलग श्रेणी की भूमि के बदले कितने और किस आकार के विकसित प्लॉट दिए जाएंगे। प्लॉट आकार और उनके संयोजन को अंतिम रूप मिलने के बाद अब पुनर्वास नीति को लागू करने, लेआउट प्लान तैयार करने और प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

न्यूज ब्रीफ

पीएसईबी ने शुरू किया सुरक्षित प्रमाणपत्र सत्यापन पोर्टल

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रमाणपत्र सत्यापन प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य प्रमाणपत्रों में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाना है। बोर्ड के अनुसार, हर साल करीब 25 हजार से अधिक सत्यापन आवेदन प्राप्त होते हैं। पहले सत्यापन रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप और फर्जीवाड़े की शिकायतें सामने आई थीं, जिनमें कुछ मामलों में आपराधिक कार्रवाई भी करनी पड़ी थी। नई डिजिटल व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित और छेड़छाड़ मुक्त होगी। आवेदन से लेकर अंतिम रिपोर्ट जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया केवल अधिकृत अधिकारियों और बोर्ड के बीच सीमित रहेगी। उम्मीदवार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभाग, विश्वविद्यालय और भर्ती एजेंसियां सीधे बोर्ड से प्रमाणपत्रों का सत्यापन करा सकेंगी।

पार्क में नशा करते तीन युवक गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर। शिवालिक विहार स्थित शिव मंदिर पार्क में नशीले पदार्थों के सेवन की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पार्क में कुछ युवक नशे का सेवन कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने शाम करीब सवा सात बजे मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से पीयूष तलवार, निखिल और रोहन सैनी को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने तीनों युवकों को सिविल अस्पताल ढकोली ले जाकर डोप टेस्ट करवाया। मेडिकल जांच में पीयूष तलवार और रोहन सैनी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोनों के शरीर में मॉर्फीन और बेंज़ोडायजेपीन के सेवन की पुष्टि हुई। पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

मोहाली तहसील में रिश्वत लेते क्लर्क गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। मोहाली तहसील कार्यालय में रजिस्ट्रियों के नाम पर रिश्वतखोरी के मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। फ्लाइंग स्क्वाड-1 की टीम ने तहसीलदार कार्यालय में तैनात क्लर्क भूपेंद्र कौर को एक लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विजिलेंस के अनुसार यह कार्रवाई शिकायतकर्ता प्रभजीत सिंह की शिकायत पर की गई। आरोप है कि क्लर्क ने स्काई लार्क सोसाइटी में सस्ते फ्लैट की रजिस्ट्री करवाने के लिए आठ लाख रुपये में सौदा तय किया था। पहली किस्त के रूप में एक लाख रुपये लेते समय विजिलेंस टीम ने उसे पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पर पहले भी रजिस्ट्री संबंधी कार्यों में अवैध वसूली के आरोप रहे हैं। विजिलेंस अब यह पता लगाने में जुटी है कि रिश्वतखोरी के इस मामले में कोई अन्य कर्मचारी, अधिकारी या बिचौलिया शामिल है या नहीं। मामले से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जा रही है।

गुरबाणी प्रसारण को लेकर विधायक निज्जर ने उठाई मांगें

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के विधायक इंदरबीर सिंह निज्जर ने गुरबाणी के प्रसारण को लेकर कई मांगें उठाई हैं। उन्होंने कहा कि गुरबाणी का सभी चैनलों पर निःशुल्क और निष्पक्ष प्रसारण होना चाहिए तथा इसका व्यवसायीकरण नहीं किया जाना चाहिए। निज्जर ने गुरबाणी प्रसारण में कथित एकाधिकार व्यवस्था समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि सभी चैनलों को समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने एसजीपीसी को कथित वित्तीय नुकसान की भरपाई और 7.5 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने की मांग भी की। उन्होंने एसजीपीसी से अपना स्वयं का प्रसारण ढांचा विकसित करने की अपील की। साथ ही सिख न्यायिक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और एसजीपीसी चुनाव जल्द कराने की मांग भी उठाई।

पंजाब विधानसभा में विकास और सुविधाओं पर गरमाया मुद्दा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब विधानसभा के प्रश्नकाल में विकास कार्यों में देरी, सरकारी स्कूलों में बिजली व्यवस्था और जेलों में मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में रखा, वहीं विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने लंबित मामलों को लेकर अधिकारियों और विभागों को सख्त निर्देश दिए।

जलालाबाद से विधायक गोल्डी कंबोज ने अपने क्षेत्र में प्रस्तावित दो नई मंडी समितियों के निर्माण में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से बार-बार नई आपत्तियां लगाई जा रही हैं, जिसके कारण विकास कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सभी आपत्तियों को एक साथ रखा जाए, ताकि उनका जल्द समाधान कर निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।

इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब 'तारीख पर तारीख' वाली कार्यप्रणाली नहीं चलेगी। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाए, ताकि जनता से जुड़े विकास कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।

सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने सरकारी स्कूलों में बिजली की समस्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में प्रवासी भारतीयों की मदद से एयर कंडीशनर लगाए गए हैं, लेकिन बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को भी बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए।

पठानमाजरा ने कहा कि पहले सदन में सरकारी स्कूलों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक यह योजना पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है। इस पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से स्कूलों और अन्य सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

कैग ने खोली सिटको की पोल, प्रशासनिक चूक से करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की ऑडिट रिपोर्ट में चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सिटको) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि खराब योजना, वित्तीय अनुशासन की कमी और परिसंपत्तियों के समुचित उपयोग में लापरवाही के कारण निगम को पिछले तीन वर्षों में लगभग 10 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।

वर्ष 2023-24 और 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट में कई ऐसे मामलों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें समय रहते उचित निर्णय लेकर टाला जा सकता था। रिपोर्ट के अनुसार सिटको अपने होटलों के लिए आज तक स्वयं की ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली विकसित नहीं कर सका। इसके चलते होटल माउंटव्यू, होटल शिवालिकव्यू और होटल पार्कव्यू निजी बुकिंग वेबसाइटों पर निर्भर रहे। अप्रैल 2022 से फरवरी 2025 के बीच इन प्लेटफॉर्मों को कमीशन के रूप में करीब 2.08 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा। कैग ने माना कि समय पर अपनी बुकिंग व्यवस्था शुरू होने से यह खर्च बचाया जा सकता था।

रिपोर्ट में स्टील डिपो के संचालन पर भी सवाल उठाए गए हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को इस्पात उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित डिपो में बिक्री लगभग बंद रही। वर्ष 2023-24 में केवल चार लाख रुपये की बिक्री हुई, जबकि 2024-25 में फरवरी तक कोई बिक्री दर्ज नहीं की गई। इसके बावजूद वहां तैनात 10 कर्मचारियों के वेतन और अन्य मदों पर दो वर्षों में लगभग 1.40 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

कैग ने सुखना लेक स्थित बेकरी के संचालन को भी घाटे का सौदा बताया है। रिपोर्ट के अनुसार दुकान को किराये पर देने के बजाय सिटको ने स्वयं बेकरी चलाने का निर्णय लिया। यदि दुकान किराये पर दी जाती तो हर माह लगभग डेढ़ लाख रुपये का किराया प्राप्त हो सकता था।

शराब ठेकेदार की शिकायत पर सीबीआई ने जुटाए अहम साक्ष्य और रिकॉर्डिंग

सीबीआई के सबूतों के बावजूद मनीमाजरा एसएचओ पर कार्रवाई नहीं, उठे गंभीर सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली

चंडीगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मनीमाजरा थाना के तत्कालीन एसएचओ पर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोपों से जुड़े साक्ष्य चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का दावा किया जा रहा है। इस मामले ने पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार और जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

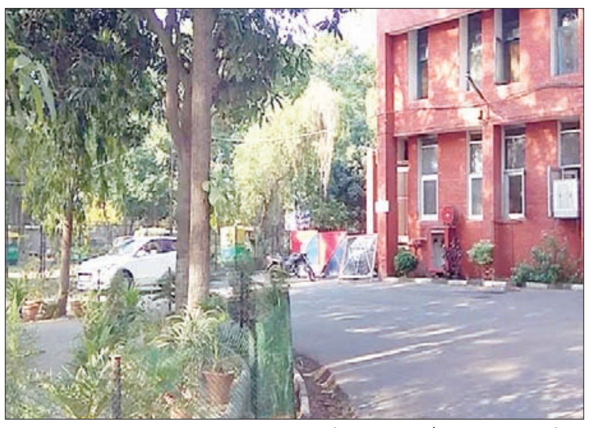

जानकारी के अनुसार, सीबीआई के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) ने लगभग 15 दिन पहले चंडीगढ़ पुलिस के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को एक विस्तृत पत्र भेजकर संबंधित एसएचओ के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी। पत्र के साथ कथित रिश्वत मांगने की ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसकी पेन ड्राइव तथा बातचीत की लिखित ट्रांस्क्रिप्ट भी उपलब्ध कराई गई थी।

बताया जा रहा है कि संबंधित एसएचओ पर एक शराब ठेकेदार से हर माह एक लाख रुपये और दो पेटी महंगी विदेशी शराब की मांग करने का आरोप है। शिकायत के अनुसार, ठेकेदार पहले भी कथित रूप से मासिक राशि देता रहा था, लेकिन जब एसएचओ ने रकम बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रतिमाह और अतिरिक्त विदेशी शराब की मांग की तो ठेकेदार ने आर्थिक असमर्थता जताई। इसके बाद उसे लगातार परेशान किए जाने का आरोप लगाया गया।

शिकायत में कहा गया है कि पुलिस ने शराब के ठेके के बाहर नाका लगवा दिया, जिससे ग्राहकों को वाहन खड़ा करने और ठेके तक पहुंचने में परेशानी होने लगी। इससे व्यवसाय प्रभावित होने लगा। लगातार दबाव और कथित उत्पीड़न से परेशान होकर ठेकेदार ने पूरे मामले की शिकायत सीबीआई से की।

शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की प्राथमिक जांच शुरू की। जांच एजेंसी ने कथित बातचीत की रिकॉर्डिंग कराई और रिश्वत लेने के आरोप की पुष्टि के लिए ट्रैप की योजना भी बनाई। हालांकि, निर्धारित समय पर शिकायतकर्ता पैसे लेकर मौके पर नहीं पहुंच सका, जिसके कारण ट्रैप सफल नहीं हो पाया। बावजूद इसके, सीबीआई ने उपलब्ध रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए उन्हें चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास कार्रवाई के लिए भेज दिया।

सूत्रों के अनुसार, यह पहला अवसर माना जा रहा है जब किसी एसएचओ स्तर के अधिकारी की कथित रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग और उससे संबंधित दस्तावेज सीधे पुलिस नेतृत्व को उपलब्ध कराए गए हैं।

रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर पांच लाख की ठगी

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर पांच लाख रुपये की कथित ठगी और पैसे वापस मांगने पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। ढकोली पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना में घायल युवक को गंभीर हालत में सेक्टर-32 स्थित सरकारी अस्पताल रेफर किया गया है।

पीड़ित शैंटी और विजय ने पुलिस को बताया कि उन्होंने हैप्पी नामक एजेंट को रूस में नौकरी दिलाने के लिए पांच लाख रुपये दिए थे। आरोपी ने दोनों को भरोसा दिलाया था कि रूस पहुंचते ही उन्हें अच्छी नौकरी और उचित वेतन मिलेगा। एजेंट के आश्वासन पर दोनों युवक रूस चले गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद करीब दस दिनों तक उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला। काफी प्रयासों के बावजूद जब काम नहीं मिला तो दोनों भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद दोनों युवकों ने एजेंट से संपर्क कर अपने रुपये वापस मांगे। बुधवार को वे पैसे लेने के लिए आरोपी से मिलने पहुंचे। आरोप है कि एजेंट ने रुपये लौटाने से साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने शैंटी के सिर पर किसी वस्तु से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर से काफी खून बहने लगा।

◆ नौकरी का वादा निकला झूठा, रकम मांगने पर मारपीट का लगा आरोप

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया और ढकोली पुलिस के हवाले कर दिया गया। घायल शैंटी को पहले स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए सेक्टर-32 स्थित सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया। मामले के जांच अधिकारी भूपिंदर सिंह ने बताया कि अस्पताल से मेडिकल रुक्का प्राप्त हो गया है।

227 करोड़ प्रस्ताव पर 'आप 'का हमला, भाजपा पर नियम तोड़ने का आरोप

टेबल एजेंडे से प्रस्ताव पारित करने पर पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों के उल्लंघन का आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी (आप) चंडीगढ़ ने नगर निगम की जनरल हाउस बैठक में 227 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को अंतिम समय में टेबल एजेंडे के माध्यम से पारित किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि भाजपा ने अपने बहुमत का दुरुपयोग करते हुए इतने बड़े वित्तीय प्रस्ताव को बिना पर्याप्त चर्चा और पारदर्शिता के जल्दबाजी में मंजूरी दिला दी, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता के टैक्स के पैसे की जवाबदेही पर सवाल खड़े हो गए हैं।

चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में आप के प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह, महासचिव ओमकार सिंह औलख, मुख्य प्रवक्ता योगेश धींगरा, कोर कमेटी अध्यक्ष प्रेम गर्ग तथा पूर्व महापौर कुलदीप कुमार ने कहा कि 31 जुलाई 2026 को हुई नगर निगम की 363वीं जनरल हाउस बैठक में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अनुसार बैठक का एजेंडा सभी पार्षदों को कम से कम 72 घंटे पहले उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जबकि पूरक एजेंडा भी 48 घंटे पहले दिया जाना अनिवार्य है। इसके बावजूद 227 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण प्रस्ताव केवल दो पन्नों के टेबल एजेंडे के रूप में अंतिम समय पर सदन में रखा गया।

आप नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्षदों को प्रस्ताव का अध्ययन करने, विशेषज्ञों से राय लेने या तकनीकी और वित्तीय पहलुओं की समीक्षा का अवसर नहीं दिया गया। पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि सेक्टर-39 और कजौली वाटर वर्क्स से जुड़ी पाइपलाइन परियोजना के संबंध में आवश्यक तकनीकी जानकारी एजेंडे में शामिल नहीं थी। पाइपलाइन नई होगी या पुरानी बदली जाएगी, किस प्रकार के पाइप का इस्तेमाल होगा, उसकी क्षमता और लागत का आधार क्या है, जैसी अहम जानकारियां भी उपलब्ध नहीं कराई गईं। पार्टी ने इस मामले की शिकायत पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी प्रशासक को भेजने की जानकारी देते हुए मांग की कि 227 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को तत्काल निरस्त कर नियमित प्रक्रिया के तहत दोबारा सदन में लाया जाए। साथ ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, लागत का पूरा ब्यौरा, टेंडर संबंधी जानकारी और तकनीकी विवरण सार्वजनिक किए जाएं। आप ने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो वह सड़क से लेकर सदन तक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी।

भाजपा पर आप का हमला

साथ ही आम आदमी पार्टी ने मांग की कि भविष्य में करोड़ों रुपये के किसी भी वित्तीय प्रस्ताव को टेबल एजेंडे के माध्यम से अंतिम समय पर सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पार्टी नेताओं का कहना है कि ऐसे सभी प्रस्ताव निर्धारित नियमों के अनुसार समय से पहले सभी पार्षदों को उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे उनका अध्ययन कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों से तकनीकी व वित्तीय सलाह भी ले सकें। उनका कहना था कि नगर निगम जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि यह पहला अवसर नहीं है जब बड़े वित्तीय प्रस्तावों को सीमित चर्चा के बीच पारित किया गया हो। इससे पहले भी लगभग 190 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को इसी प्रकार मंजूरी दिए जाने का पार्टी ने विरोध किया था। उनका कहना है कि यदि इस तरह की प्रक्रिया जारी रही तो जनता के धन के उपयोग पर प्रभावी निगरानी संभव नहीं हो पाएगी। पार्टी ने यह भी मांग उठाई कि नगर निगम में टेबल एजेंडे के माध्यम से लाए जाने वाले प्रस्तावों की अधिकतम वित्तीय सीमा तय की जाए, ताकि बड़े और महत्वपूर्ण विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा सुनिश्चित हो सके।

इलाज बहाने होटल पहुंचा कैदी, दो पुलिसकर्मियों सहित पांच गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा और चंडीगढ़ के बहुचर्चित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 661 करोड़ रुपये के कथित फ्रॉड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। न्यायिक हिरासत में बंद विचाराधीन कैदी विक्रम वाधवा को इलाज के बहाने अस्पताल ले जाने के बाद कथित साजिश के तहत सेक्टर-17 स्थित होटल सिटीहार्ट में परिवार और अन्य लोगों से मिलवाने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में सेक्टर-17 थाना पुलिस ने सेक्टर-26 पुलिस लाइन में तैनात सब-इंस्पेक्टर जगमेहर और एएसआई सुरिंदर सहित पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अन्य आरोपितों में विक्रम वाधवा के बेटे करण वाधवा और कुणाल वाधवा भी शामिल हैं। सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे घटनाक्रम की योजना पहले से बनाई गई थी या नहीं और इसमें अन्य लोगों की भी कोई भूमिका रही है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 661 करोड़ रुपये के कथित बैंक फ्रॉड मामले में न्यायिक हिरासत में बंद विक्रम वाधवा ने जेल में तबीयत खराब होने की शिकायत की थी। इसके बाद अदालत की अनुमति मिलने पर उसे उपचार के लिए सेक्टर-16 स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया। आरोप है कि इलाज पूरा होने के बाद उसे नियमानुसार सीधे जेल वापस ले जाने के बजाय पुलिसकर्मी निजी वाहन से सेक्टर-17 स्थित होटल सिटीहार्ट ले गए।

जांच के अनुसार विक्रम वाधवा होटल में काफी देर तक रुका। इस दौरान उसने आराम किया और अपने परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों से मुलाकात की। पुलिस को संदेह है कि इस मुलाकात के दौरान फरार होने की संभावित योजना पर भी चर्चा की गई हो सकती है। होटल में उसकी मौजूदगी और वहां हुई मुलाकातों से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। होटल के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पुलिस विभाग ने इस पूरे मामले को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की विभागीय जांच भी शुरू कर दी है।

पंजाब में कृषि और उद्योग संकट पर व्यापार मंडल ने जताई चिंता

व्यापार मंडल ने सरकार से उद्योगों को राहत और कृषि समस्याओं के समाधान की मांग की

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने पंजाब में कृषि, उद्योग और व्यापार की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कभी देश में कृषि क्षेत्र का अग्रणी राज्य माना जाने वाला पंजाब आज उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से इन समस्याओं के समाधान के लिए जल्द प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।

दो दिवसीय चंडीगढ़ दौरे के दौरान किसान भवन में आयोजित बैठक में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के उद्योग एवं व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करते हुए बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि और औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, जबकि पंजाब का कृषि और उद्योग क्षेत्र लगातार दबाव में है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के उद्योगों को नई नीतियों, निवेश और सरकारी सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों में नए उद्योग स्थापित करने या मौजूदा उद्योगों के विस्तार के लिए पर्याप्त रियायतें और सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। इससे राज्य में औद्योगिक विकास की गति प्रभावित हुई है।

बैठक में राइस मिल उद्योग से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई। बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि गोदामों से समय पर माल की निकासी नहीं होने के कारण पंजाब के राइस मिलरों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार चावल को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के लिए 200 से 300 किलोमीटर तक अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है, जिसका ट्रांसपोर्ट खर्च भी उद्योग संचालकों को स्वयं उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी मिलिंग प्रक्रिया से जुड़े कई काम अभी भी अधूरे पड़े हैं।

बैठक में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह चीमा ने इथेनॉल मिश्रण नीति को लेकर चल रहे विवाद पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में इथेनॉल उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है, जबकि पंजाब में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं होने के बावजूद विकास में बाधाएं आ रही हैं।

चीमा ने कहा कि इथेनॉल उद्योग का सीधा संबंध किसानों से है। उन्होंने दावा किया कि मक्का पंजाब की प्रमुख फसलों में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि इथेनॉल मिश्रण नीति प्रभावित होती है तो इसका सबसे अधिक असर किसानों की आय पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ईंधन में इथेनॉल मिश्रण को लेकर अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए और किसानों तथा देश के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर नीति बनाई जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिश्रण से विदेशी मुद्रा की बचत होती है और किसानों को वैकल्पिक बाजार मिलता है। इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक विवाद की बजाय आर्थिक और कृषि हितों के नजरिए से देखा जाना चाहिए।

बैठक के बाद बाबूलाल गुप्ता ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और उन्हें कृषि, उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि इन मुद्दों को केंद्र और राज्य सरकारों के समक्ष उठाकर समाधान की दिशा में पहल की जाए।

इस अवसर पर राष्ट्रीय व्यापारी बोर्ड के सदस्य चरणजीत सिंह, हिमाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष प्रकाश देव, चंडीगढ़ आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील मित्तल, उद्योग व्यापार मंडल चंडीगढ़ के अध्यक्ष संजीव चड्ढा, राष्ट्रीय महासचिव पुनीत जैन और पंजाब इकाई के अध्यक्ष जसविंदर सिंह राणा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में व्यापारियों और उद्योगपतियों ने राज्य में कारोबारी माहौल सुधारने, नीतिगत सहयोग बढ़ाने और उद्योगों को राहत देने की मांग उठाई।

अमृतसर में चन्नी के खिलाफ लगे पोस्टर , कांग्रेस में हुई गुटबाजी तेज

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर। पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान अब सार्वजनिक रूप से सामने आती दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ अमृतसर शहर के कई इलाकों में विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से चन्नी को पार्टी से बाहर करने की मांग की गई है। साथ ही उन पर भारतीय जनता पार्टी के करीब होने के आरोप भी लगाए गए हैं।

बुधवार सुबह शहर के विभिन्न इलाकों में लगाए गए इन पोस्टरों पर लोगों की नजर पड़ी। सुबह की सैर के लिए निकले लोगों ने पोस्टरों पर लिखे संदेशों को पढ़ा और कई लोगों ने इनके फोटो और वीडियो बनाकर सामाजिक माध्यमों पर साझा किए। इसके बाद देखते ही देखते ये पोस्टर चर्चा का विषय बन गए।

पोस्टरों में चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। एक पोस्टर में लिखा गया, 'घर-घर दे विच चली गल, चन्नी चल्या भाजपा वल '। वहीं, दूसरे पोस्टर में राहुल गांधी से अपील करते हुए लिखा गया कि चन्नी को कांग्रेस से बाहर किया जाए। एक अन्य पोस्टर में चन्नी से सवाल करते हुए भाजपा से कथित नजदीकियों को लेकर जवाब मांगा गया है।

हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये पोस्टर किसने लगाए हैं। पोस्टर लगाने वालों की पहचान को लेकर पुलिस या कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कांग्रेस की तरफ से भी इस मामले में अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है।

राजनीतिक जानकार इस पूरे घटनाक्रम को पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी गुटबाजी से जोड़कर देख रहे हैं। चर्चा है कि इन पोस्टरों के पीछे कांग्रेस के ही कुछ नेताओं का हाथ हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कुछ लोग इसे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के समर्थक गुट से जोड़कर भी देख रहे हैं, लेकिन इस संबंध में भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

गौरतलब है कि पंजाब कांग्रेस पिछले कुछ समय से नेताओं के बीच मतभेदों को लेकर चर्चा में रही है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ लगे पोस्टरों ने पार्टी की अंदरूनी राजनीति को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। अब सभी की नजर कांग्रेस नेतृत्व की प्रतिक्रिया और मामले में आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। कांग्रेस नेताओं के बीच बढ़ते मतभेदों के बीच यह घटनाक्रम पार्टी के लिए नई चुनौती माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर बयानबाजी और तेज हो सकती है। वहीं, पोस्टर लगाने वाले लोगों की पहचान सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।

पूजा के बहाने युवती से दुष्कर्म के प्रयास पर तांत्रिक के खिलाफ कथित मामला दर्ज

कनाडा निवासी युवती की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज

भारतेंदु संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना में पूजा कराने के बहाने एक युवती से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। कनाडा में रहने वाली एक प्रवासी भारतीय युवती ने कथित तांत्रिक पर होटल के कमरे में उसके साथ अश्लील हरकतें करने और जबरन दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद सराभा नगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है।

पुलिस को दी शिकायत के अनुसार, पीड़िता मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली है और वर्तमान में कनाडा में रहती है। वह अपनी मां और भाई के साथ लुधियाना आई थी। परिवार का उद्देश्य भाई के बेहतर भविष्य के लिए विशेष पूजा करवाना था। इसके लिए उन्होंने शहर के एक होटल में कमरा लिया था।

शिकायत में युवती ने बताया कि राहुल सूद नामक व्यक्ति ने उसके भाई के उज्ज्वल भविष्य और विशेष पूजा कराने का भरोसा दिया था। इसके बाद उसने परिवार को होटल में बुलाया। पीड़िता के अनुसार, पूजा शुरू होने से पहले आरोपी ने कुछ पूजा सामग्री मंगवाई। इसी दौरान उसकी मां सामान लेने बाहर चली गई और आरोपी ने किसी बहाने उसके भाई को भी कमरे से बाहर भेज दिया।

पीड़िता का आरोप है कि कमरे में अकेले होने के बाद आरोपी ने कहा कि उसके शरीर में दो कथित नकारात्मक शक्तियां हैं, जिन्हें धार्मिक प्रक्रिया के माध्यम से बाहर निकालना होगा। आरोप है कि इसी बहाने उसने युवती के साथ गलत हरकतें शुरू कर दीं। जब युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने इसे पूजा की प्रक्रिया का हिस्सा बताया। इसके बाद उसने कथित रूप से जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया। युवती ने शोर मचाकर विरोध किया और किसी तरह खुद को आरोपी से बचाकर कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आने के बाद उसने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

बीएसएफ ने पकड़ी 25 करोड़ की हेरोइन और ड्रोन

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पंजाब के अमृतसर सेक्टर में बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की हेरोइन, एक ड्रोन और अत्याधुनिक पिस्टल बरामद की है। बीएसएफ की टीम ने सीमावर्ती गांव दुपसरी के इलाके में यह कार्रवाई की।

जानकारी के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि गांव के पास धान के खेतों में एक ड्रोन लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। ड्रोन के साथ एक पीले रंग का पैकेट भी बंधा हुआ था। सूचना मिलते ही बीएसएफ जवान मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र की जांच की। जांच के दौरान ड्रोन से बंधे पैकेट में हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा मौके से एक अत्याधुनिक पिस्टल भी बरामद किया गया। बीएसएफ ने सभी सामान को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि ड्रोन किसके द्वारा भेजा गया था और इसके पीछे कौन सा तस्करी नेटवर्क सक्रिय है। अधिकारियों के अनुसार, सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थ और हथियार पहुंचाने की कोशिशों को रोकने के लिए लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है।

निजी स्कूल फीस सीमा विवाद पहुंचा हाईकोर्ट

फीस वृद्धि नियमों पर पंजाब सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि की सीमा को 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ निजी स्कूल संचालकों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निजी स्कूलों की तीन प्रमुख एसोसिएशनों ने सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए इसे कानून के प्रावधानों के खिलाफ बताया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अध्यादेश के खिलाफ स्कूल एसोसिएशन पहुंची हाईकोर्ट

फैडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पंजाब, रिकॉग्नाइज्ड एफिलिएटेड स्कूल्स एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन और प्राइवेट अनएडिड स्कूल्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि पंजाब सरकार द्वारा जारी किया गया अध्यादेश वर्ष 2016 और 2019 में बनाए गए संबंधित कानूनों की भावना के विपरीत है।

स्कूल एसोसिएशनों ने कहा कि सरकार द्वारा अध्यादेश के माध्यम से निजी स्कूलों से शैक्षणिक सत्र 2023-24 से अब तक की फीस संबंधी पूरी जानकारी और रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, जो उचित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। उन्होंने अदालत से मांग की कि इस अध्यादेश को रद्द किया जाए।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी सवाल उठाया कि जब पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका था तो सरकार इस मामले को अध्यादेश के बजाय विधेयक के रूप में सदन में पेश कर सकती थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान अध्यादेश लाने की जरूरत समझ से परे है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि क्या इस अध्यादेश को अब विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जा रहा है। सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि इस संबंध में विचार किया जा सकता है। इस पर अदालत ने अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अध्यादेश आमतौर पर उस समय लाया जाता है जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार ने पिछले महीने अध्यादेश जारी किया और अब विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में इतनी जल्दबाजी में अध्यादेश लाने का क्या कारण था, इसका जवाब सरकार को देना होगा। वहीं पंजाब सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि अगले आदेश तक निजी स्कूलों से पिछले तीन वर्षों में 5 प्रतिशत से अधिक बढ़ाई गई फीस वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सीएचओ हड़ताल से पंजाब के आयुष्मान केंद्रों पर लगे ताले

भारतेंदु संवाददाता, गुरदासपुर। पंजाब के करीब 2500 आयुष्मान आरोग्य केंद्रों में सेवाएं दे रहे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) ने बुधवार से अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल दोबारा शुरू कर दी। हड़ताल के पहले ही दिन गुरदासपुर समेत पूरे पंजाब में आयुष्मान आरोग्य केंद्र बंद रहे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं।

सीएचओ ने अपने-अपने जिलों के सिविल सर्जन कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस की प्रतियां जलाकर विरोध जताया।

सीएचओ यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुनील तरगोतरा ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के साथ वादाखिलाफी की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बैठकों के दौरान 5000 रुपये वेतन वृद्धि का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में इसे स्थायी वेतन में शामिल करने के बजाय इंसेंटिव के रूप में लागू कर दिया गया। इसके साथ ही कई ऐसी शर्तें जोड़ दी गईं, जिन्हें पूरा करना मुश्किल है।

यूनियन नेताओं ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में 5000 रुपये की स्थायी वेतन वृद्धि, लॉयल्टी बोनस, सीएचओ का नियमित कैडर मंजूर करना और वेतन व इंसेंटिव को मर्ज करना शामिल है।

चंबा-भरमौर मार्ग पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा

चलती गाड़ी पर विशाल पत्थर गिरने से पंजाब के श्रद्धालु की मौत

भारतेंदु संवाददाता, होशियारपुर। हिमाचल प्रदेश में चल रही मणिमहेश यात्रा के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में होशियारपुर जिले के एक श्रद्धालु की मौत हो गई। बुधवार तड़के चंबा-भरमौर मार्ग पर बग्गा के पास पहाड़ी से अचानक गिरे विशाल पत्थर की चपेट में श्रद्धालुओं की गाड़ी आ गई। हादसे में होशियारपुर निवासी माखन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ यात्रा कर रहे चार अन्य श्रद्धालु सुरक्षित बच गए।

मृतक की पहचान 40 वर्षीय माखन सिंह पुत्र शरवन सिंह निवासी गांव मलियां, डाकघर गढ़दीवाल, तहसील गढ़दीवाल, जिला होशियारपुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि माखन सिंह अपने साथियों के साथ मणिमहेश यात्रा के लिए निकले थे। बुधवार तड़के करीब तीन बजे जब उनकी गाड़ी चंबा-भरमौर मार्ग पर बग्गा के पास पहुंची, तभी पहाड़ी से एक भारी पत्थर टूटकर सीधे वाहन के सनरूफ पर जा गिरा।

पत्थर गिरने से गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सनरूफ टूटने के कारण माखन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश शर्मा ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। लगातार बारिश के कारण हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

संपत्ति विवाद में भाई द्वारा बहन पर हमला करने का आरोप

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर। छेहरटा के खंडवाला क्षेत्र स्थित न्यू मॉडल टाउन में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक पर अपनी ही सगी बहन पर लोहे की रॉड से हमला करने का आरोप लगा है। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामाजिक माध्यमों पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पीड़िता की पहचान मुंबई निवासी नवदीप कौर के रूप में हुई है। हमले में उसकी एक टांग में कई जगह फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद उसका ऑपरेशन किया गया। फिलहाल वह अस्पताल में उपचाराधीन है। जानकारी के अनुसार, नवदीप कौर जैसे ही घर से बाहर निकली, उसी समय एक कार वहां पहुंची। आरोप है कि कार से उतरने के बाद उसके छोटे भाई ने लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया।

गुरदासपुर के दो स्कूलों को बम धमकी पुलिस ने चलाया सघन तलाशी अभियान

भारतेंदु संवाददाता, गुरदासपुर। शहर के दो प्रतिष्ठित स्कूलों को ई-मेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। सूचना मिलते ही दोनों स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस ने पूरे परिसर में गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

धमकी की जानकारी मिलने के बाद गुरदासपुर के एसएसपी आदित्य खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने एंटी-सबोटाज टीमों और पुलिस अधिकारियों के साथ स्कूल परिसरों का निरीक्षण किया। पुलिस टीमों ने कक्षाओं, परिसर और आसपास के क्षेत्रों की बारीकी से जांच की, ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके।

तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। इसके बाद स्कूल प्रशासन, विद्यार्थियों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली। हालांकि, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है।

धमकी भरा ई-मेल भेजने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। पुलिस ई-मेल के स्रोत और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है। गौरतलब है कि करीब छह महीने पहले भी गुरदासपुर के कुछ नामी स्कूलों को इसी तरह की बम धमकी मिल चुकी है, जिसके बाद शहर में चिंता का माहौल बन गया था।

अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर पहुंचा पुलिस वाहन, जवान की लापरवाही की जांच शुरू

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। भगतांवाला फाटक के पास एक पुलिस प्रतिक्रिया वाहन अचानक रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वाहन चालक पुलिसकर्मी पर नशे की हालत में होने का आरोप लगाया। मामले का वीडियो सामने आने के बाद यह तेजी से सामाजिक माध्यमों पर वायरल हो गया और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा शुरू हो गई।

जानकारी के अनुसार, घटना के समय पुलिस का वाहन भगतांवाला रेलवे फाटक पार कर रहा था। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर सीधे रेलवे पटरियों के बीच जा पहुंचा। रेलवे ट्रैक पर पुलिस वाहन खड़ा देख आसपास मौजूद लोग मौके पर एकत्र हो गए। लोगों ने पुलिसकर्मी से सवाल किया कि वाहन ट्रैक पर कैसे पहुंच गया। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि यदि उस समय रेलवे ट्रैक से कोई ट्रेन गुजरती तो बड़ा हादसा हो सकता था।

वायरल वीडियो में पुलिस वाहन रेलवे लाइन के बीचों-बीच दिखाई दे रहा है। वीडियो में वाहन के अंदर मौजूद पुलिसकर्मी अपना नाम बलविंदर सिंह बताते हुए नजर आ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिसकर्मी की हालत सामान्य नहीं लग रही थी। लोगों का आरोप है कि वह ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में था। वीडियो में पुलिसकर्मी द्वारा गलती स्वीकार करने की बात भी सामने आई है।

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद अन्नगढ़ चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने स्थिति को नियंत्रित किया और रेलवे ट्रैक पर फंसे वाहन को हटवाकर यातायात व्यवस्था सामान्य कराई। कुछ समय के लिए रेलवे और सड़क यातायात प्रभावित रहा।

मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस विभाग ने विभागीय जांच शुरू कर दी है। एडीसीपी-एक विशालजीत सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में यदि सहायक उप निरीक्षक दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

आक्रोश — 27 करोड़ रुपये से अधिक बकाया भुगतान को लेकर किसानों में बढ़ी नाराजगी

बकाया राशि नहीं मिली तो राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे गन्ना किसान

भारतेंदु संवाददाता, जालंधर। पंजाब में गन्ना किसानों के लंबित भुगतान का मामला एक बार फिर गरमा गया है। भारतीय किसान यूनियन दोआबा ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की बकाया राशि का जल्द भुगतान नहीं किया गया तो 20 अगस्त से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। संगठन ने पहले चरण में फगवाड़ा में विशाल किसान रैली आयोजित करने का ऐलान किया है, जिसके बाद किसान सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे।

जालंधर स्थित पंजाब प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय किसान यूनियन दोआबा के प्रधान मनजीत सिंह राय ने कहा कि सरकार किसानों के साथ हुए समझौते को लागू कराने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके कारण उनमें भारी नाराजगी है।

मनजीत सिंह राय ने बताया कि वर्ष 2021-22 का लगभग 27 करोड़ 84 लाख रुपये का गन्ना भुगतान अभी तक लंबित है। इसके अलावा वर्ष 2025-26 के गन्ना सीजन में प्रति क्विंटल 68 रुपये 50 पैसे के हिसाब से मिलने वाली राशि और फगवाड़ा चीनी मिल की ओर से प्रति क्विंटल 41 रुपये 60 पैसे की काटी गई पेनल्टी का भुगतान भी किसानों को नहीं किया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सहकारी चीनी मिलों की ओर किसानों का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री की मौजूदगी में हुए समझौते के तहत किसानों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीं, लेकिन सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई। किसान यूनियन ने आंदोलन से पहले सरकार को एक और मौका देने का फैसला किया है। इसके तहत 10 अगस्त को संगठन का प्रतिनिधिमंडल कपूरथला के उपायुक्त को मांग पत्र और चेतावनी पत्र सौंपेगा। यदि इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 20 अगस्त को फगवाड़ा की दाना मंडी में बड़ी किसान रैली आयोजित की जाएगी।

गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो 20 अगस्त से किसान करेंगे आंदोलन

मनजीत सिंह राय ने कहा कि रैली के बाद आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला किसानों की बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को मजबूरी में संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। यदि आंदोलन के कारण आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, क्योंकि किसानों की मांगों का समाधान समय पर नहीं किया गया।

बृहस्पति की कृपा और सकारात्मक सोच के साथ सफलता की राह दिखाता गुरुवार

राजन कुमार शर्मा
स्वतंत्र लेखक

सप्ताह के सात दिनों में गुरुवार का विशेष महत्व माना जाता है। भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में गुरुवार को ज्ञान, आस्था और आध्यात्मिक उन्नति का दिन माना गया है। यह दिन विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है, जिन्हें ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, धर्म और सदाचार का प्रतीक माना जाता है। भारतीय ज्योतिष में भी बृहस्पति ग्रह को शुभ ग्रहों में स्थान दिया गया है, जो व्यक्ति के जीवन में सफलता, सम्मान और समृद्धि का कारक माना जाता है।

गुरुवार का संबंध केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन आत्मचिंतन, सीखने और जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देता है। प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में गुरुओं और ज्ञान का विशेष सम्मान रहा है। यही कारण है कि गुरुवार को गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर माना जाता है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। पूजा में पीले फूल, पीली मिठाई और पीले रंग की वस्तुओं का उपयोग शुभ माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि गुरुवार को श्रद्धा और नियमपूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।

भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति को शिक्षा, संतान, विवाह, धन और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा ग्रह माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है, उनमें ज्ञान, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता अधिक होने की मान्यता है। इसी कारण गुरुवार को बृहस्पति ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं।

गुरुवार का महत्व विद्यार्थियों के लिए भी विशेष है। ज्ञान और शिक्षा के प्रतीक इस दिन को अध्ययन, नई चीजें सीखने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुभ माना जाता है। आज के आधुनिक समय में भी गुरुवार हमें यह संदेश देता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार सीखते रहना आवश्यक है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को सही निर्णय लेने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाती है।

गुरुवार हमें गुरु के महत्व की भी याद दिलाता है। गुरु केवल शिक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं होता बल्कि वह जीवन को सही दिशा दिखाने वाला मार्गदर्शक होता है। माता पिता, शिक्षक और अनुभवी लोग जीवन में गुरु की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है।

समाज में गुरुवार को दान और सेवा के कार्यों के लिए भी शुभ माना जाता है। जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, भोजन कराना और अच्छे कार्य करना भारतीय परंपरा में पुण्य कार्य माने गए हैं। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक लाभ प्राप्त करना नहीं बल्कि समाज में सहयोग और मानवता की भावना को मजबूत करना भी है।

आधुनिक जीवन की भागदौड़ में व्यक्ति अक्सर मानसिक तनाव और चिंताओं से घिरा रहता है। ऐसे समय में गुरुवार जैसे दिन आत्ममंथन और सकारात्मक सोच विकसित करने का अवसर देते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में धन और सफलता के साथ ज्ञान, शांति और अच्छे विचारों का भी महत्व है।

आज के समय में जब तकनीक और भौतिक सुविधाएँ तेजी से बढ़ रही हैं, तब आध्यात्मिक मूल्यों की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। गुरुवार हमें संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जिसमें आधुनिक सोच के साथ संस्कार और नैतिकता का भी समावेश हो।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

हिरोशिमा की पीड़ा आज भी देती है चेतावनी 'युद्ध नहीं बल्कि शांति है मानवता का रास्ता'

डॉ. कमौरया मनोज
स्वतंत्र लेखक

विश्व हिरोशिमा दिवस प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन मानव इतिहास की उस दर्दनाक घटना की याद दिलाता है, जब 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया गया था। इस विनाशकारी हमले ने न केवल हजारों लोगों की जान ली, बल्कि पूरी दुनिया को परमाणु हथियारों के भयावह परिणामों से परिचित कराया। हिरोशिमा दिवस का उद्देश्य युद्ध और हिंसा के दुष्परिणामों को याद करना तथा विश्व में शांति, भाईचारे और परमाणु हथियारों के उन्मूलन का संदेश फैलाना है।

द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था। इस हमले में बड़ी संख्या में लोग तत्काल मारे गए और कई लोग विकिरण के प्रभाव से वर्षों तक पीड़ित रहे। कुछ ही दिनों बाद जापान के नागासाकी शहर पर भी परमाणु हमला किया गया। इन घटनाओं ने पूरी मानव सभ्यता को यह सोचने पर मजबूर किया कि युद्ध और विनाश की राह किसी भी देश या समाज के लिए लाभकारी नहीं हो सकती।

हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले का प्रभाव केवल उस समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों ने इसके दुष्परिणाम झेले। विकिरण के कारण लोगों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हुईं और पर्यावरण पर भी इसका गहरा असर पड़ा। हजारों परिवार उजड़ गए और शहर का बड़ा हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक विज्ञान का गलत उपयोग मानवता के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है।

विश्व हिरोशिमा दिवस हमें यह संदेश देता है कि विज्ञान और तकनीक का उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए। आज दुनिया के कई देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिससे वैश्विक सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। ऐसे में यह दिन सभी देशों को याद दिलाता है कि शांति और संवाद के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि बातचीत और सहयोग ही बेहतर रास्ता है।

इस दिवस पर दुनियाभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं में शांति से जुड़े कार्यक्रम, विचार गोष्ठियां और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को युद्ध के नुकसान और शांति के महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है। हिरोशिमा दिवस नई पीढ़ी को यह प्रेरणा देता है कि वे हिंसा से दूर रहकर विश्व में सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान दें।

आज के समय में जब कई क्षेत्रों में तनाव और संघर्ष देखने को मिल रहे हैं, तब हिरोशिमा दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। दुनिया को यह समझने की जरूरत है कि हथियारों की बढ़ती होड़ मानव सुरक्षा को मजबूत नहीं करती, बल्कि खतरे को बढ़ाती है। देशों के बीच आपसी विश्वास, सहयोग और कूटनीतिक प्रयासों से ही स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है।

भारत भी हमेशा विश्व शांति और परमाणु हथियारों के जिम्मेदार उपयोग की बात करता रहा है। भारतीय संस्कृति में शांति और सह-अस्तित्व की भावना को विशेष महत्व दिया गया है। भारत का मानना है कि विश्व के विकास के लिए संघर्ष की जगह सहयोग और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। हिरोशिमा दिवस इसी सोच को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है।

विश्व हिरोशिमा दिवस केवल एक ऐतिहासिक घटना की याद नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक चेतावनी भी है। यह दिन हमें बताता है कि युद्ध का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है और शांति का मार्ग ही मानव सभ्यता की प्रगति का आधार है। परमाणु हथियारों का खतरा समाप्त करने और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए दुनिया के सभी देशों को मिलकर प्रयास करने होंगे।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

'संपादकीय'

हार से सीखें, जीत की तैयारी

लोकतंत्र में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे जनता की भावनाओं, अपेक्षाओं और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन का आईना भी होते हैं। किसी भी बड़े राजनीतिक दल के लिए चुनावी जीत जितनी महत्वपूर्ण होती है, उतना ही जरूरी हार के कारणों को समझना भी होता है। बिहार की बांकीपुर और मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर भाजपा की हार को केवल दो उपचुनावों के सीमित परिणाम के रूप में देखना राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से उचित नहीं होगा। उपचुनाव कई बार स्थानीय समीकरणों, उम्मीदवारों और क्षेत्रीय मुद्दों से प्रभावित होते हैं, लेकिन वे जनता के बदलते रुझानों और संगठन की जमीनी स्थिति के संकेत भी देते हैं। इन दोनों सीटों के परिणाम भाजपा के लिए गंभीर आत्ममंथन का अवसर लेकर आए हैं।

भाजपा लंबे समय से अपने मजबूत संगठन, अनुशासित कार्यकर्ताओं और प्रभावी चुनावी रणनीति के लिए जानी जाती रही है। पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका कार्यकर्ता वर्ग रहा है, जो चुनावी समय में बूथ स्तर तक पहुंचकर संगठन को मजबूती प्रदान करता है। यही कारण है कि भाजपा ने कई राज्यों में कठिन परिस्थितियों में भी शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन किसी भी संगठन के लिए यह जरूरी होता है कि वह समय-समय पर अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं को समझता रहे। यदि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच किसी प्रकार की दूरी या असंतोष पैदा होता है, तो उसका असर चुनावी परिणामों में दिखाई दे सकता है।

हाल के समय में कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए, जिन पर भाजपा समर्थक वर्ग के एक हिस्से में चिंता और सवाल उठे। अयोध्या से जुड़े चंदा विवाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीतियों को लेकर उठे प्रश्न और नीट परीक्षा से संबंधित अनियमितताओं जैसे मामलों ने विशेष रूप से शिक्षित वर्ग और मध्यम वर्ग में चर्चा को जन्म दिया। भाजपा का पारंपरिक समर्थक वर्ग केवल राष्ट्रवाद या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर समर्थन नहीं करता, बल्कि वह सुशासन, पारदर्शिता, व्यवस्था की विश्वसनीयता और जवाबदेही को भी महत्व देता है। जब ऐसे मुद्दों पर सवाल उठते हैं, तो स्वाभाविक रूप से समर्थकों के बीच चिंतन की स्थिति बनती है।

नीट परीक्षा से जुड़ा विवाद लाखों छात्रों और अभिभावकों की उम्मीदों से जुड़ा विषय था। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर अत्यंत संवेदनशील होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। यदि किसी परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठते हैं, तो उसका प्रभाव केवल एक घटना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी व्यवस्था पर विश्वास को प्रभावित करता है। इसी तरह शिक्षा नीति से जुड़े निर्णयों पर भी युवाओं और शिक्षित समाज की नजर रहती है। भाजपा के लिए यह आवश्यक है कि वह इन वर्गों की चिंताओं को गंभीरता से सुने और विश्वास बहाली के लिए प्रभावी कदम उठाए।

बांकीपुर विधानसभा सीट का परिणाम भी भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। लंबे समय से मजबूत मानी जाने वाली सीटों पर भी राजनीतिक दलों को यह याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में कोई भी सीट स्थायी नहीं होती। जनता का समर्थन निरंतर प्रयास, संवाद और विश्वास के आधार पर मिलता है। यदि किसी संगठन में यह भावना आ जाए कि जीत निश्चित है, तो वही आत्मविश्वास धीरे-धीरे अति आत्मविश्वास में बदल सकता है। चुनावों में छोटी-छोटी अनदेखियां भी बड़े परिणाम दे सकती हैं। मतदाता हमेशा अपने प्रतिनिधियों से सक्रियता, उपलब्धता और संवेदनशील व्यवहार की उम्मीद करता है।

दतिया विधानसभा सीट का परिणाम भी भाजपा के लिए स्थानीय संगठन की भूमिका को रेखांकित करता है। किसी भी चुनाव में केवल सरकार की उपलब्धियां ही पर्याप्त नहीं होतीं। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनता से संपर्क, उम्मीदवार की छवि और क्षेत्रीय समस्याओं की समझ भी निर्णायक भूमिका निभाती है। यदि कार्यकर्ता उत्साह और विश्वास के साथ मैदान में नहीं उतरता, तो सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत भी कमजोर पड़ सकती है। संगठन की मजबूती केवल बैठकों और योजनाओं से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के सम्मान और भागीदारी से बनती है।

भाजपा को इन परिणामों को आलोचना के रूप में नहीं, बल्कि सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए। पार्टी का इतिहास बताता है कि उसने कई बार चुनावी झटकों से सीख लेकर अपनी रणनीति को बदला और मजबूत वापसी की। यही क्षमता किसी भी बड़े राजनीतिक संगठन की पहचान होती है। यदि पार्टी समय रहते जमीनी स्तर की समस्याओं को समझे, कार्यकर्ताओं की आवाज सुने और जनता के बीच दे, युवाओं और मध्यम वर्ग की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करे तथा पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर ठोस कदम उठाए, तो वर्तमान चुनौती भविष्य की सफलता का आधार बन सकती है।

-शिवांश धाकड़

कविता

लो हो गया मुंडन महोत्सव...?

संजय एम. तराणेकर,(कवि, लेखक व समीक्षक) इन्दौर-452011 (मध्यप्रदेश)

जनाब, अब अफवाहों का भी क्या कहना!
पहले लोग कहते थे— 'अक्ल बड़ी या भैंस ?'
अब नया सवाल— 'बाल बड़े या पंद्रह हजार ?'
किसी ने अधिकारी बन फोन पर ये कहा,
'सरकार मुंडन करवाओ, इनाम पाओ!'
बस यारों फिर क्या था, नाई की दुकान पर भीड़ ऐसी लगी,
मानो सरकारी नौकरी का फॉर्म भरना हो।
नाई बोला- 'इतनी खुशी तो शादी के
सीज़न में भी नहीं मिली, नाई की बांछें जमकर खिली, बोला- 'आज तो कैंची भी ओवरटाइम मांग रही है!'
जब सच्चाई सामने आई कि न सरकार, न योजना, न तहसीलदार- तब सबने सिर सहलाते हुए कहा, 'चलो... बाल तो वापस आ जाएंगे,
पर भरोसा अगली बार थोड़ा देर से आएगा!

तकनीक शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से गरीबी उन्मूलन की नई राह

धनी राम
स्वतंत्र लेखक

गरीबी किसी भी राष्ट्र के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक मानी जाती है। आर्थिक प्रगति के बावजूद जब समाज का एक बड़ा वर्ग मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रह जाता है तो विकास की तस्वीर अधूरी दिखाई देती है। गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पोषण और सम्मानजनक जीवन के अवसरों की कमी से भी जुड़ी होती है। इसलिए गरीबी उन्मूलन केवल आर्थिक योजना का विषय नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय जिम्मेदारी भी है।

भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में गरीबी उन्मूलन एक जटिल चुनौती है। देश ने पिछले कुछ दशकों में आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और सामाजिक योजनाओं के माध्यम से गरीबी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। करोड़ों लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और आर्थिक सहायता से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं। इसके बावजूद आज भी कई क्षेत्रों में गरीबी एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

गरीबी की सबसे बड़ी चुनौती रोजगार से जुड़ी हुई है। बड़ी संख्या में लोग आज भी स्थायी और सुरक्षित रोजगार के अभाव में जीवनयापन करने को मजबूर हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को नियमित आय, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्य परिस्थितियों का अभाव रहता है। जब व्यक्ति के पास पर्याप्त आय का साधन नहीं होता तो उसके परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

शिक्षा की कमी भी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। शिक्षा व्यक्ति को बेहतर रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करती है। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कई बच्चे आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से दूर हैं। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालयों की सुविधाओं, शिक्षकों की उपलब्धता और आधुनिक शिक्षा संसाधनों की कमी गरीबी को लंबे समय तक बनाए रखने में योगदान देती है।

स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी गरीबी बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण चुनौती है। गरीब परिवारों के लिए बीमारी का खर्च कई बार आर्थिक संकट का कारण बन जाता है। इलाज पर होने वाला अधिक खर्च परिवारों को कर्ज लेने के लिए मजबूर कर सकता है। इसलिए गरीबी उन्मूलन के लिए सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता आवश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की समस्या का एक बड़ा कारण कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भी है। छोटे और सीमांत किसानों को कई बार कम उत्पादन, मौसम की अनिश्चितता और बाजार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना, किसानों को आधुनिक तकनीक, उचित मूल्य और बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना गरीबी कम करने के लिए जरूरी है।

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना भी गरीबी उन्मूलन का महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। जब महिलाएँ शिक्षा और रोजगार से जुड़ती हैं तो परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। स्वयं सहायता समूहों और कौशल विकास कार्यक्रमों ने कई क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिनका उद्देश्य गरीब वर्गों को सहायता और अवसर प्रदान करना है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है राजनीतिक भाषा में मर्यादा और जिम्मेदारी का संतुलन

केशव शर्मा 'रसिक'
स्वतंत्र लेखक, गांव-कोटला, घुमारवीं।

लोकतंत्र में राजनीतिक दल और उनके नेता समाज को दिशा देने वाले महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से यह उम्मीद करती है कि वे हर परिस्थिति में धैर्य, संयम, मर्यादा और जिम्मेदारी का परिचय देंगे। लोकतंत्र केवल चुनाव प्रक्रिया तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें नेताओं का व्यवहार, भाषा, विचार और आचरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनता जिन लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनती है, उनसे अपेक्षा रहती है कि वे समाज में सकारात्मक वातावरण बनाएंगे और देशहित से जुड़े विषयों पर गंभीरता से कार्य करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में राजनीतिक संवाद का स्तर जिस प्रकार लगातार गिरता जा रहा है, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन गया है।

आज राजनीतिक मंचों, सार्वजनिक सभाओं, समाचार माध्यमों और सामाजिक माध्यमों पर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है, उसमें कई बार शालीनता और मर्यादा का अभाव दिखाई देता है। नेताओं के बीच व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, कटु टिप्पणियां, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग और भावनाओं को भड़काने वाले बयान लोकतांत्रिक संस्कृति को कमजोर करते हैं। राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन मतभेदों को दुश्मनी में बदलना उचित नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, व्यक्तियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए।

राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज में सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा देना भी उनका कर्तव्य है। सभी राजनीतिक दलों को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए ऐसी आचार संहिता सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे सार्वजनिक जीवन में भाषा और व्यवहार की मर्यादा बनी रहे। दलों को ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए जो तथ्यों, तर्कों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करें। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे विषयों पर गंभीर बहस लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। इसके विपरीत व्यक्तिगत हमले और अनावश्यक विवाद समाज में विभाजन पैदा करते हैं।

राजनीतिक दलों को यह भी समझना होगा कि उनके नेताओं के बयान केवल व्यक्तिगत विचार नहीं होते, बल्कि उनका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। जब कोई बड़ा नेता असंयमित भाषा का प्रयोग करता है तो उसके समर्थक भी उसी प्रकार की भाषा अपनाने लगते हैं। इससे सामाजिक वातावरण में तनाव बढ़ सकता है। इसलिए राजनीतिक संगठनों को समय समय पर अपने नेताओं को लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक जिम्मेदारियों और सार्वजनिक व्यवहार की मर्यादा के प्रति जागरूक करना चाहिए। गलत और भड़काऊ बयानों पर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करना भी राजनीतिक शुचिता के लिए जरूरी है।

मीडिया और सामाजिक माध्यमों की भूमिका भी राजनीतिक विमर्श को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण है। आज सूचना तेजी से लोगों तक पहुंचती है और किसी भी बयान का प्रभाव तुरंत समाज पर दिखाई देता है। कई बार सनसनी फैलाने वाले बयानों को अधिक महत्व मिल जाता है जबकि गंभीर और सकारात्मक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

युवा ऊर्जा, तकनीकी बदलाव और सामाजिक जिम्मेदारी से बनेगा विकसित भारत का भविष्य

हितेंद्र शर्मा
(साहित्यकार एवं स्तंभकार)
गांव व डाकघर कृमित, तहसील कुमारसैन जिला शिमला, हि.प्र. 172029

किसी भी राष्ट्र का भविष्य केवल सरकारों के निर्णयों से तय नहीं होता, बल्कि वह आने वाली पीढ़ियों के विचारों, संस्कारों और सपनों से आकार लेता है। आज भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ नई पीढ़ियाँ देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को नई दिशा दे रही हैं। एक ओर यह युवा वर्ग है जिसने डिजिटल दुनिया के साथ अपना बचपन और युवावस्था देखी है, वहीं दूसरी ओर वह पीढ़ी तैयार हो रही है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधुनिक तकनीक और आभासी दुनिया के साथ आगे बढ़ेगी।

हर पीढ़ी अपने समय की परिस्थितियों से बनती है। इसलिए किसी भी नई पीढ़ी को केवल पुराने अनुभवों के आधार पर परखना उचित नहीं है। समय बदलता है, चुनौतियाँ बदलती हैं और उनके समाधान खोजने के तरीके भी बदल जाते हैं। इतिहास गवाह है कि हर नई पीढ़ी ने अपने से पहले वाली पीढ़ी को कभी न कभी चिंतित किया है। जब रेडियो आया तो लोगों को बदलाव की चिंता हुई, फिर दूरदर्शन, इंटरनेट और अब आधुनिक तकनीक ने समाज के सामने नई संभावनाएँ और नई चुनौतियाँ रखी हैं।

आज की युवा पीढ़ी सूचना के विशाल संसार में जी रही है। उसके पास ज्ञान प्राप्त करने के पहले से कहीं अधिक साधन उपलब्ध हैं। वह सवाल पूछती है, तर्क करती है और किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले उसके प्रमाण तलाशती है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है क्योंकि जागरूक नागरिक ही मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। सूचना की अधिकता के समय में गलत खबरों, भ्रम और अधूरी जानकारी से बचने के लिए विवेक और समझ का विकास आवश्यक है।

आने वाली पीढ़ी तकनीक के और करीब होगी। उसके लिए मशीनों से संवाद करना, डिजिटल माध्यमों से सीखना और नई तकनीकों का उपयोग करना सामान्य बात होगी। संभव है कि भविष्य में शिक्षा, रोजगार और जीवन जीने के तरीके आज से बहुत अलग हों। कई पुराने काम बदलेंगे और नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन तकनीक के विकास के साथ मानवीय मूल्यों का महत्व कम नहीं होगा। ईमानदारी, संवेदना, सहयोग, सहनशीलता और जिम्मेदारी जैसे गुण हमेशा समाज की नींव बने रहेंगे।

भारत विश्व का सबसे युवा देश है। यह हमारे लिए अवसर भी है और चुनौती भी। करोड़ों युवाओं की ऊर्जा यदि सही दिशा में लगाई जाए तो भारत विकास की नई ऊँचाइयों को छू सकता है। लेकिन यदि युवाओं की शक्ति केवल विवाद, भ्रम और तात्कालिक प्रतिक्रियाओं तक सीमित रह गई तो यह ऊर्जा कमजोर पड़ सकती है। इसलिए युवाओं को ज्ञान, कौशल और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है। विचारों में अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन असहमति को शत्रुता में बदल देना समाज के लिए नुकसानदायक होता है। किसी युवा की अलग राय को तुरंत गलत ठहरा देना उचित नहीं है और न ही पुरानी पीढ़ी के अनुभवों को बेकार समझना सही है। नई सोच और पुराने अनुभवों का मेल ही समाज को मजबूत बनाता है।

भारत की यात्रा कई पीढ़ियों के योगदान से बनी है। स्वतंत्रता संग्राम की पीढ़ी ने त्याग और संघर्ष का मार्ग दिखाया। राष्ट्र निर्माण की पीढ़ी ने संस्थाओं को मजबूत किया। आर्थिक बदलाव की पीढ़ी ने नए अवसरों के द्वार खोले। अब नई पीढ़ियाँ तकनीक, नवाचार और वैश्विक सोच के माध्यम से भारत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी निभाएँगी।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

सादगी और सफलता की मिसाल

दीपिका कक्कड़
जन्म : 6 अगस्त 1986

दीपिका कक्कड़ भारतीय टेलीविजन जगत की जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपने अभिनय कौशल और सरल व्यक्तित्व के माध्यम से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है। उनका जन्म 6 अगस्त 1986 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ। बचपन से ही कला और अभिनय के प्रति उनकी रुचि रही, जिसने आगे चलकर उन्हें मनोरंजन जगत में कदम रखने के लिए प्रेरित किया।

दीपिका कक्कड़ ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन धारावाहिकों से की और धीरे धीरे अपनी मेहनत, प्रतिभा और भावनात्मक अभिनय के दम पर घर घर में लोकप्रिय हो गईं। उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि लोकप्रिय धारावाहिक ससुराल सिमर का से मिली, जिसमें उन्होंने सिमर भारद्वाज की भूमिका निभाई। इस किरदार ने उन्हें दर्शकों के बीच एक अलग पहचान दिलाई और वह टेलीविजन की पसंदीदा अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं।

दीपिका कक्कड़ की अभिनय शैली में भावनाओं की गहराई और किरदार के प्रति समर्पण साफ दिखाई देता है। उन्होंने अपने विभिन्न किरदारों के माध्यम से यह साबित किया कि वह केवल एक ही प्रकार की भूमिकाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अलग अलग परिस्थितियों और चरित्रों को प्रभावी ढंग से निभाने की क्षमता रखती हैं।

टेलीविजन के अलावा दीपिका कक्कड़ ने रियलिटी शो में भी अपनी अलग पहचान बनाई। वह बिग बॉस 12 की विजेता रहीं। इस शो में उनके शांत स्वभाव, धैर्य और मजबूत व्यक्तित्व को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस जीत ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया।

अभिनय के साथ साथ दीपिका अपने पारिवारिक जीवन और सकारात्मक सोच के लिए भी जानी जाती हैं। वह अपने प्रशंसकों के साथ सामाजिक माध्यमों के जरिए जुड़ी रहती हैं और अपने जीवन से जुड़े कई अनुभव साझा करती हैं। उनकी सादगी और पारिवारिक मूल्यों के प्रति लगाव उन्हें अन्य कलाकारों से अलग बनाता है। दीपिका कक्कड़ ने मनोरंजन क्षेत्र में अपनी मेहनत और निरंतर प्रयासों से सफलता हासिल की है।

'भारतेन्दु शिखर'

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रजनीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

न्यूज ब्रीफ

पत्नी और सास के उत्पीड़न के चलते युवक ने की आत्महत्या, मुकदमा दर्ज

एजेंसी, नोएडा। बादलपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी बहू पर शादी के लिए रखे 13.5 लाख रुपये चोरी करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि बहू ने चोरी की रकम से अपनी मां और अपने नाम एफडी कराई तथा एक फ्लैट भी बुक कराया। आरोप है कि मामले से परेशान होकर उसके बेटे हरेंद्र ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, शिकायत में बहू और उसकी मां पर रुपये हड़पने तथा बेटे को मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित ने बहू के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रा बंद, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक प्लान

एजेंसी, बागपत। कांवड़ यात्रा को देखते हुए बागपत पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। पुलिस ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। पुलिस के अनुसार मवीकलां कट बैरियर समेत जिले के कई स्थानों पर बैरिकेडिंग और डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है। कांवड़ यात्रियों को केवल निर्धारित मार्गों से ही जाने की अनुमति होगी। प्रमुख चौराहों और बैरियरों पर पुलिस बल तैनात कर निगरानी की जा रही है। एसपी सूरज कुमार राय ने श्रद्धालुओं से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार मार्गों पर यात्रा से दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है।

रायबरेली जेल में आजीवन कारावास काट रहे कैदी की हार्ट अटैक से मौत

एजेंसी, रायबरेली। रायबरेली जिला कारागार में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी सुग्गन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मंगलवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद वह अचेत होकर गिर पड़ा। जेल चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रतापगढ़ निवासी सुग्गन वर्ष 2011 के हत्या मामले में सजा काट रहा था। न्यायालय ने जनवरी 2025 में उसे आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच में मौत का कारण हृदयाघात बताया है। हालांकि, वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा। जेल प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है।

नोएडा में डेढ़ करोड़ रुपए की चांदी और सोने के जेवरात लूटने वाले पांच बदमाश गिरफ्तार

एजेंसी, नोएडा। नोएडा थाना बीटा-2 पुलिस ने ज्वेलर के मुनीम और कर्मचारी से करीब डेढ़ करोड़ रुपये के सोने-चांदी के आभूषण लूटने वाले पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए जेवरात, 12.138 किलोग्राम चांदी, घटना में इस्तेमाल कार, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, दो अगस्त को दिल्ली के ज्वेलर का मुनीम कार से सोने-चांदी के आभूषण लेकर आगरा जा रहा था। परी चौक के पास बदमाशों ने कार को ओवरटेक कर हादसे का बहाना बनाया और हथियारों के बल पर वारदात को अंजाम दिया। जांच में सामने आया कि गिरोह के सरगना कमलकांत ने कई दिनों तक रेकी कर पूरी योजना बनाई थी। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि बरामद सामान की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

यूपी विधान भवन स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठे सपा विधायक

किसानों, महिलाओं, युवाओं और छात्रों के मुद्दों को लेकर सपा ने सरकार पर साधा निशाना

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। विधान भवन परिसर स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने सपा विधायक धरने पर बैठ गए। मंगलवार को विधानसभा में हुए हंगामे के बाद निलंबित किए गए पार्टी विधायक इंजीनियर सचिन यादव के समर्थन में यह प्रदर्शन किया जा रहा है।

धरने में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय समेत कई विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी विधायकों के हाथों में सरकार विरोधी नारे लिखे पोस्टर दिखाई दिए। इन पोस्टरों में राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े आरोपों, किसानों की समस्याओं, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। सपा विधायकों ने सरकार पर जनहित के मुद्दों की

अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। उनका कहना है कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और विधानसभा में जन समस्याओं को उठाने का अवसर नहीं दिया जा रहा।

उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा। गौरतलब है कि मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सपा विधायक इंजीनियर सचिन यादव मुख्यमंत्री की तस्वीर वाला पोस्टर लेकर सदन के वेल में पहुंच गए थे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें कई बार अपनी सीट पर लौटने के लिए कहा, लेकिन स्थिति नहीं संभली।

इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। निलंबन की कार्रवाई के विरोध में सपा विधायकों ने मंगलवार को भी प्रदर्शन किया था। बुधवार को उन्होंने दोबारा धरना देकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को जनता की आवाज उठाने का अधिकार है और इसे रोका नहीं जाना चाहिए। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बुधवार को सदन में मंगलवार की घटना पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि संसदीय आचरण की सीमा लांघना संवैधानिक संस्था के लिए नुकसानदायक है।

उन्होंने सभी दलों के सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करने की अपील की थी। सपा नेताओं का कहना है कि वे किसानों, युवाओं, महिलाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण आम जनता परेशान है और विपक्ष का कर्तव्य है कि वह इन समस्याओं को सदन और सड़क दोनों जगह उठाए। विधानसभा परिसर में चल रहे इस प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। पुलिस और विधानसभा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

नगर पालिका अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार सीज, कूड़ा टेंडर में मिली अनियमितताएं

एजेंसी, हाथरस

उत्तर प्रदेश के हाथरस में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्वेता चौधरी के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए हैं। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की निविदा प्रक्रिया में कथित वित्तीय और प्रक्रियागत अनियमितताओं की जांच के बाद शासन स्तर से यह कार्रवाई की गई है। मंगलवार देर रात इस संबंध में आदेश जारी किए गए। मामले की शुरुआत 30 अगस्त 2024 को हुई थी, जब नगर पालिका के वार्ड-35 के सभासद मनीष अग्रवाल और वार्ड-34 के सभासद पं. सुनील अग्निहोत्री ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की निविदा प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 35 वार्डों में कूड़ा कलेक्शन के लिए निविदा और कार्यादेश जारी करने में नियमों की अनदेखी की गई, जिससे नगर पालिका को आर्थिक नुकसान हुआ। शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की थी। समिति ने निविदा प्रक्रिया, दस्तावेजों और संबंधित अभिलेखों की जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी। शासन स्तर पर रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा के बाद कार्रवाई का निर्णय लिया गया। जांच में प्रथम दृष्टया नगर पालिका अध्यक्ष को कर्तव्य पालन में चूक, प्रशासनिक

हाथरस पालिका अध्यक्ष के अधिकार अब जिला प्रशासन के पास रहेंगे

अनियमितता, पालिका निधि को नुकसान पहुंचाने और निधि के दुरुपयोग का दोषी माना गया।

इसके बाद उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 48(2) के तहत उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को सीज किया गया। अब नगर पालिका के वित्तीय और प्रशासनिक कार्य जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर स्तर से नीचे नहीं होने वाले अधिकारी द्वारा संचालित किए जाएंगे। अध्यक्ष श्वेता चौधरी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी।

मोटर बोट से बाढ़ के पानी से घिरे गांव पहुंची जिलाधिकारी, बचाव व राहत का लिया जायजा

एजेंसी, फर्रुखाबाद

जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने बुधवार को तहसील अमृतपुर के विकासखंड राजेपुर अंतर्गत बाढ़ प्रभावित ग्राम तीस राम की मड़ैया का निरीक्षण कर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रभावित परिवार तक समय पर और पारदर्शी तरीके से राहत सामग्री पहुंचाई जाए।

राजेपुर में बाढ़ हालात का जायजा, डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश।

डीएम ने राहत शिविरों, खाद्यान्न वितरण, पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था और पशुओं के चारे की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य जांच कराने के निर्देश दिए गए। बच्चों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने, क्लोरीन, एंटी वेनम और अन्य स्वास्थ्य सामग्री वितरित करने को कहा गया।

हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से पंचर मिस्त्री की मौके पर मौत

एजेंसी, मीरजापुर। मीरजापुर जिले के पड़री थाना क्षेत्र के डगमगपुर में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में पंचर मिस्त्री की मौत हो गई। बिजली केबल जोड़ने के दौरान वह हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही जान चली गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। अहरौरा थाना क्षेत्र के पटियटा खुटहा गांव निवासी अजहरुद्दीन (40) पिछले तीन वर्षों से डगमगपुर स्थित क्रेशर प्लांट के पास पंचर बनाने की दुकान चलाते थे। इसी काम से वह अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। बताया गया कि बुधवार सुबह करीब सात बजे दुकान की बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण वह केबल ठीक करने के लिए नीम के पेड़ पर चढ़े थे। इसी दौरान पेड़ के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

श्रावण में महादेव को समर्पित भोजपुरी गीत ने जगाई काशी की भक्ति भावना

एजेंसी, वाराणसी

श्रावण मास के पावन अवसर पर महादेव और काशी की आध्यात्मिक महिमा को समर्पित भोजपुरी भक्ति गीत 'हे भोले बाबा, मनवा के हमरा बनारस बना दह्य' रिलीज किया गया है। यह गीत भोजपुरी आईटी सेल के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जारी हुआ है। गीत के रचनाकार मनोज 'भावुक' ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

मनोज भावुक ने बताया कि यह गीत उनके लिए केवल एक भक्ति रचना नहीं, बल्कि बनारस के प्रति श्रद्धा, आस्था और जीवन दर्शन की संगीतमय अभिव्यक्ति है। गीत में काशी को केवल एक शहर नहीं, बल्कि भक्ति, मुक्ति और आत्मिक चेतना के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि यह गीत महादेव से एक प्रार्थना है, जिसमें मनुष्य के भीतर ऐसा बनारस बसने की कामना

की गई है, जहां सुख-दुख से ऊपर उठकर शिव की मस्ती, करुणा, संतुलन और शांति का अनुभव हो।

गीत में काशी विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष और लंका चौराहे जैसे आध्यात्मिक प्रतीकों का उल्लेख किया गया है। इस भक्ति गीत को सुरभि कश्यप और अर्जुन पांडेय ने स्वर दिया है, जबकि संगीत भोजपुरी फिल्म जगत के प्रसिद्ध संगीतकार रजनीश मिश्रा ने तैयार किया है।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में तीन कांवड़ियों की मौत

एजेंसी, गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में बुधवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में तीन कांवड़ियों की मौत हो गई। हादसा भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव कलछीना के पास दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ। बताया जा रहा है कि तीनों युवक बाइक से हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

पुलिस के अनुसार, हादसा सुबह करीब पांच बजे हुआ। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण) सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि मृतक तीनों कांवड़िये हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले थे। उनकी पहचान ज्ञानप्रकाश, राजकुमार और प्रदीप के रूप में हुई है। तीनों युवक एक ही गांव के निवासी थे और धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार जा रहे थे।

हादसे की जानकारी मिलने के बाद मृतकों के परिजनों में मातम छा गया। गांव में भी शोक का माहौल है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है, ताकि टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान की जा सके। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी हुई है और जल्द कार्रवाई का दावा किया है।

योगी सरकार की पहल से कानपुर में पोल्ट्री व्यवसाय को मिली नई रफ्तार

एजेंसी, कानपुर

उत्तर प्रदेश सरकार की कुक्कुट विकास नीति का असर कानपुर नगर जिले में साफ दिखाई दे रहा है। जिले में पोल्ट्री पालन व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है और वर्तमान में 14 बड़े पंजीकृत फार्म व्यावसायिक स्तर पर संचालित हो रहे हैं। इन फार्मों से प्रतिदिन करीब 50 हजार से 60 हजार अंडों का उत्पादन किया जा रहा है। चौबेपुर, बिल्हौर, बिठूर, कल्याणपुर और पतारा क्षेत्रों में स्थापित पोल्ट्री फार्म स्थानीय बाजार की मांग को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

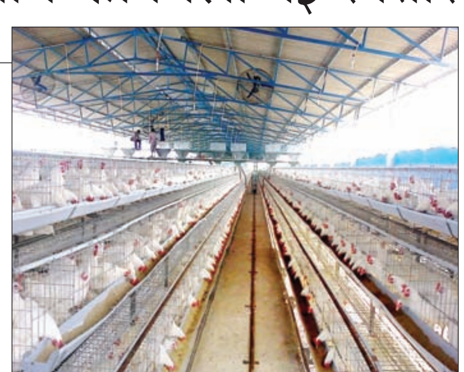

कुक्कुट विकास नीति से कानपुर में बढ़ा उत्पादन, युवाओं को मिल रहे रोजगार अवसर

जिले में ही बड़ी मात्रा में अंडों का उत्पादन होने से दूसरे जिलों और राज्यों पर निर्भरता कम हुई है। साथ ही लोगों को ताजा अंडे उचित कीमतों पर उपलब्ध हो रहे हैं। पोल्ट्री व्यवसाय से ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और श्रमिकों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता, आसान ऋण और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इस क्षेत्र में निवेश बढ़ा है। कालोरा एग्रो फार्म, आरआर एग्रो, डीजीएनएस, टीडी एग्रो और राज पोल्ट्री फार्म जैसे संस्थान आधुनिक तकनीकों के जरिए उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं। मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी अनुराग सिंह ने बताया कि पशुपालन विभाग फार्मों को तकनीकी सहायता, टीकाकरण और योजनाओं का लाभ उपलब्ध करा रहा है।

सरकार का लक्ष्य पोल्ट्री उद्योग को मजबूत बनाकर किसानों और युवाओं की आय बढ़ाना है। इससे कानपुर में पोल्ट्री क्षेत्र को नई पहचान मिल रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है।

देवरिया में चाकू लगने से किशोर की मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप

एजेंसी, देवरिया। देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र में गांव के विवाद के दौरान चाकू लगने से घायल 16 वर्षीय किशोर सागर उर्फ भूवर की बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। किशोर की मौत के बाद परिजनों ने निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। मृतक सागर भटनी थाना क्षेत्र का निवासी था। परिजनों के मुताबिक मंगलवार शाम गांव में हुए विवाद के दौरान उस पर चाकू से हमला कर दिया गया था। गंभीर हालत में उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर किया गया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले जाने की सलाह दी थी।

परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान निजी एंबुलेंस चालक ने उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहां किशोर का ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। परिजनों के अनुसार डॉक्टरों की सलाह पर करीब 18 यूनिट रक्त की व्यवस्था की गई, लेकिन चार से पांच घंटे चले ऑपरेशन के बाद भी सागर की जान नहीं बच सकी। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस निगरानी बनाए हुए है और आरोपियों की तलाश जारी है।

सोनभद्र में बस की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत, दो घायल

एजेंसी, सोनभद्र

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मार्ग स्थित मधुपुर फ्लाईओवर के पास हुआ। यहां एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक ही बाइक पर सवार चार लोग हादसे का शिकार हो गए।

जानकारी के अनुसार, परही गांव निवासी सुभाष यादव (27) अपने रिश्तेदार के यहां सुकृत गया था। बुधवार को वह वहां से तेतरा देवी (70) और सात वर्षीय आर्यन तथा उसकी मां के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर मधुपुर की ओर जा रहा था। दोपहर करीब 11:30 बजे जैसे ही बाइक मधुपुर फ्लाईओवर के पास पहुंची, तभी पीछे से तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी और मौके से निकल गई। हादसे में बाइक चला रहे सुभाष यादव और तेतरा देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, सात वर्षीय आर्यन और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई और लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधुपुर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद आर्यन की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना करने वाले वाहन की पहचान के लिए जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहन चालक तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

मर्यादा सपा विधायकों के हंगामे के बाद अध्यक्ष ने दी नसीहत, लोकतंत्र में असहमति के साथ मर्यादा भी जरूरी

संसदीय आचरण की परिधि लांघना इस संस्था के लिए अत्यंत हानिकारक है : सतीश महाना

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंगलवार को सदन में हुए हंगामे को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि संसदीय आचरण की परिधि को लांघना लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण संस्था के लिए बेहद हानिकारक है। सदन की गरिमा और संवैधानिक मर्यादाओं को बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है।

सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद पीठ से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि मंगलवार को सदन में जो कुछ हुआ, वह संवैधानिक संस्था के लिए उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संवाद, सहमति और असहमति लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन असहमति व्यक्त करते समय भाषा और व्यवहार की मर्यादा का ध्यान रखना आवश्यक है।

महाना ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को सदन में उठाना है। वहीं सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सदन के माध्यम से जनता तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि सदन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब माहौल असहज हो जाता है, लेकिन पिछले साढ़े चार वर्षों में विधानसभा की कार्यवाही लगातार चली है।

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी विपक्ष के सदस्य कई बार सदन के बीचों-बीच यानी बेल में आए हैं, लेकिन समय और परिस्थिति को देखते हुए अपनी बात रखने के बाद वापस अपनी सीटों पर चले गए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध का अधिकार है, लेकिन विरोध का तरीका संसदीय परंपराओं के अनुरूप होना चाहिए।

विधानसभा अध्यक्ष ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान में समस्या नहीं होती, बल्कि समस्या व्यक्तियों के आचरण में हो सकती है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में उनका लगातार प्रयास रहा है कि सदन की कार्यवाही संविधान की भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप संचालित हो। महाना ने बताया कि उन्होंने पहली बार विधानसभा सदस्यों को उनकी योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया।

उन्होंने कहा कि विधानसभा में डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता और शिक्षाविद जैसे कई योग्य सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। विधायिका किसी भी संस्था से कम नहीं है और इसकी गरिमा बनाए रखना सभी का दायित्व है। उन्होंने मंगलवार की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक सदस्य के आचरण से उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी दुख पहुंचा। उन्होंने कहा कि बार-बार समझाने के बावजूद भाषा की मर्यादा का पालन नहीं किया गया। बाहर जाकर भी उसी प्रकार की बातें की गईं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव और सीख को सदन के हित में लगाने का प्रयास किया है, लेकिन यदि सदस्य अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो संवैधानिक संस्था का विकास संभव नहीं होगा।

नासी की सदस्यता के लिए बीएचयू के तीन संकाय सदस्य चयनित, विश्वविद्यालय परिवार में हर्ष

एजेंसी, वाराणसी

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। विश्वविद्यालय के तीन संकाय सदस्यों का वर्ष 2026 के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया (नासी), प्रयागराज की प्रतिष्ठित सदस्यता के लिए चयन किया गया है। इस उपलब्धि से बीएचयू परिवार में खुशी और गर्व का माहौल है।

शोध और नवाचार में बीएचयू की बड़ी उपलब्धि, तीन प्रोफेसर नासी के लिए चयनित

नासी की ओर से जारी चयनित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार, पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजीव प्रताप सिंह और वनस्पति विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सतीश कुमार वर्मा को 'कृषि एवं पादप विज्ञान' श्रेणी में सदस्यता के लिए चुना गया है। वहीं, सेंटर फॉर एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन एंड सर्जरी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विभव गौतम का चयन 'जैव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी' श्रेणी में किया गया है।

अनुसंधान और नवाचार की मिसाल बना बीएचयू, तीन शिक्षकों को बड़ी सफलता

बीएचयू के जनसंपर्क कार्यालय ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय के तीन शिक्षकों का नासी जैसी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था की सदस्यता के लिए चयन होना संस्थान के लिए गौरव की बात है। यह उपलब्धि विश्वविद्यालय में हो रहे उच्चस्तरीय शोध, वैज्ञानिक नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक गतिविधियों को दर्शाती है। नासी देश की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक है, जो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को मान्यता प्रदान करती है। इसकी सदस्यता वैज्ञानिक समुदाय में विशेष सम्मान मानी जाती है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस उपलब्धि पर चयनित तीनों संकाय सदस्यों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि वे भविष्य में भी अपने शोध कार्यों से विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे।

बीएचयू लगातार अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और इस चयन ने विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है। यह उपलब्धि बीएचयू के वैज्ञानिक योगदान और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान को दर्शाती है। विश्वविद्यालय भविष्य में भी शोध और नवाचार के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहेगा।

पानीपत बच्ची दुष्कर्म और हत्या मामले में हाई कोर्ट ने दो दोषियों की फांसी की सजा की रद्द

गंभीर प्रक्रियागत कमियों के चलते हाई कोर्ट ने फांसी की सजा रद्द कर मामले को पुनः ट्रायल के लिए भेजा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पानीपत के उरलाना कलां में 12 वर्षीय बच्ची के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को दी गई फांसी की सजा रद्द कर दी है। अदालत ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए सत्र अदालत भेजते हुए स्पष्ट किया कि यह निर्णय आरोपितों को दोषमुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि निष्पक्ष और कानूनसम्मत न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

जस्टिस अनूप चितकारा और जस्टिस रमेश चंदर डिमरी की खंडपीठ ने कहा कि ट्रायल के दौरान कई गंभीर प्रक्रियागत कमियां सामने आईं, जिनके कारण दोषसिद्धि और सजा को यथावत बनाए रखना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि किसी भी आपराधिक मुकदमे में कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन होना आवश्यक है और यदि उसमें गंभीर त्रुटियां रह जाएं तो निष्पक्ष न्याय प्रभावित हो सकता है।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में जांच अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने माना कि जांच और मुकदमे की प्रक्रिया में ऐसी खामियां रहीं, जिनसे अभियोजन का मामला प्रभावित हुआ।

इसलिए पूरे मामले की दोबारा सुनवाई आवश्यक है, ताकि सभी पक्षों को कानून के अनुसार अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिल सके और उपलब्ध साक्ष्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि फांसी की सजा रद्द करने का अर्थ आरोपितों को बरी करना नहीं है। मामला अब संबंधित सत्र अदालत में नए सिरे से चलेगा, जहां सभी साक्ष्यों, गवाहों और कानूनी प्रक्रियाओं की दोबारा समीक्षा की जाएगी। इसके बाद अदालत कानून के अनुरूप नया निर्णय सुनाएगी।

यह मामला वर्ष 2018 का है। अभियोजन के अनुसार 13 जनवरी 2018 की शाम करीब छह बजे उरलाना कलां की 12 वर्षीय बच्ची घर से कूड़ा फेंकने निकली थी। आरोप है कि प्रदीप और सागर उर्फ कल्लू उसे अगवा कर प्रदीप के घर ले गए, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में व्यापक आक्रोश फैल गया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 18 फरवरी 2022 को ट्रायल कोर्ट ने प्रदीप और सागर उर्फ कल्लू को अपहरण, हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।

रोहित धनखड़ हत्याकांड में 8 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं, खाप ने लगाया जाम

भारतेन्दु संवाददाता, रोहतक

रोहतक जिले के गांव हमायूंपुर निवासी बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की हत्या के मामले में आठ महीने बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों और ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है। बुधवार को रोहित के परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर खाप पंचायत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग लघु सचिवालय पहुंचे और प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान रोहित की मां संतोष भावुक हो गईं। आंखों में आंसू लिए उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे की हत्या का न्याय चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि परिवार को इंसाफ मिल सके। खाप पंचायत ने आरोप लगाया कि घटना को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। नाराज लोगों ने सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। अधिकारियों ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने कहा कि हत्याकांड की जांच जारी है और आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रोहित धनखड़ की हत्या के बाद से ही परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। अब खाप पंचायत के आंदोलन के बाद एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आ गया है।

न्यूज ब्रीफ

हरियाणा में अपराधियों के खिलाफ चला विशेष अभियान ट्रैकडाउन

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। आगामी स्वतंत्रता दिवस 2026 के मद्देनजर हरियाणा पुलिस ने प्रदेशभर में 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, फिरौती, स्नैचिंग, अपहरण और अवैध हथियारों जैसे गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना है। एक से तीन अगस्त तक चले अभियान में पुलिस ने 903 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनमें 103 गंभीर मामलों में 139 आरोपित पकड़े गए, जबकि अन्य मामलों में भी बड़ी संख्या में अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने 43 आर्म्स एक्ट, 19 हत्या के प्रयास, 16 हत्या, सात लूट, तीन डकैती, छह स्नैचिंग, चार फिरौती और तीन अपहरण के मामलों में कार्रवाई की। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने बताया कि अभियान अपराधियों में कानून का भय बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा है।

हरियाणा सरकार ने सभी विभागों से मांगा बैंक खातों का पांच साल का रिकार्ड

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा में करीब 650 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के बाद राज्य सरकार ने सभी विभागों से पिछले पांच वित्तीय वर्षों के बैंक खातों का विस्तृत ब्यौरा तलब किया है। वित्त विभाग ने वर्ष 2021-22 से 2025 26 तक संचालित डीडीओ बैंक खातों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। विभागों से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक संचालित खातों की संख्या, कुल व्यय और शेष राशि का विवरण मांगा गया है। इसके अलावा 50 प्रतिशत से कम, 50 से 99 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत खर्च वाले खातों की अलग-अलग जानकारी देने को कहा गया है। जिन खातों से कोई खर्च नहीं हुआ, उनके बैंक, खाता संख्या, संबंधित अधिकारी, विभाग और क्लोजिंग बैलेंस का पूरा रिकॉर्ड भी वित्त विभाग ने मांगा है।

पानीपत में बोलेरो की टक्कर से फ्लाईओवर से गिरे कारोबारी की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत। पानीपत के जाटल रोड रेलवे ओवरब्रिज पर मंगलवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक कारोबारी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार और बेकाबू बोलेरो ने स्कूटी और बाइक सवारों को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान विराट नगर निवासी कारोबारी संजीव ग्रोवर के रूप में हुई है। वह रात को स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आई बोलेरो ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि संजीव ओवरब्रिज से करीब 70 फीट नीचे जा गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका उपचार जारी है।

लुवास में शिक्षकों को बड़ी सौगात, करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत मिली पदोन्नति

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास) में करियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत शिक्षकों को पदोन्नति दी गई। कुलपति प्रो. (डॉ.) विनोद कुमार वर्मा ने बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में पदोन्नत शिक्षकों को आदेश पत्र सौंपे। सीएएस के तहत विभिन्न विभागों के आठ शिक्षकों को पदोन्नति मिली, जबकि डॉ. बिस्वा रंजन महारणा को वेटरिनरी पैरासिटोलॉजी विभाग में सीनियर साइंटिस्ट बनाया गया। कुलपति ने शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की सफलता में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पदोन्नत शिक्षक शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों में बेहतर योगदान देंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि सभी पदोन्नतियां निर्धारित नियमों और यूजीसी मानकों के अनुसार की गई हैं।

हिसार में 15 हमलावरों का जानलेवा हमला, डेयरी संचालक की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार

हिसार के सूर्यनगर क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते पशु डेयरी संचालक जीवन (32) की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना मंगलवार सुबह रेलवे लाइन के पास हुई, जहां 12 से 15 हमलावरों ने कथित तौर पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, करीब डेढ़ माह पहले घर के बाहर हौद में तूड़ी डालने को लेकर मृतक का पड़ोसी रमेश पंडित से विवाद हुआ था। परिजनों का आरोप है कि इसी रंजिश के चलते हमलावरों ने सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से पहले जीवन का एक मिनट 12 सेकेंड का वीडियो भी

हत्या से पहले बनाया गया पीड़ित का वीडियो जांच का बना अहम हिस्सा।

सामने आया है। वीडियो में वह बताता है कि जब वह सुबह बाइक पर गोबर डालने जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे रास्ते में रोककर बाइक से नीचे गिरा दिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया।

वीडियो में वह यह भी कहता सुनाई देता है कि उसके हाथ-पैर टूट गए हैं और उसकी हालत बेहद गंभीर है। सूचना मिलने पर एचटीएम थाना पुलिस और सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

आठ महीने की शादी के बाद एसडीओ की पत्नी की संदिग्ध मौत

भारतेन्दु संवाददाता, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सेक्टर-3 में एक एसडीओ की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। विवाहिता का शव घर में पंखे से लटका मिला। उसकी शादी करीब आठ महीने पहले ही हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से एक नैपकिन पर अंग्रेजी में 'ढ्ढ'रू हश्वह्ल ङ्खद्गह्यद्य' लिखा मिला है, जिसे जांच का हिस्सा बनाया गया है। वहीं, मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पति के किसी अन्य महिला से संबंध थे और उनकी बेटी की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया।

हरियाणा के 16 जिलों में झमाझम बारिश, उमस से राहत और खरीफ फसलों को बड़ी संजीवनी मिली

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार

हरियाणा के 16 जिलों में मंगलवार को हुई झमाझम बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दिलाई। लगातार हो रही वर्षा से जहां मौसम सुहावना हो गया, वहीं धान, नरमा और बाजरा जैसी खरीफ फसलों को भी नया जीवन मिला है। हालांकि प्रदेश में मानसून के दो महीने बीतने के बावजूद वर्षा का कुल घाटा अभी भी बना हुआ है और अधिकांश जिले सामान्य बारिश से पीछे चल रहे हैं।

बारिश का असर पानीपत, अंबाला, हिसार, फतेहाबाद, हांसी, गुरुग्राम, चरखी दादरी और अन्य जिलों में देखने को मिला। कई शहरों में सड़कों और बाजारों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। पानीपत में मूसलधार बारिश के कारण जीटी रोड पर करीब दो घंटे तक यातायात प्रभावित रहा, जबकि अंबाला में बाजारों और नगर निगम कार्यालय परिसर में पानी भर गया।

गुरुग्राम, हिसार और बहादुरगढ़ के कई निचले इलाकों में भी जलभराव की स्थिति बनी रही। कृषि विशेषज्ञों और किसानों के अनुसार यह बारिश खरीफ फसलों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। खेतों में नमी बढ़ने से धान, नरमा और बाजरा की फसलों को पर्याप्त लाभ मिलेगा और सिंचाई की आवश्यकता भी कम होगी। फतेहाबाद के टोहाना और जाखल क्षेत्रों में अच्छी बारिश के बाद किसानों ने राहत की सांस ली।

मौसम विभाग के अनुसार चार से छह अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। विभाग का कहना है कि यदि आगामी दिनों में भी इसी तरह बारिश होती रही तो वर्षा घाटे में कमी आ सकती है। हालांकि अब तक केवल फरीदाबाद और पलवल में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इसके विपरीत 21 जिलों में 7 से 68 प्रतिशत तक बारिश की कमी बनी हुई है।

धार्मिक आस्था से जुड़ी सामग्री गटर में मिलने पर संगत ने उठाई कड़ी कार्रवाई की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र के गोचरान क्षेत्र में खुले गटर से सिख और हिंदू धर्म से जुड़ी धार्मिक सामग्री मिलने के बाद क्षेत्र में रोष का माहौल बन गया। गटर से गुटका साहिब, जपजी साहिब, सिख गुरुओं के पोस्टर तथा हिंदू देवी-देवताओं के चित्र मिलने की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में सिख संगत और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने धार्मिक सामग्री को सम्मानपूर्वक गटर से बाहर निकाला और इसे किसी शरारती अथवा असामाजिक तत्व की हरकत बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

धार्मिक सामग्री मिलने के बाद बड़ी संख्या में संगत मौके पर पहुंची, सम्मानपूर्वक सामग्री बाहर निकाली।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है तथा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि धार्मिक सामग्री वहां फेंकने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है।

सिख संगत के प्रतिनिधियों ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों और देवी-देवताओं के चित्रों के साथ इस प्रकार का व्यवहार लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि घटना के जिम्मेदार लोगों की जल्द पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि समाज में सौहार्द और आपसी भाईचारे को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की गई है।

प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मामले को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी तथा दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

पेड़ से लटका मिला किसान का शव, बहन को भेजा सुसाइड नोट

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत

पानीपत के मतलौडा थाना क्षेत्र के गांव कवी के खेत में एक किसान का शव पेड़ से फंदे पर लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान करनाल जिले के गांव मोर माजरा निवासी 35 वर्षीय संदीप के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, आत्महत्या से पहले संदीप ने अपनी बहन को व्हाट्सऐप पर एक सुसाइड नोट भेजा था, जिसमें उसने अपनी मानसिक पीड़ा का उल्लेख किया था।

मृतक के भाई सोनू ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि एक अगस्त को गांव के सरपंच राजेंद्र, उसके बेटे विकास और भतीजे पुनीत ने संदीप के साथ खेत में मारपीट की थी। आरोप है कि तीनों ने संदीप को बांधकर रॉड और डंडों से पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद संदीप ने करनाल की बल्ला पुलिस चौकी में शिकायत भी दर्ज कराई थी। परिजनों का कहना है कि शिकायत के बाद भी आरोपित लगातार समझौते के लिए दबाव बना रहे थे और धमकियां दे रहे थे। उनका आरोप है कि इसी मानसिक प्रताड़ना और भय के कारण संदीप ने आत्मघाती कदम उठाया। आत्महत्या से पहले बहन को भेजे गए सुसाइड नोट को भी पुलिस ने जांच में शामिल किया है।

पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर सरपंच राजेंद्र, उसके बेटे विकास और भतीजे पुनीत के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुसाइड नोट, परिजनों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है तथा जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सुशील कुमार के बाद सतिंदर मलिक बने लगातार दो अंडर-17 विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय पहलवान

भारतेन्दु संवाददाता, हांसी

हरियाणा के हिसार जिले के गांव सुल्तानपुर के 17 वर्षीय पहलवान सतिंदर मलिक ने अजरबैजान के बाकू में आयोजित अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय कुश्ती इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। 60 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग के फाइनल मुकाबले में उन्होंने रूस के सर्गेई कर्मरियन को 3-1 से हराकर अपना विश्व खिताब सफलतापूर्वक बरकरार रखा।

इस उपलब्धि के साथ सतिंदर मलिक लगातार दो अंडर-17 विश्व खिताब जीतने वाले भारत के दूसरे पुरुष फ्रीस्टाइल पहलवान बन गए हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने हासिल की थी। सतिंदर की इस ऐतिहासिक जीत से हरियाणा सहित पूरे देश में खुशी की लहर है और खेल जगत ने उनकी शानदार सफलता पर बधाई दी है। सतिंदर का यह सफर आसान नहीं रहा।

विश्व मंच पर स्वर्णिम दांव लगाकर इतिहास रचने वाले युवा पहलवान सतिंदर मलिक।

विश्व चैंपियनशिप से करीब दो महीने पहले अभ्यास के दौरान उनकी गर्दन में चोट लग गई थी, जिससे उनका प्रशिक्षण प्रभावित हुआ। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कड़ी मेहनत व मजबूत इच्छाशक्ति के दम पर फिटनेस हासिल कर विश्व मंच पर दमदार वापसी की।

फाइनल मुकाबले में सतिंदर ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और रूस के पहलवान को ज्यादा अवसर नहीं दिए। तकनीकी कौशल और बेहतरीन रणनीति के दम पर उन्होंने 3-1 से मुकाबला जीतकर लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। सतिंदर मलिक की इस सफलता को भारतीय कुश्ती के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। उनकी जीत ने एक बार फिर साबित किया कि हरियाणा देश को विश्वस्तरीय पहलवान देने में अग्रणी है।

खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सतिंदर इसी तरह मेहनत और अनुशासन बनाए रखते हैं तो भविष्य में वह एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर भी भारत के लिए पदक जीतने की क्षमता रखते हैं। उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन गई है।

दीपक लांबा बने एचपीसीसी समन्वय एवं संपर्क केंद्र प्रभारी

राव नरेंद्र सिंह ने नियुक्ति पत्र सौंपकर संगठन मजबूत करने का जताया भरोसा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एचपीसीसी) ने संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दीपक लांबा को एचपीसीसी समन्वय एवं संपर्क केंद्र का प्रभारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के हरियाणा प्रभारी संजय दत्त से विचार-विमर्श के बाद की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने दीपक लांबा को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उनके उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं और विश्वास व्यक्त किया कि वह संगठन को नई ऊर्जा और बेहतर समन्वय प्रदान करेंगे।

राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक अधिक प्रभावी, सक्रिय और मजबूत बनाने के लिए समन्वय व्यवस्था को सुदृढ़ करना समय की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दीपक लांबा को यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक अनुभव, समर्पण और कार्यकुशलता के आधार पर दीपक लांबा इस जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे तथा संगठन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाएंगे।

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि एचपीसीसी समन्वय एवं संपर्क केंद्र संगठन के विभिन्न स्तरों के बीच संवाद और समन्वय का प्रमुख माध्यम होगा। प्रभारी के रूप में दीपक लांबा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों, वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश स्तरीय प्रकोष्ठों, जिला कांग्रेस समितियों, ब्लॉक कांग्रेस समितियों, मंडल समितियों और बूथ समितियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने का कार्य करेंगे। इसके माध्यम से संगठनात्मक गतिविधियों को गति मिलेगी और सभी इकाइयों के बीच नियमित संवाद सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले संगठनात्मक कार्यक्रमों, अभियानों, बैठकों, निर्देशों और जनसंपर्क गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी समन्वय एवं संपर्क केंद्र की होगी। दीपक लांबा इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे ताकि प्रत्येक कार्यक्रम निर्धारित समय पर और तय रणनीति के अनुरूप सफलतापूर्वक संचालित हो सके।

राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि समन्वय एवं संपर्क केंद्र केवल संवाद का माध्यम ही नहीं होगा, बल्कि संगठनात्मक गतिविधियों की नियमित समीक्षा और रिपोर्टिंग का भी प्रमुख केंद्र रहेगा। दीपक लांबा संपर्क केंद्र के दैनिक संचालन, विभिन्न इकाइयों के साथ समन्वय, संचार व्यवस्था, कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग तथा उनके अनुपालन की पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व और पर्यवेक्षण करेंगे। इससे संगठन के विभिन्न स्तरों पर कार्यों की प्रगति की नियमित निगरानी हो सकेगी और आवश्यकतानुसार समय पर सुधारात्मक कदम भी उठाए जा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत होता है। यदि शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक प्रभावी संवाद और समन्वय बना रहे तो संगठन की कार्यक्षमता स्वतः बढ़ती है। इसी सोच के साथ समन्वय एवं संपर्क केंद्र की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि प्रत्येक कार्यकर्ता तक संगठन की योजनाएं और निर्देश समय पर पहुंच सकें तथा उनकी प्रतिक्रिया भी नेतृत्व तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, जिला एवं ब्लॉक स्तर के नेताओं, संगठन के कार्यकर्ताओं और पार्टी सदस्यों से आह्वान किया कि वे दीपक लांबा को उनकी नई जिम्मेदारियों के निर्वहन में पूरा सहयोग दें। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास, बेहतर समन्वय और अनुशासित संगठनात्मक कार्यशैली के माध्यम से कांग्रेस को प्रदेश में और अधिक मजबूत एवं जनोन्मुख बनाया जा सकता है।

जंतर-मंतर प्रदर्शन विवाद के बीच डीएमईओ सुल्तान सिंह निलंबित, सरकार ने दिए कार्रवाई के आदेश

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड में तैनात जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी (डीएमईओ) सुल्तान सिंह को हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में बोर्ड के मुख्य प्रशासक धर्मेंद्र सिंह द्वारा जारी आदेश 3 अगस्त को जारी किए गए थे, जो बुधवार को सार्वजनिक हुए। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पंचकूला स्थित हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक का कार्यालय निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

सरकारी आदेश में निलंबन का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। हालांकि प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का कथित समर्थन करने की शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद यह कार्रवाई की गई। इन चर्चाओं के बीच सुल्तान सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार और मनगढ़ंत बताया है। सुल्तान सिंह का कहना है कि उन्होंने किसी भी छात्र आंदोलन या राजनीतिक प्रदर्शन का समर्थन नहीं किया। उनके अनुसार कुछ लोगों ने गलत तथ्यों के आधार पर उनकी शिकायत की, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और सच्चाई सामने आएगी। सुल्तान सिंह पहले भी विवादों में रह चुके हैं। वर्ष 2020 में हिसार मार्केट कमेटी में सचिव रहते हुए भाजपा नेता एवं टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के साथ उनका विवाद काफी चर्चित हुआ था। बालसमंद में निरीक्षण के दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद सोनाली फोगाट ने सार्वजनिक रूप से उनकी सैंडल से पिटाई कर दी थी।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुआ था और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज कराए थे। फिलहाल सरकार की ओर से निलंबन के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। मामले को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं जारी हैं, जबकि विभागीय कार्रवाई और संभावित जांच पर सभी की नजर बनी हुई है। फिलहाल विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी।

न्यूज ब्रीफ

अनशन खत्म होने के बाद भी जंतर-मंतर आंदोलन की यादों में डूबे सोनम वांगचुक

एजेंसी, नई दिल्ली। सोनम वांगचुक ने अनशन समाप्त होने के 12 दिन बाद भी जंतर-मंतर आंदोलन की यादों को साझा किया है। उन्होंने कहा कि जब भी वह अपनी आंखें बंद करते हैं तो प्रदर्शन के दौरान बिताए गए पल उनकी आंखों के सामने आ जाते हैं। वांगचुक ने आंदोलन से जुड़े अनुभवों को भावुक कर देने वाला बताया और कहा कि जंतर-मंतर पर लोगों का समर्थन और संघर्ष हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा कि अनशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आवाज उठाई गई थी, वे अभी भी महत्वपूर्ण हैं। सोनम वांगचुक लंबे समय से विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय विषयों को लेकर अपनी बात रखते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान मिले लोगों के सहयोग और समर्थन ने उन्हें नई ऊर्जा दी। वांगचुक के अनुसार, जंतर-मंतर पर बिताया गया समय उनके जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों में शामिल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा और समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास जारी रहेंगे।

गुटखा देने में देरी पर दुकानदार को मारी गोली, आईटीबीपी हवलदार गिरफ्तार

एजेंसी, नई दिल्ली। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गुटखा देने में देरी होने पर एक आईटीबीपी हवलदार ने दुकानदार को गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घायल दुकानदार को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपी आईटीबीपी में हवलदार के पद पर तैनात है और वह छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था। किसी बात को लेकर दुकानदार और आरोपी के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद उसने कथित रूप से पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दी। गोली लगने से दुकानदार घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली हाई अलर्ट, लाल किले की सुरक्षा में 12 हजार जवान तैनात

एजेंसी, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने लाल किले और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा योजना तैयार की है। 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, जिसमें करीब 24 हजार मेहमानों के शामिल होने की संभावना है। सुरक्षा को देखते हुए लगभग 12 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आतंकी संगठनों से संभावित खतरे और अचानक होने वाले विरोध प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई गई है। कई सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां मिलकर समारोह की निगरानी करेंगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और खुफिया इनपुट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

गाजियाबाद में ड्रग्स गिरोह का खुलासा छात्रों को ऑनलाइन सप्लाई होता था नशा

एजेंसी, गाजियाबाद। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने कौस्तुभ उर्फ कार्तिक को गिरफ्तार कर उसके पास से 13 लाख रुपये नकद, 894 ग्राम गांजा और दो ग्राम कोकीन बरामद की है। आरोपी व्हाट्सएप के जरिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल के छात्रों से नशे का ऑर्डर लेता था। भुगतान यूपीआई से लिया जाता था और पोर्टर के माध्यम से सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने दो अन्य तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 21 किलो गांजा बरामद हुआ है। आरोपी बिहार से मादक पदार्थ लाकर दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई करता था।

नोएडा एयरपोर्ट को मिलेगी नई उड़ान, दिल्ली हरियाणा से जोड़ेगा हाईटेक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे

सेक्टर-94 से यमुना एक्सप्रेसवे तक बनेगा नया लिंक, एयरपोर्ट पहुंचने में समय की होगी बचत

एजेंसी, नई दिल्ली

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली और हरियाणा से सीधे जोड़ने के लिए एक बड़ी सड़क परियोजना की तैयारी पूरी कर ली गई है। एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 50 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का रूट डिजाइन फाइनल कर लिया गया है। इस परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तैयार करेगा।

इसकी अनुमानित लागत करीब चार हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है। प्रस्तावित एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली, नोएडा और हरियाणा के प्रमुख क्षेत्रों से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच आसान हो जाएगी। रूट डिजाइन तैयार होने के बाद इसे नोएडा प्राधिकरण को भेजा गया है।

योजना के अनुसार यह एक्सप्रेसवे नोएडा के सेक्टर-94 से शुरू होकर यमुना क्षेत्र की 120 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़ेगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एयरपोर्ट तक आने-जाने वाले यात्रियों को तेज और सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध कराना है। वर्तमान में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से एयरपोर्ट पहुंचने में लगने वाले समय को कम करने के लिए बेहतर सड़क नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली एनसीआर के यात्रियों को नोएडा एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक और तेज मार्ग मिलेगा। इससे मौजूदा सड़कों पर यातायात दबाव भी कम होने की संभावना है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्षेत्र के बड़े विकास प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। एयरपोर्ट के संचालन के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। ऐसे में बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। एनएचएआई द्वारा तैयार किए जा रहे इस एक्सप्रेसवे से नोएडा एयरपोर्ट को दिल्ली और हरियाणा के प्रमुख हिस्सों से सीधा संपर्क मिलेगा। इससे यात्रियों के साथ-साथ कारोबारियों और निवेशकों को भी फायदा होने की उम्मीद है।

उद्यमियों को राहत, एनओसी-लाइसेंस प्रक्रिया सरल करेगी दिल्ली सरकार

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार कारोबार को आसान, पारदर्शी और तेज बनाने के उद्देश्य से 'दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026' लाने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्तावित बिल के जरिए उद्यमियों को विभिन्न अनुमति, एनओसी और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देने की योजना है।

सरकार का उद्देश्य है कि दिल्ली में व्यापार शुरू करने और संचालित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। नए प्रावधानों के तहत प्रशासनिक प्रक्रियाओं को कम करने, ऑनलाइन व्यवस्था को मजबूत करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बिल में कई ऐसे बदलाव शामिल किए गए हैं, जिनसे कारोबारियों को समय की बचत होगी और कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि आसान नियमों से नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रस्तावित कानून के तहत उद्यमियों को लाइसेंस और अन्य अनुमतियों के लिए लंबी प्रक्रिया से राहत मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि व्यापार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने से छोटे कारोबारियों, स्टार्टअप और निवेशकों को फायदा मिलने की संभावना है।

टर्बुलेंस में 300 फीट नीचे गिरा विमान यात्रियों ने सुनाया खौफनाक अनुभव

एजेंसी, नई दिल्ली

फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई2379 मंगलवार को उड़ान के दौरान अचानक तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। इस दौरान विमान की ऊंचाई करीब 300 फीट तक नीचे चली गई, जिससे यात्रियों और क्रू सदस्यों में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद कई यात्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए इसे जिंदगी का सबसे डरावना पल बताया।

यात्रियों के मुताबिक, विमान अचानक जोर-जोर से हिलने लगा और कुछ समय के लिए ऐसा महसूस हुआ कि नियंत्रण खो गया है। कई लोगों ने बताया कि उस समय उन्हें लगा कि शायद अब बचना मुश्किल है। यात्रियों ने कहा कि तेज झटकों के कारण केबिन में डर का माहौल बन गया था और कई लोग घबरा गए थे। एयर इंडिया के अनुसार, फ्लाइट में कुल 137 यात्री सवार थे, जिनमें तीन शिशु भी शामिल थे। इसके अलावा विमान में आठ क्रू सदस्य मौजूद थे। टर्बुलेंस के दौरान कुछ यात्रियों और केबिन क्रू को चोटें आईं, लेकिन पायलट ने स्थिति को संभालते हुए विमान को सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार लिया।

एयरलाइन ने बताया कि घटना के बाद विमान सामान्य रूप से आगे बढ़ा और करीब सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंच गया। सभी यात्रियों और क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। विमानन विशेषज्ञों के अनुसार, टर्बुलेंस उड़ान के दौरान मौसम संबंधी कारणों से आने वाली सामान्य घटना है, लेकिन तेज टर्बुलेंस कई बार यात्रियों के लिए बेहद डरावना अनुभव बन जाता है।

फर्जी कॉल सेंटर से चल रहा था साइबर फ्रॉड पुलिस ने छह को दबोचा

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। द्वारका जिले की पुलिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर में छापा मारकर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह कॉल सेंटर के जरिए लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बना रहा था। पुलिस को लंबे समय से इस फर्जी कॉल सेंटर के संचालन की जानकारी मिल रही थी। सूचना के आधार पर टीम ने इंदौर में दबिश दी और मौके से आरोपियों को पकड़ लिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी बड़े स्तर पर साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और ठगी के तरीकों की जानकारी जुटा रही है।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश से मौसम बदला विकास मार्ग पर जलभराव से लगा जाम

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली का एक्यूआई 64, 'संतोषजनक' श्रेणी में दर्ज।

राजधानी दिल्ली और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कई इलाकों में बुधवार सुबह से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण जहां लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली, वहीं कई स्थानों पर जलभराव और यातायात जाम की समस्या भी सामने आई। विकास मार्ग पर बारिश के बाद वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

बारिश के चलते सड़क पर पानी जमा होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। सुबह और दोपहर के समय कार्यालय जाने वाले लोगों को जाम में फंसना पड़ा। यातायात पुलिस की ओर से व्यवस्था संभालने के प्रयास किए गए, लेकिन बारिश और जलभराव के कारण कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य के आसपास रहा।

दिन के समय अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले समय में भी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं तथा कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के बावजूद लोगों को उमस से पूरी तरह राहत नहीं मिली। वातावरण में नमी अधिक होने के कारण गर्मी का अहसास बना रहा। कई इलाकों में लोग बारिश से बचने के लिए सड़कों पर रुकते नजर आए।

वहीं, दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 64 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में कमी आई है।

दो हजार घरों पर नजर, बिना कनेक्शन बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगो पर होगी सख्ती

एजेंसी, साहिबाबाद

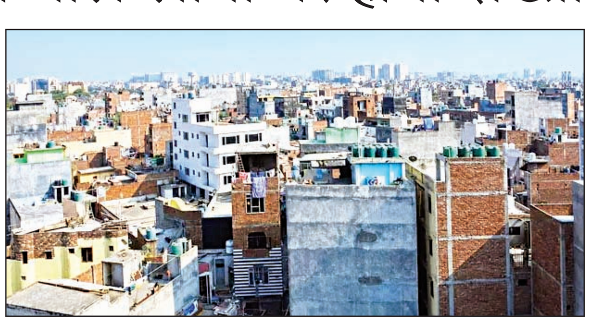

खोड़ा क्षेत्र में बिना बिजली कनेक्शन के बिजली का उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ विद्युत निगम अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। बिजली चोरी रोकने और राजस्व नुकसान को कम करने के लिए विद्युत निगम एक सितंबर से खोड़ा में घर-घर सर्वे अभियान शुरू करेगा। इसके लिए पांच विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो क्षेत्र के प्रत्येक घर की जांच करेंगी।

विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार खोड़ा में करीब 52 हजार मकान हैं। इनमें से लगभग 50 हजार घरों में ही वैध बिजली कनेक्शन हैं, जबकि करीब दो हजार घरों में अभी तक कनेक्शन नहीं लिया गया है। ऐसे घरों में बिजली के अवैध इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है, जिससे निगम को हर महीने लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सर्वे के दौरान टीम यह जांच करेगी कि घरों में बिजली का उपयोग किस माध्यम से किया जा रहा है। यदि किसी घर में बिना कनेक्शन बिजली का इस्तेमाल पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बिजली चोरी के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दरअसल, खोड़ा क्षेत्र में बिजली कनेक्शन को लेकर नगर पालिका और विद्युत निगम के आंकड़ों में अंतर सामने आने के बाद अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। जांच में सामने आया कि कई घरों में बिजली का उपयोग तो हो रहा है, लेकिन उनके पास वैध कनेक्शन नहीं हैं।

विद्युत निगम का कहना है कि अभियान का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सभी उपभोक्ताओं को वैध बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना भी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे बिजली चोरी से बचें और जल्द से जल्द वैध कनेक्शन लेकर बिजली का इस्तेमाल करें।

मेट्रो के बाद अब बस सेवा में कदम, डीएमआरसी ने शुरू की हाइड्रोजन बसें

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने राजधानी में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू की है। यह सेवा दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई है। हाइड्रोजन बसें प्रदूषण कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। इन बसों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे यात्रियों को आरामदायक सफर मिल सकेगा। डीएमआरसी की यह पहल स्वच्छ ऊर्जा आधारित सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का प्रयास है। बस सेवा के निर्धारित मार्ग, स्टॉप और किराये की जानकारी यात्रियों के लिए जारी की गई है। इससे दिल्ली में हरित परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

करोड़ों का कारोबार करने वाले शिवचरण गुप्ता को आखिरी विदाई में नहीं मिली बेटियों की मौजूदगी

एजेंसी, नई दिल्ली

एक बेटी ने वीडियो कॉल पर देखी अंतिम विदाई।

वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग कारोबारी शिवचरण गुप्ता का निधन हो गया। जीवनभर परिवार के लिए मेहनत करने वाले शिवचरण गुप्ता को अंतिम समय में अपनों की मौजूदगी नसीब नहीं हुई। उनकी तीनों बेटियों ने अंतिम संस्कार में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि, एक बेटी ने आर्थिक सहयोग भेजकर वीडियो कॉल के माध्यम से अंतिम विदाई देखी।

जानकारी के अनुसार, शिवचरण गुप्ता कभी मुंबई में कपड़ा कारोबार से जुड़े थे और उन्होंने मेहनत के बल पर अपना व्यवसाय खड़ा किया था। परिवार की खुशियों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, लेकिन उम्र के अंतिम पड़ाव में उन्हें वृद्धाश्रम में रहना पड़ा। वृद्धाश्रम से जुड़े लोगों के अनुसार, शिवचरण गुप्ता की तबीयत खराब होने के बाद उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार की जानकारी उनकी बेटियों को दी गई, लेकिन किसी ने मौके पर पहुंचने में असमर्थता जताई। इसके बाद सामाजिक संस्था के सदस्यों ने आगे बढ़कर उनका अंतिम संस्कार किया। बताया गया कि एक बेटी ने अंतिम संस्कार के लिए रुपये भेजे और वीडियो कॉल के जरिए पिता की अंतिम विदाई देखी। वहीं, अन्य बेटियां भी किसी कारणवश शामिल नहीं हो सकीं।

इस घटना ने बुजुर्गों की देखभाल और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुजुर्ग माता-पिता को जीवन के आखिरी दौर में परिवार के साथ और भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है।

शिवचरण गुप्ता की कहानी समाज के लिए एक संदेश है कि आर्थिक सफलता के साथ पारिवारिक संस्कार और रिश्तों की अहमियत भी बनाए रखना जरूरी है। सामाजिक संस्था के सदस्यों ने उन्हें सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद सुरक्षा समीक्षा वाली जनहित याचिका की खारिज

अदालत की टिप्पणी- संसदीय लोकतंत्र अपनी मजबूत संवैधानिक व्यवस्था के तहत चलता है

एजेंसी, नई दिल्ली

संसद सुरक्षा याचिका पर कोर्ट की दो टूक, संस्थागत व्यवस्था पर जताया भरोसा

संसद की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को स्पष्ट शब्दों में कहा कि संसदीय लोकतंत्र को किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि संसद और उसकी सुरक्षा व्यवस्था एक मजबूत संवैधानिक ढांचे के तहत संचालित होती है और इसके लिए निर्धारित संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं।

याचिका में संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि केवल आशंकाओं के आधार पर ऐसी याचिकाएं दाखिल नहीं की जानी चाहिए। संसद देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है और उसकी सुरक्षा को लेकर संबंधित एजेंसियां पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करती हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और कार्यप्रणाली को समझना जरूरी है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संसदीय लोकतंत्र किसी व्यक्ति के सुझावों या निर्देशों से नहीं चलता, बल्कि संविधान और स्थापित नियमों के अनुसार संचालित होता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता से यह भी सवाल किया कि संसद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाई गई चिंताओं के पीछे ठोस आधार क्या है। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा से जुड़े मामलों में विशेषज्ञ एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं और हर विषय को न्यायिक हस्तक्षेप के जरिए हल नहीं किया जा सकता।

गौरतलब है कि संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समय-समय पर समीक्षा होती रही है। संसद परिसर की सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, प्रवेश व्यवस्था, निगरानी उपकरणों और जांच प्रक्रिया को लगातार मजबूत किया जाता रहा है।

याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका के माध्यम से संसद की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और इसे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अदालत ने संसद सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर संस्थागत व्यवस्था को प्राथमिकता दी है। अदालत ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज को लेकर अनावश्यक हस्तक्षेप उचित नहीं है।

इससे पहले भी न्यायालय कई मामलों में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जनहित याचिकाओं का उपयोग वास्तविक जनहित के मुद्दों के लिए किया जाना चाहिए। अदालतों में दाखिल याचिकाओं में ठोस तथ्य और पर्याप्त आधार होना आवश्यक है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद संसद सुरक्षा से जुड़ी जनहित याचिका पर विराम लग गया है।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर टिप्पणी विवाद में सौरभ दास का जवाब

एजेंसी, नई दिल्ली

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लेकर की गई अपनी टिप्पणियों पर उठे विवाद के बीच सौरभ दास ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा से संबंधित अपनी टिप्पणियों को डिलीट नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी ओर से कही गई बातें सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर थीं। सौरभ दास ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह की गलत या भ्रामक जानकारी साझा करने का प्रयास नहीं किया। उनका कहना है कि उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए, वे उपलब्ध दस्तावेजों और सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर रखे गए थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टिप्पणियों को हटाने की बात सही नहीं है।

गौरतलब है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लेकर की गई टिप्पणियों के बाद यह मामला चर्चा में आया था। इस मामले में सौरभ दास के बयानों को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की छवि को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर अपनी बात रखना था। उन्होंने कहा कि आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी सार्वजनिक दस्तावेज का हिस्सा होती है और उसी के आधार पर उन्होंने अपनी राय व्यक्त की थी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी विषय पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन तथ्यों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। मामले को लेकर न्यायिक और कानूनी हलकों में भी चर्चा बनी हुई है। वहीं, सौरभ दास के बयान के बाद अब सभी की नजर आगे की कार्रवाई पर है। उन्होंने अपने पक्ष को दोहराते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियां तथ्यों पर आधारित थीं और उन्होंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। इस पूरे मामले में संबंधित पक्षों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विवाद के बीच सौरभ दास ने एक बार फिर अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह अपनी बात सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही रखते हैं।

सौरभ दास ने आगे कहा कि किसी भी सार्वजनिक विषय पर चर्चा करते समय तथ्यों और दस्तावेजों की विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य न्यायपालिका या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने केवल उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर अपनी राय व्यक्त की थी।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी विषय को लेकर सवाल उठते हैं तो उनका समाधान तथ्यों और उचित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि उनकी टिप्पणियां किसी व्यक्तिगत दुर्भावना से प्रेरित नहीं थीं, बल्कि सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी के आधार पर थीं। मामले को लेकर कानूनी विशेषज्ञों और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच भी चर्चा जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायपालिका से जुड़े मामलों में टिप्पणी करते समय भाषा और तथ्यों की सावधानी रखना बेहद जरूरी होता है।

आतंक से पीड़ित परिवारों के लिए सरकार का बड़ा मानवीय फैसला

पीड़ित परिवारों को मिला न्याय, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन का भरोसा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को आतंकवादी हिंसा में मारे गए निर्दोष नागरिकों के परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आतंक पीड़ित परिवारों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देना केवल रोजगार उपलब्ध कराने की पहल नहीं है, बल्कि यह न्याय, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कांफ्रेंस सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पहल उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण है, जो लंबे समय से सहायता और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे।

उपराज्यपाल ने कहा कि किसी अपने को खोने के दर्द की भरपाई न तो नौकरी कर सकती है और न ही आर्थिक सहायता। लेकिन ऐसे परिवारों के साथ खड़ा होना सरकार की संवैधानिक, नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित प्रत्येक पात्र परिवार तक सरकारी सहायता पहुंचाई जाएगी और कोई भी पीड़ित परिवार उपेक्षित नहीं रहेगा।

> **उपराज्यपाल** ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और नागरिक प्रशासन मिलकर आतंकवाद के पूरे तंत्र को खत्म करने के लिए अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखना केवल सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है।

मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता आतंकवाद प्रभावित परिवारों को सम्मान के साथ जीवन दोबारा शुरू करने का अवसर देने की है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि स्थायी अवसर और आत्मनिर्भर बनने का रास्ता चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नियुक्ति मिलने से इन परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और वे अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। उपराज्यपाल ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित परिवारों के कल्याण के लिए सहायता का सिलसिला जारी रहेगा।

नया संवैधानिक अध्याय

उपराज्यपाल ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर के इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक बदलावों के बाद दशकों से चले आ रहे भेदभाव को खत्म किया गया और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि इसके बाद केंद्र सरकार के 890 से अधिक कानून जम्मू-कश्मीर में लागू हुए, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। उन्होंने बताया कि आतंकवाद के कारण जम्मू-कश्मीर में हजारों लोगों की जान गई है और कई परिवारों ने लंबे समय तक पीड़ा झेली है।

जम्मू में अवैध घुसपैठ नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

जम्मू। जम्मू संभाग में समय-समय पर पकड़े गए रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के मामलों ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने अवैध प्रवेश के नेटवर्क को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। जांच में सामने आया है कि कुछ लोग दलालों की मदद, फर्जी दस्तावेजों और परिवहन साधनों के जरिए जम्मू तक पहुंचे। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, रोहिंग्या नागरिकों के भारत आने का एक प्रमुख रास्ता बांग्लादेश रहा है। कई मामलों में सीमा पार करने के बाद उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने में कथित दलालों की भूमिका सामने आई है। जम्मू पुलिस ने दस्तावेज सत्यापन अभियान के दौरान कई रोहिंग्या नागरिकों को हिरासत में लिया था। नवंबर 2023 में जम्मू में पकड़ी गई छह बांग्लादेशी महिलाओं के मामले में जांच के दौरान एक दलाल की मदद से उनके पहुंचने की बात सामने आई थी। वहीं, कुछ मामलों में विदेशी नागरिकों को आधार कार्ड और डोमिसाइल जैसे भारतीय दस्तावेज उपलब्ध करवाने में स्थानीय लोगों की भूमिका की भी जांच हुई है। सुरक्षा एजेंसियां अब किरायेदारों के सत्यापन, संदिग्ध श्रमिकों की पहचान और दस्तावेजों की जांच पर विशेष ध्यान दे रही हैं।

शीर कॉलोनी में तलाशी के दौरान मिला विस्फोटक जखीरा

सोपोर में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, 45 मोर्टार शेल बरामद

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। सोपोर के शीर कॉलोनी इलाके में चलाए गए संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 45 मोर्टार शेल बरामद किए हैं। बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है।

अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। बुधवार सुबह सुरक्षाबलों को इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। इसके बाद विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जवानों ने तरजू पुलिस थाना क्षेत्र के घट निंगली और शीर कॉलोनी इलाकों में घेराबंदी कर घर-घर तलाशी ली।

इस संयुक्त अभियान में सोपोर पुलिस की विशेष अभियान इकाई एसओजी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 177वीं बटालियन और सेना की 52 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान शामिल थे। सुरक्षाबलों ने इलाके को पूरी तरह घेरने के बाद संदिग्ध स्थानों की जांच शुरू की। इसी दौरान शीर कॉलोनी निवासी शाहबाज अजीज डार पुत्र अब्दुल अजीज डार के रिहायशी मकान से 45 मोर्टार शेल बरामद किए गए। बरामद किए गए सभी मोर्टार शेल को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। अधिकारियों के मुताबिक यह गोले पुराने भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें अभी भी विस्फोटक क्षमता मौजूद होने की संभावना को देखते हुए बम निरोधक दस्ते ने पूरी सावधानी के साथ उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में गोला-बारूद वहां कैसे पहुंचा और इसके पीछे किसी आतंकी संगठन या अन्य नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है। पुलिस कई पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

सुरक्षाबलों ने नाकाम की बड़ी साजिश

अधिकारियों के अनुसार बरामदगी के बाद इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षाबल यह भी जांच कर रहे हैं कि ये मोर्टार शेल किसी पुराने ठिकाने से जुड़े हैं या फिर हाल ही में यहां पहुंचाए गए थे। जांच एजेंसियां आसपास के इलाकों में भी संदिग्ध गतिविधियों और संपर्कों की जानकारी जुटा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को कमजोर करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुरक्षाबल संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान और निगरानी बढ़ा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि बरामद गोला-बारूद का इस्तेमाल किसी साजिश के लिए किया जाना था या यह किसी पुराने भंडार का हिस्सा था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रही हैं।

अनुच्छेद 370 हटने के सात साल बाद बदला कश्मीर, विकास और सुरक्षा में दिखा बड़ा परिवर्तन

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। सात साल बाद घाटी का माहौल पहले की तुलना में काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। अलगाववाद का प्रभाव कमजोर हुआ है, आतंकी हिंसा में कमी आई है और राजनीतिक मुद्दों का स्वरूप भी बदल गया है। कभी कश्मीर में अलगाववादी राजनीति का केंद्र रही हुर्रियत कांफ्रेंस का प्रभाव अब काफी सीमित हो चुका है। हुर्रियत के प्रमुख मीरवाइज मौलवी उमर फारूक अब खुद को हुर्रियत चेयरमैन के रूप में पेश नहीं करते। वहीं, कुछ पूर्व अलगाववादी नेता मुख्यधारा की राजनीति की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी से जुड़े कई नेताओं ने भी भारतीय संविधान में विश्वास जताते हुए नए राजनीतिक मंच की शुरुआत की है।

महबूबा पर टिप्पणी को लेकर पीडीपी ने गिरिराज सिंह पर साधा निशाना

◆ **वहीद पारा ने बयान को आपत्तिजनक और गैरजिम्मेदाराना बताया**

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। पीडीपी नेता वहीद पारा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की उस टिप्पणी की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को कथित तौर पर आतंकवादी बताया था। पारा ने इस बयान को आपत्तिजनक, गैरजिम्मेदाराना और केंद्रीय मंत्री के पद की गरिमा के खिलाफ बताया। वहीद पारा ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि महबूबा मुफ्ती जैसी वरिष्ठ राजनीतिक नेता के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक असहमति से आगे बढ़कर पूर्वाग्रह और असहिष्णुता को दर्शाता है।

जम्मू-कश्मीर के हक में राजौरी से उठी आवाज

भारतेंदु संवाददाता, राजौरी। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सातवीं वर्षगांठ पर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर राजौरी में प्रदर्शन किया गया। बुधवार को राजौरी के अंबेडकर पार्क में विधायक थन्नामंडी मुजफ्फर इकबाल खान के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया।

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने और क्षेत्र के विशेष अधिकारों की बहाली की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना जनता की भावनाओं और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की लंबे समय से यह मांग रही है कि क्षेत्र को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए।

जम्मू के पूर्ण राज्य दर्जे की मांग को लेकर धर्मयुद्ध अभियान शुरू

शिवसेना यूबीटी ने संवैधानिक संरक्षण और अधिकारों की मांग दोहराई

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) जम्मू-कश्मीर इकाई और राष्ट्रीय हिंदू कल्याण संगठन ने मंगलवार को जम्मू में प्रदर्शन कर क्षेत्र को अलग पूर्ण राज्य का दर्जा देने और अनुच्छेद 371 के तहत विशेष संवैधानिक संरक्षण देने की मांग उठाई। संगठनों ने महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा स्थल पर प्रदर्शन करते हुए जम्मू धर्मयुद्ध अभियान की शुरुआत की।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी जम्मू-कश्मीर के प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के राजनीतिक बदलावों के समय जम्मू की जनता से क्षेत्रीय भेदभाव खत्म करने, संतुलित विकास और सम्मान बहाल करने का वादा किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सात साल बाद भी जम्मू राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक उपेक्षा का सामना कर रहा है।

साहनी ने कहा कि जम्मू के लोगों को अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र के जनसांख्यिकीय संतुलन, स्थानीय संसाधनों और आर्थिक हितों पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बाहरी कंपनियों और ठेकेदारों के बढ़ते प्रभाव से स्थानीय लोगों के रोजगार और व्यापार पर असर पड़ रहा है।

उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि जम्मू को अलग पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और अनुच्छेद 371 के तहत विशेष संरक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय भूमि, सरकारी नौकरियों, व्यापार और प्राकृतिक संसाधनों पर मूल निवासियों के अधिकार सुरक्षित हो सकेंगे।

कुलगाम हत्याकांड पर पनुन कश्मीर ने जताया रोष

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। पनुन कश्मीर ने कुलगाम में दो हिंदू मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की है। संगठन के अध्यक्ष डॉ. अजय च्रुंगू ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना पर चिंता जताई और केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की बदलती प्रकृति को गंभीरता से समझते हुए प्रभावी रणनीति बनाने की मांग की।

पनुन कश्मीर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल होने के दावों के बावजूद आतंकी घटनाएं, लक्षित हत्याएं और घुसपैठ की कोशिशें लगातार सुरक्षा चुनौतियों को सामने ला रही हैं। संगठन ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए केवल विकास कार्यों, आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा देना पर्याप्त नहीं है।

सांबा में 58 किलो पोस्त बरामद, तस्कर गिरफ्तार

अंतरराज्यीय नशा नेटवर्क का पर्दाफाश, पुलिस ने ट्रक समेत पकड़ा आरोपी

भारतेंदु संवाददाता, सांबा

मध्य प्रदेश से आई खेप, पंजाब तक जुड़े तार

जम्मू-कश्मीर में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सांबा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नशा तस्करी के एक अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए एक तस्कर को करीब 58.068 किलोग्राम पोस्त जैसे मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थाना घगवाल क्षेत्र में की गई।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि जिले से होकर भारी मात्रा में मादक पदार्थ की खेप ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर थाना घगवाल की पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे तप्याल पर नाका लगाकर वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान कठुआ की ओर से बाड़ी ब्राह्मणा जा रहे एक कंटेनर ट्रक को शक के आधार पर रोका गया।

तलाशी के दौरान पुलिस को ट्रक के अंदर छिपाकर रखा गया करीब 58.068 किलोग्राम पोस्त जैसा मादक पदार्थ बरामद हुआ। तस्करों ने खेप को छिपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते यह पकड़ में आ गई।

पुलिस ने ट्रक चालक को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान दीपक सिंह पुत्र नरिंदर सिंह निवासी सेशवां, तहसील मढ़ीन, जिला कठुआ के रूप में हुई है। पुलिस ने मादक पदार्थ को जब्त करने के साथ ही तस्करी में इस्तेमाल किए गए कंटेनर ट्रक को भी सीज कर लिया है। बरामद माल और वाहन की कुल कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई जा रही है।

इस मामले में थाना घगवाल में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह खेप मध्य प्रदेश से लाई गई थी और इसके तार पंजाब से जुड़े हुए हैं।

महबूबा के तिरंगा विवाद पर उमर अब्दुल्ला ने बताया इसे अनजानी गलती

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा पकड़े जाने के विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को गंभीर मुद्दा बनाने से इनकार करते हुए कहा कि यह संभवत: अनजाने में हुई गलती थी और इसे जानबूझकर किया गया कृत्य नहीं माना जा सकता।

यह विवाद मंगलवार रात श्रीनगर में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान शुरू हुआ। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने के विरोध में धरने पर बैठी थीं। इस दौरान उनके हाथ में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्य का झंडा और भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दिखाई दिया। इसी दौरान सामने आई तस्वीरों और वीडियो में तिरंगा कथित रूप से उल्टा नजर आया, जिसके बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया। पुंछ जिले की बाढ़ प्रभावित सुरनकोट तहसील के दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह यह स्वीकार नहीं कर सकते कि जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी कोई नेता जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेगी।

उन्होंने कहा कि इस मामले में सवाल महबूबा मुफ्ती से पूछा जाना चाहिए, लेकिन उनका मानना है कि यह एक मानवीय भूल रही होगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर गलती से झंडा गलत तरीके से पकड़ा गया है तो उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए।

आरएसपुरा में शुरू होगी कैंप अदालत लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

भारतेंदु संवाददाता, आरएसपुरा

गंभीर मामलों की सुनवाई आरएसपुरा में ही होगी

जम्मू जिले के आरएसपुरा क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब गंभीर आपराधिक और दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए लोगों को बार-बार जम्मू नहीं जाना पड़ेगा। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आरएसपुरा मुंसिफ कोर्ट में द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जम्मू की कैंप अदालत शुरू की जाएगी।

उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार शुरुआती चरण में यह कैंप अदालत हर पखवाड़े में एक बार बैठेगी और आरएसपुरा क्षेत्र से जुड़े नए तथा जरूरी मामलों की सुनवाई करेगी। यह व्यवस्था फिलहाल तीन माह के लिए लागू की गई है। इसके बाद अदालत के कामकाज, मामलों की संख्या और जनहित को देखते हुए इसकी समीक्षा की जाएगी।

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आरएसपुरा में अदालत की बैठकों का पहले से कैलेंडर जारी किया जाएगा, ताकि अधिवक्ताओं, वादकारियों और अन्य संबंधित लोगों को समय पर जानकारी मिल सके। शुरुआती दौर में नए मामलों के साथ-साथ अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी।

अनुच्छेद 370 की बरसी पर जम्मू-कश्मीर में सियासत हुई तेज

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने की सातवीं बरसी पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी इसे देश के संवैधानिक इतिहास का ऐतिहासिक और निर्णायक दिन बता रही है, वहीं कई क्षेत्रीय दलों ने इस दिन को काला दिवस बताते हुए विरोध जताया है।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने इस मौके पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह जंतर-मंतर पर जेन-जी ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई, उसी तरह जम्मू-कश्मीर के लोग भी अपनी बात मजबूती से रखेंगे।

◆ **इल्तिजा मुफ्ती ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई**

इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि उनकी मांग जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे, अपने झंडे, कानून और संविधान की बहाली की है। उन्होंने कहा कि केवल राज्य के दर्जे की बहाली की मांग पर्याप्त नहीं है और उनकी पार्टी विशेष अधिकारों की बहाली के मुद्दे पर कायम है।

उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी आतंकी घटना के बाद बड़ी संख्या में आम लोगों को हिरासत में लिया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हर नागरिक को आतंकवादी मानना उचित है। उन्होंने कहा कि लोगों की आवाज को उग्रवाद या आतंकवाद का नाम देकर दबाया नहीं जा सकता।

अनुच्छेद 370 हटाए जाने की बरसी को देखते हुए जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की है। सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई गई है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है।

कासिम नगर की गलियों का होगा कायाकल्प, 20 लाख से शुरू होगा काम

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। शहर के वार्ड नंबर 47 स्थित कासिम नगर और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से जर्जर गलियों, जलभराव और धूल-मिट्टी की समस्या झेल रहे स्थानीय निवासियों को जल्द ही इन परेशानियों से निजात मिलने वाली है। जम्मू नगर निगम ने क्षेत्र की आंतरिक गलियों के सुदृढ़ीकरण और पक्का करने के लिए 20.10 लाख रुपये की अनुमानित लागत से टेंडर जारी कर दिया है।

आवास एवं शहरी विकास विभाग, जम्मू-कश्मीर प्रशासन के तहत शुरू होने वाली इस परियोजना से क्षेत्र में आवागमन आसान होगा और स्वच्छता व्यवस्था में भी सुधार आएगा। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर वर्क्स फिरदौस काजी ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी महीने काम आवंटित कर दिया जाएगा। इसके बाद ठेकेदार डेढ़ महीने के भीतर निर्माण कार्य शुरू कर सकता है। कासिम नगर की गलियां लंबे समय से खराब स्थिति में थीं।

परिवर्तन — अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास की खुलीं नई राहें – पीएम मोदी

अनुच्छेद 370 की बरसी पर पीएम मोदी ने गिनाए बदलाव

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सातवीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्ष 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि अनुच्छेद 370 और 35ए हटने के बाद क्षेत्र के विकास की नई यात्रा शुरू हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले सात वर्षों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, उद्यमिता और खेल के क्षेत्रों में लोगों के लिए नए अवसर बढ़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के संविधान के पूर्ण कार्यान्वयन से महिलाओं और वंचित वर्गों को उनके अधिकार मिले हैं, जो लंबे समय से इससे वंचित थे। उन्होंने इस वर्ष 5 अगस्त के महत्व को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती से भी जोड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए डॉ. मुखर्जी का योगदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा और उनका सपना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से पूरा हुआ।

बदला जम्मू-कश्मीर परिदृश्य

प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शांति, विकास और समान अवसरों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार क्षेत्र के युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

जम्मू-कश्मीर में विकास की नई कहानी

प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूती मिली है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अब अधिक लोगों तक पहुंच रहा है और विकास कार्यों में तेजी आई है। सड़क, रेल, पर्यटन और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं को नए अवसर मिलने की बात कही और कहा कि जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख देश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

शांति और प्रगति की नई राह

केंद्र सरकार के अनुसार अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में कई प्रशासनिक और सामाजिक बदलाव हुए हैं। पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को गति मिली है और स्थानीय निकायों की भूमिका बढ़ी है। पर्यटन क्षेत्र में भी गतिविधियां बढ़ने से रोजगार के नए अवसर सामने आए हैं। सरकार का कहना है कि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखते हुए शांति और स्थिरता कायम रखने के प्रयास लगातार जारी हैं।

न्यूज ब्रीफ

केमिस्ट्री टीचर के 78 पदों का कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने केमिस्ट्री टीचर (एंजेसमेंट के आधार पर) के 78 पदों का पोस्ट कोड-26018 की भर्ती के लिए कंप्यूटर-बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 3.07.2026 को आयोजित की गई थी। परिणाम आयोग द्वारा स्वीकृत अवार्ड लिस्ट और अनुपात के आधार पर तैयार किया गया है। इन पदों को भरने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशक शिमला-01 से मांग प्राप्त हुई थी और 07.04.2026 को विज्ञापन संख्या 07/2026 के तहत विज्ञापन जारी किया गया था इस विज्ञापन के जवाब में 2439 आवेदन प्राप्त हुए और सभी को प्रोविजनली (अस्थायी रूप से) स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा, 1963 उम्मीदवार कंप्यूटर-बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल हुए और 476 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ विक्रम महाजन ने बताया कि यह परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। उन्होंने कहा कि चयनित उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया/दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया गया है।

सिरमौर पुलिस ने लौटाए 829 गुम मोबाइल

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। सिरमौर पुलिस ने गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन तलाशने के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर) पोर्टल की मदद से अब तक 829 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए हैं। इन मोबाइलों की कुल कीमत करीब एक करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार एक जुलाई से पांच अगस्त 2026 के बीच 18 मोबाइल फोन भी विशेष अभियान के तहत बरामद किए गए। सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुम या चोरी हुए मोबाइल की निगरानी और ट्रैकिंग की जाती है। साइबर कमांडो और पुलिस की तकनीकी टीम मोबाइल की जानकारी जुटाकर संबंधित थानों को उपलब्ध करवाती है, जिसके बाद मोबाइल बरामद कर मालिकों को सौंपे जाते हैं। एसपी निश्चित सिंह नेगी ने लोगों से मोबाइल गुम होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने और सीईआईआर पोर्टल पर मोबाइल ब्लॉक करवाने की अपील की है।

दिव्यांगजनों के लिए कल चिकित्सा परीक्षण शिविर

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर में दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से 7 अगस्त को क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में चिकित्सा परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शशि दत्त शर्मा ने जिला मेडिकल डिसेबिलिटी बोर्ड का गठन किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बोर्ड में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों और अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसमें शिशु रोग विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक और मेडिसिन विशेषज्ञ सेवाएं देंगे। उन्होंने बताया कि शिविर सुबह 10 बजे से शुरू होगा और अंतिम लाभार्थी के परीक्षण तक जारी रहेगा। उन्होंने सभी संबंधित दिव्यांगजनों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचकर चिकित्सा परीक्षण करवाएं, ताकि उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

नशा मुक्त युवा ही विकसित समाज की पहचान

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा राजकीय डिग्री कॉलेज बिलासपुर में नशा मुक्त भारत अभियान और प्रोटेक्टिव एजिंग कार्यक्रम के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त राहुल कुमार ने मुख्य ातिथि के रूप में शिरकत की। डीसी ने कहा कि नशा मुक्त युवा और सम्मानित वरिष्ठ नागरिक ही विकसित समाज की पहचान हैं। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने, पौधरोपण करने और बुजुर्गों का सम्मान करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि जिले की 27 संवेदनशील पंचायतों में नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक डेढ़ लाख से अधिक लोगों को नशा मुक्ति और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया जा चुका है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के विशेषज्ञों ने नशे के दुष्प्रभाव, साइबर सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल पर जानकारी दी।

फसल बीमा योजना के तहत 15 तक करवाएं बीमा

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। कृषि उपनिदेशक सिरमौर ने बताया कि सिरमौर जिला में दो फसल बीमा योजनाएं जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना चल रही है जिसके अंतर्गत खरीफ मौसम -2025 के लिए फसलों का बीमा 15 अगस्त तक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मक्की और धान तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत आलू और टमाटर की फसलों का बीमा किया जाना है। उन्होंने बताया कि मक्की और धान दोनो फसलों के लिए बीमित राशि 60 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर है जिसमें किसानों को बीमित राशि का मात्र 02 प्रतिशत अर्थात प्रति हेक्टेयर 1200 रुपए या प्रति बीघा 98 रुपए प्रीमियम राशि के रूप में देना होगा। इसी प्रकार टमाटर के लिए बीमित राशि 02 लाख तथा आलू की बीमित राशि 01 लाख, 50 हजार रुपए निर्धारित की गई है। इन दोनों फसलों के लिए किसानों को 05 प्रतिशत अर्थात टमाटर के लिए 800 रुपए तथा आलू के लिए 600 रुपए प्रति बीघा प्रीमियम राशि देनी होगी जबकि शेष प्रीमियम राशि का भुगतान केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन फसलों का बीमा करवा कर किसान फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक, प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, सैलाब, प्राकृतिक आग, भूमि कटाव आदि के जोखिम से फसलों को सुरक्षित कर सकते है। इसके अतिरिक्त फसल कटाई के उपरांत दो सप्ताह तक होने वाले नुकसान तथा स्थानीयकृत आपदाओं से होने वाले नुकसानों की भी भरपाई की जा सकती है।

शिमला में भाजपा का प्रदर्शन, भ्रष्टाचार और बदले की राजनीति के खिलाफ हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे

कांग्रेस प्रतिशोध की राजनीति कर रही : जयराम

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हिमाचल प्रदेश ने बुधवार को राजधानी शिमला में कांग्रेस सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार, प्रतिशोध की राजनीति, बिगड़ती कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग के विरोध में विशाल धरना-प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया, जबकि अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने की। प्रदर्शन में प्रदेशभर से आए भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। धरना-प्रदर्शन के बाद भाजपा कार्यकर्ता रैली के रूप में शेर-ए-पंजाब से मुख्यमंत्री आवास ओकओवर तक पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई तथा सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई गई। सभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद से विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को टालने के प्रयास किए गए, लेकिन भाजपा ने न्यायालय का रुख किया, जिसके बाद चुनाव हुए। उन्होंने दावा किया कि हालिया चुनाव परिणामों में जनता ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ स्पष्ट जनादेश दिया है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनावी हार के बाद सरकार प्रशासन का दुरुपयोग कर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल सहित कई विधायकों और पार्टी नेताओं को राजनीतिक प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों और सोशल मीडिया पर आवाज उठाने वाले नागरिकों पर भी कार्रवाई की जा रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि 21 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में भाजपा इन मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाएगी। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपनी कार्यशैली नहीं बदली, तो पार्टी राज्यभर में आंदोलन को और व्यापक बनाएगी। उन्होंने प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर भी चिंता जताते हुए हाल की आपराधिक घटनाओं का उल्लेख किया।

महिलाओं, युवाओं, किसानों व कर्मचारियों से किए हर वादे से मुकर गई कांग्रेस सरकार: डॉ. राजीव बिंदल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि यह आंदोलन केवल शुरुआत है और अब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र एवं मंडल स्तर पर हर महीने धरने-प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को 1500 प्रतिमाह, युवाओं को रोजगार और अन्य चुनावी वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि कई संस्थानों को बंद कर दिया गया तथा कर्मचारियों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित हर वर्ग निराश है। डॉ. बिंदल ने दावा किया कि बिजली, डीजल और सीमेंट जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर सरकार की कथित विफलताओं को जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया। प्रदर्शन के अंत में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार की नीतियों के विरोध में आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया।

कांगड़ा में दो आरोपी 5.18 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। कांगड़ा पुलिस ने एक वाहन से 5.18 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के खिलाफ पुलिस थाना कांगड़ा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक थाना प्रभारी आदर्श बरयाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पुराना कांगड़ा स्थित हनुमान घाट के पास नाकाबंदी के दौरान देहरा की ओर से आ रहे एप्लाइड फ़ॉर वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन के डैशबोर्ड से 5.18 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई। इस मामले में वाहन चालक अशोक कुमार (27 वर्ष), निवासी रजोल, तहसील शाहपुर तथा वाहन मालिक शुभम डोगरा (30 वर्ष), निवासी लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कांगड़ा में एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

4-5 सितंबर को होगा राज्य स्तरीय जन्माष्टमी महोत्सव

जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कसी कमर

अशोक ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, नूरपुर। राज्य स्तरीय जन्माष्टमी महोत्सव को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी 4 और 5 सितंबर को नूरपुर में आयोजित होने वाले महोत्सव की तैयारियों को लेकर एसडीएम अरुण शर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और तैयारियों की प्रगति पर चर्चा की गई। एसडीएम अरुण शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और महोत्सव की भव्यता को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। उन्होंने नगर परिषद को मेला स्थल पर सफाई व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिए। जल शक्ति विभाग को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने और अस्थायी पानी के नल लगाने को कहा गया। वहीं बिजली बोर्ड को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि महोत्सव की तैयारियों की नियमित समीक्षा की जाएगी और आयोजन से पहले एक और बैठक आयोजित कर अंतिम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा।

श्रद्धालुओं के वाहनों की सुविधा के लिए बचत भवन के समीप विशेष पार्किंग स्थल बनाया जाएगा, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे। एसडीएम ने बताया कि जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाली 4 और 5 सितंबर की सांस्कृतिक संध्याओं के लिए कलाकारों का चयन जल्द किया जाएगा। महोत्सव की निगरानी और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए तहसीलदार राधिका सैनी को मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने सभी विभागों से आपसी तालमेल के साथ कार्य करने का आह्वान किया, ताकि महोत्सव श्रद्धा, उत्साह और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। बैठक में वन विकास निगम के निदेशक योगेश महाजन, तहसीलदार राधिका सैनी, तहसीलदार प्रोबेशन स्वाति वालिया, बीडीओ अशोक कुमार, पीडब्ल्यूडी एसडीओ उमिंद्र सिंह, नगर परिषद एसडीओ राजेश चौधरी, बिजली बोर्ड एसडीओ पुनीत कुमार, नगर परिषद अध्यक्ष नीति महाजन, उपाध्यक्ष सोनिया सोगा, मंदिर कमेटी अध्यक्ष दविंद्र शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

रोहड़ू में पब्बर नदी में गिरी पिकअप, चालक को सुरक्षित बचाया

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। रोहड़ू उपमंडल में एक पिकअप के पब्बर नदी में गिर जाने का मामला सामने आया है। हादसे में वाहन चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने जांच के बाद चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। बुधवार तड़के सड़क हादसे की सूचना मिलने पर रोहड़ू थाना पुलिस की टीम एएसआई यशपाल के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस को बोलेरो पिकअप, जिसका पंजीकरण नंबर एचपी-10बी-1536 है, पब्बर नदी के बीच में मिली। पुलिस ने वाहन चालक सचिन चौहान (35) पुत्र प्रीतम सिंह, निवासी गांव जगोठी, तहसील रोहड़ू को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल रोहड़ू भेजा। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि हादसे के समय वाहन में सचिन चौहान अकेला सवार था।

नूरपुर में 2.3 ग्राम चिट्टे के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

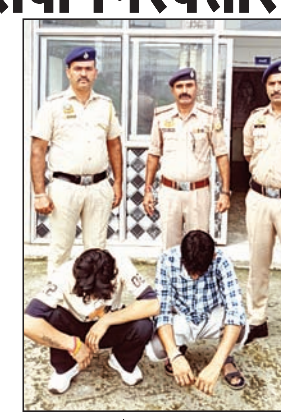

भारतेन्दु संवाददाता नूरपुर। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 2.3 ग्राम हेरोइन बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की है। एसपी नूरपुर ने बताया कि पुलिस चौकी कंडवाल की टीम द्वारा नागावाड़ी क्षेत्र में पक्का टियाला के पास गश्त व चैकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को पैदल आते देखा गया। पुलिस को देखकर एक व्यक्ति ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर सड़क किनारे फेंक दी तथा दोनों वापस मुड़कर जाने लगे। शक के आधार पर पुलिस टीम ने दोनों को रोककर स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में पुड़िया की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुड़िया से 2.3 ग्राम हैरोइन बरामद हुआ। आरोपियों की पहचान सुनील सिंह (28 वर्ष) पुत्र अमरीक सिंह व अरविन्द सिंह (38 वर्ष) पुत्र मदन सिंह, दोनों निवासी गांव व डाकघर बाड़ी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बाद में नियमानुसार जमानत पर रिहा किया गया। मामले की जांच जारी है।

किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन लगवाने की अपील

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। अतिरिक्त उपायुक्त रुपिंदर कौर ने जिले के अभिभावकों से 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बेटियों को निशुल्क एचपीवी (ह्यूमन पेपीलोमा वायरस) वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन भविष्य में महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सबसे प्रभावी वैज्ञानिक उपाय है। उन्होंने बताया कि जिले के चिन्हित सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में यह टीका पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध है। अब तक बिलासपुर में 1,111 किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का करीब 41 प्रतिशत है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियों पर ध्यान न दें, क्योंकि इसके सुरक्षित होने के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे स्वास्थ्य विभाग की प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करें और पात्र बेटियों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाकर टीकाकरण अवश्य करवाएं।

सीएम के गृह जिले का मेडिकल कॉलेज बदहाल : आशीष शर्मा

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। सदर के विधायक आशीष शर्मा ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के गृह जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की हालत ही प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत कर रही है।

आशीष शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में पिछले कई दिनों से सीटी स्कैन सुविधा बाधित रहने के कारण मरीजों को निजी लैब में महंगे दामों पर जांच करवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर इसका सीधा बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री के अपने जिले के मरीजों को भी समय पर सीटी स्कैन जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही तो प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की लिफ्टें बार-बार खराब हो रही हैं, जिससे बुजुर्ग, गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं और स्ट्रेचर पर लाए जाने वाले मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह केवल तकनीकी खामी नहीं बल्कि अस्पताल प्रबंधन की गंभीर प्रशासनिक विफलता का उदाहरण है। आशीष शर्मा ने आरोप लगाया कि अस्पताल में कई आवश्यक जेनेरिक दवाइयों का अभाव बना हुआ है। इतना ही नहीं, कई बार मरीजों और उनके परिजनों को सर्जिकल ग्लव्स, सिरिंज तथा अन्य आवश्यक चिकित्सा सामग्री तक बाहर निजी मेडिकल स्टोरों से खरीदने के लिए कहा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले लोगों को यदि हर जरूरी सामान बाजार से खरीदना पड़े तो फिर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का औचित्य ही क्या रह जाता है।

भाखड़ा विस्थापितों की मांग, कब्जे वाली भूमि का दिया जाए स्वामित्व

10 को डीसी कार्यालय में धरना देंगे विस्थापित

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला ग्रामीण भाखड़ा विस्थापित सुधार समिति की बैठक बल्ह-बलवाणा पंचायत में प्रधान इंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

बैठक में समिति के प्रधान देशराज शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान भाखड़ा विस्थापितों की लंबे समय से लंबित समस्याओं और मांगों पर चर्चा की गई तथा सरकार की कार्यप्रणाली पर रोष जताया गया। समिति के सदस्यों ने कहा कि विस्थापितों की समस्याओं को लेकर कई बार प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 अगस्त को उपायुक्त कार्यालय परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जाएगा। इसके बाद मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को उपायुक्त के माध्यम से भेजा जाएगा। समिति ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। समिति प्रधान देशराज शर्मा ने कहा कि 9 अगस्त 1960 को भाखड़ा बांध में पहली बार पानी भरना शुरू हुआ था और तभी से हजारों परिवार विस्थापन की पीड़ा झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि छह दशक से अधिक समय बीतने के बावजूद कई विस्थापित परिवार भूमि, पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

समिति ने मांग की कि भाखड़ा विस्थापित बहुल क्षेत्रों का बंदोबस्त कर कब्जे वाली भूमि का स्वामित्व दिया जाए। इसके अलावा बिजली-पानी के काटे गए कनेक्शन बहाल करने, निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करवाने, विस्थापितों के बच्चों को बीबीएमबी व सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने और गोबिंद सागर झील के विकास की मांग उठाई गई। बैठक में झील क्षेत्र में पुलों के निर्माण, मछुआरों के हितों की रक्षा, पर्यटन विकास और वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत पात्र परिवारों को भूमि व आवास अधिकार देने की मांग भी की गई। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।

नशा मुक्ति केंद्रों में बेहतर माहौल गतिविधियों पर जोर : नरेश ठाकुर

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। नशा निवारण बोर्ड के संयोजक एवं सलाहकार नरेश ठाकुर ने हमीरपुर शहर में संचालित किए जा रहे दो नशा मुक्ति केंद्रों-आयुष्मान रिहेबिलिटेशन सेंटर और गुंजन संस्था के एकीकृत नशा निवारण व पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया।

उन्होंने दोनों नशा मुक्ति केंद्रों में प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय अत्री, सीआईडी इंचार्ज कपिल सडियाल और अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण के लिए पहुंचे नरेश ठाकुर ने इन केंद्रों में विभिन्न सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने दोनों नशा मुक्ति केंद्रों के रिकॉर्ड की गहन जांच के साथ-साथ संचालकों से इन केंद्रों की दैनिक गतिविधियों की विस्तृत भी जानकारी ली। नरेश ठाकुर ने कहा कि नशे से मुक्ति पाने के लिए इन केंद्रों में दाखिल होने वाले लोगों को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ अनकूल व सकारात्मक माहौल भी मिलना चाहिए। तभी वे नशे के दलदल से बाहर निकलने में सक्षम होंगे। इसके लिए नशा मुक्ति केंद्रों के दैनिक रूटीन में अधिक से अधिक गतिविधियों का समावेश किया जाना चाहिए। नरेश ने बताया कि राज्य नशा निवारण बोर्ड प्रदेश भर में नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण करके इनमें उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न सुविधाओं की समीक्षा कर रहा है। निरीक्षण के बाद सभी केंद्रों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर नशा मुक्ति केंद्रों के लिए बोर्ड व्यापक दिशा-निर्देश जारी करेगा।

चर्चा बिलासपुर में पेंशनर संयुक्त मोर्चा की बैठक, मांगों को लेकर बनाई रणनीति

एरियर भुगतान व जेसीसी गठन में देरी पर जताई चिंता

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त मोर्चा की राज्य स्तरीय त्रैमासिक बैठक जिला बिलासपुर मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर कोल बेली हारनोरा में आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता मोर्चा अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने की। बैठक में प्रदेशभर से आए पेंशनर प्रतिनिधियों ने लंबित मांगों और पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई। इसके बाद दिवंगत पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महासचिव ने उपस्थित पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए बैठक के एजेंडे की जानकारी दी। वहीं कोषाध्यक्ष ने मोर्चा की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में 21 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ हुई वार्ता के प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा की गई।

इसके बाद जिला प्रतिनिधियों, राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों और संबद्ध संगठनों के पदाधिकारियों ने पेंशनरों की समस्याओं को लेकर अपने विचार रखे। मोर्चा अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए सभी संगठनों को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को लंबित एरियर का भुगतान न होने पर चिंता जताई। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि 15 अगस्त तक 15 प्रतिशत बकाया डीए एरियर जारी करने की घोषणा की जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपने आश्वासन के अनुसार लंबित वित्तीय मामलों पर निर्णय नहीं लेती है, तो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर आगामी रणनीति तय की जाएगी।

बैठक में संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) के गठन में हो रही देरी पर भी चिंता व्यक्त की गई। मोर्चा के संयोजक एवं मंडी जिला अध्यक्ष हरीश शर्मा ने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए एक जुलाई से 30 सितंबर तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने की अनिवार्यता से प्रदेशभर के पेंशनरों में रोष है।

उन्होंने सरकार से इस व्यवस्था को तुरंत समाप्त कर पुरानी प्रणाली बहाल करने की मांग की। बैठक में पेंशनरों की अन्य लंबित मांगों पर भी चर्चा की गई। प्रदेश के 12 जिलों से पहुंचे करीब 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने पेंशनरों के अधिकारों और समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष कल्याण भंडारी, लेखराम कोंडल, रवि दत्त भारद्वाज, सेस राम, मुख्य सलाहकार लेखराज राणा, प्रदेश मीडिया प्रभारी कुलदीप गुलेरिया, सलाहकार प्रकाश ठाकुर, कोषाध्यक्ष संतराम शांडिल सहित विभिन्न जिलों के प्रधान, सचिव और राज्य कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे।

पर्यावरण संरक्षण हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग : प्रो. ललित

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी के इतिहास विभाग द्वारा 'भारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण का इतिहास' विषय पर अतिथि व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्यातिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ललित कुमार अवस्थी रहे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र खनियारा, कांगड़ा के इतिहास विभाग के समन्वयक एवं सहायक आचार्य डॉ. राज कुमार उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार शर्मा ने मुख्यातिथि, मुख्य वक्ता, संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों के स्वागत के साथ किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय इतिहास वर्तमान समय का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है तथा भारतीय सभ्यता में प्रकृति संरक्षण की समृद्ध परंपरा रही है। ऑनलाइन संबोधन में कुलपति प्रो. ललित कुमार अवस्थी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल वैज्ञानिक विषय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक विरासत और सामाजिक उत्तरदायित्व से भी जुड़ा है। उन्होंने विद्यार्थियों से इतिहास के माध्यम से पर्यावरणीय चेतना को समझने और सतत विकास के लक्ष्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

मुख्य वक्ता ने भारत में पर्यावरण संरक्षण की परंपराओं, प्राचीन ग्रंथों, पवित्र वनों, जल संरक्षण प्रणालियों तथा सामुदायिक संसाधन प्रबंधन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने औपनिवेशिक काल में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, वनों पर नियंत्रण, चिपको आंदोलन और बिश्नोई समुदाय के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्यावरणीय इतिहास भविष्य के लिए संतुलित और सतत विकास की दिशा दिखाता है।

खिलाड़ी व मॉडल मैंडी रोज

मैंडी रोज एक प्रसिद्ध अमेरिकी महिला पहलवान, फिटनेस मॉडल और टेलीविजन कलाकार हैं। उनका जन्म 18 जुलाई 1990 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उन्होंने कुश्ती की दुनिया में अपनी मेहनत, प्रतिभा और शानदार प्रदर्शन से अलग पहचान बनाई।

वनडे विश्व कप–2027 के लिए 22 फरवरी से शुरू होगा क्वालीफायर टूर्नामेंट

आईसीसी ने अभी नहीं की टूर्नामेंट के मेजबान देश की आधिकारिक घोषणा

एजेंसी, नई दिल्ली

वर्ष 2027 आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप के लिए क्वालीफायर टूर्नामेंट अगले वर्ष 22 फरवरी से 23 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अभी तक क्वालीफायर टूर्नामेंट के मेजबान देश की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आईसीसी द्वारा जुलाई में घोषित नई क्वालीफिकेशन प्रणाली के अनुसार, 10 टीमों वाले इस क्वालीफायर का विजेता सीधे 2027 वनडे विश्व कप के 14 टीमों वाले मुख्य ग्रुप चरण में प्रवेश करेगा। वहीं, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें टूर्नामेंट के शुरुआती चरण 'सुपर सीरीज' में खेलेंगी। इन तीन टीमों के बीच मुकाबले के बाद शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम को मुख्य चरण का अंतिम टिकट मिलेगा। 2027 वनडे विश्व कप का आयोजन 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया के 12 मैदानों पर किया जाएगा।

कुल 10 टीमों का होगा क्वालीफायर

क्वालीफायर में 30 सितंबर 2026 तक की वनडे रैंकिंग के आधार पर मेजबान दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को छोड़कर दो सबसे निचली रैंकिंग वाली पूर्ण सदस्य (फुल मेंबर) टीमें खेलेंगी। इनके अलावा क्रिकेट विश्व कप लीग-2 की शीर्ष चार टीमें और विश्व कप क्वालीफायर प्लेऑफ की शीर्ष चार टीमें भी इसमें हिस्सा लेंगी। आठ टीमों वाले क्वालीफायर प्लेऑफ में लीग-2 की सबसे निचली चार टीमें तथा चैलेंज लीग की शीर्ष चार टीमें खेलेंगी। प्लेऑफ का प्रारूप अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन शीर्ष चार टीमें विश्व कप क्वालीफायर के लिए स्थान बनाएंगी। चैलेंज लीग में 12 टीमों को छह-छह टीमों के दो समूहों में बांटा जाएगा। प्रत्येक समूह तीन राउंड-रॉबिन प्रतियोगिताएं खेलेगा और दोनों समूहों की शीर्ष दो टीमें क्वालीफायर प्लेऑफ में पहुंचेंगी।

वेस्टइंडीज पर लटक रही क्वालीफायर की तलवार

फिलहाल वेस्टइंडीज आईसीसी वनडे रैंकिंग में 10वें स्थान पर है और 30 सितंबर की कट-ऑफ तारीख से पहले उसे भारत के खिलाफ सितंबर में दो वनडे मुकाबले खेलने हैं। वेस्टइंडीज के शीर्ष आठ में पहुंचने की संभावना अन्य टीमों के परिणामों पर भी निर्भर करेगी, खासकर अफगानिस्तान (आठवें स्थान) और आयरलैंड (12वें स्थान) के बीच होने वाली पांच मैचों की वनडे श्रृंखला पर। यदि आयरलैंड यह शृंखला 4-1 या 5-0 से जीतता है और वेस्टइंडीज भारत के खिलाफ दोनों मैच जीत लेता है, तो उसके शीर्ष आठ में पहुंचने की संभावना बन सकती है, लेकिन यदि अफगानिस्तान शृंखला जीत जाता है, तो वेस्टइंडीज को लगभग तय तौर पर क्वालीफायर का रास्ता अपनाना पड़ेगा। गौरतलब है कि वेस्टइंडीज 2023 वनडे विश्व कप के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर सका था।

आर प्रज्ञानानंदा सेंट लुईस टूर्नामेंट के रैपिड में शीर्ष पर

एजेंसी, सेंट लुइस

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंदा ने सेंट लुइस रैपिड एवं ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता के रैपिड वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 में से 12 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उन्होंने इसके साथ ही वर्ष के अंत में होने वाले 'ग्रैंड शतरंज टूर (जीसीटी)' फाइनल में जगह बनाने की अपनी उम्मीदें भी कायम रखी हैं। विश्व चैंपियनशिप 2026 की दौड़ से बाहर हो चुके प्रज्ञानानंदा ने नौ दौर के रैपिड मुकाबलों में बेहतरीन तकनीक, सटीक चालों और जीत के जज्बे का परिचय दिया। उन्हें हालांकि के नौवें और अंतिम दौर में नीदरलैंड के ग्रैंडमास्टर जॉर्डन वान फोरेस्ट से हार का सामना करना पड़ा, फिर भी वह एक अंक की बढ़त के साथ शीर्ष पर बने रहे। उन्होंने उजबेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव (11 अंक) को पीछे छोड़ा, जो इस वर्ष विश्व चैम्पियनशिप मुकाबले में डी. गुकेश को चुनौती देंगे। प्रतियोगिता का परिणाम केवल रैपिड वर्ग से तय नहीं होगा। अब 18 ब्लिट्ज मुकाबले खेले जाएंगे, जिनके बाद कुल विजेता का फैसला होगा। प्रतियोगिता की कुल पुरस्कार राशि दो लाख अमेरिकी डॉलर है, जिसमें विजेता को 50 हजार अमेरिकी डॉलर मिलेंगे।

अब 18 ब्लिट्ज मैचों से होगा खिताब का फैसला

प्रज्ञानानंदा ने रैपिड वर्ग में चार जीत (प्रत्येक जीत पर दो अंक), चार ड्रॉ और एक हार के साथ कुल 12 अंक जुटाए। अब उनका पूरा ध्यान 18 दौर के ब्लिट्ज मुकाबलों पर होगा, जहां प्रत्येक जीत के लिए एक अंक मिलेगा। सिंदारोव 11 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि अमेरिका के वेस्ली सो 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इनके बाद अमेरिका के लेवोन अरोनियन, नीदरलैंड के अनीश गिरी, क्यूबा मूल के अमेरिकी लेनियर डोमिंगेज पेरेज और जर्मनी के विन्सेंट कीमर नौ–नौ अंकों के साथ संयुक्त रूप से अगले स्थान पर हैं । दस खिलाड़ियों की राउंड–रॉबिन प्रतियोगिता के बाद प्रतिष्ठित सिंकफील्ड कप खेला जाएगा, जो क्लासिकल प्रारूप में आयोजित होगा।

स्पोर्ट्स विंडो

कार्लोस अल्काराज कलाई की चोट के कारण सिनसिनाटी ओपन से हटे

एजेंसी, सिनसिनाटी। दुनिया के दूसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज दाईं कलाई की चोट के कारण मंगलवार को सिनसिनाटी ओपन से हट गए। यह चोट उन्हें अप्रैल से परेशान कर रही है। स्पेन के अल्काराज इस हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट में अपने खिताब का बचाव करने की तैयारी कर रहे थे। यह प्रतियोगिता यूएस ओपन से पहले महत्वपूर्ण अभ्यास टूर्नामेंट मानी जाती है। टूर्नामेंट निदेशक बॉब मोरान ने कहा, ''हम जानते हैं कि कार्लोस जल्द से जल्द कोर्ट पर लौटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और भविष्य में सिनसिनाटी में उनका स्वागत करने की उम्मीद करते हैं।' हाल की तस्वीरों और वीडियो में उन्हें अभ्यास करते हुए देखा गया था, जिससे उम्मीद थी कि वह 11 अगस्त से शुरू होने वाले सिनसिनाटी ओपन में वापसी कर लेंगे। यूएस ओपन में उनकी वापसी की उम्मीदें हालांकि बरकरार है। वह यूएस ओपन के मौजूदा चैंपियन भी है।

हर्ष, शिवांग, तनुष और विप्रज टीम इंडिया में बतौर नेट बॉलर शामिल

एजेंसी, नई दिल्ली। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के कैंप में चार नेट बॉलर्स को शामिल किया है। बोर्ड ने बुधवार को बताया कि हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, तनुष कोटियान और विपराज निगम अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय बल्लेबाजों को गेंदबाजी करेंगे, ताकि उन्हें मैच जैसी परिस्थितियों में तैयारी का मौका मिल सके। क्रिकेट बोर्ड ने अपने बयान में कहा, 'हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, तनुष कोटियान और विपराज निगम श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले तैयारियों में मदद के लिए नेट बॉलर्स के रूप में टीम के साथ जुड़े हैं।'

जहीर ने लंका प्रीमियर लीग में टीम खरीदी, जाफना के को-ऑनर बने

एजेंसी, नई दिल्ली। पूर्व क्रिकेटर जहीर खान ने लंका प्रीमियर लीग में टीम खरीदी है। वे जाफना फ्रेंचाइजी के को-ऑनर बन गए हैं। जहीर ने एंकर स्पोर्ट्स एबी के साथ टीम को टेकओवर किया, जिसके बाद इसका नाम बदलकर 'एंकर जाफना किंग्स' कर दिया गया है। जहीर से पहले राहुल द्रविड़, युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर जैसे भारतीय दिग्गज भी अलग-अलग टी20 लीगों में टीमों में निवेश कर चुके हैं। जहीर खान ने कहा कि उन्होंने हमेशा श्रीलंका के बॉलिंग टलैंट की तारीख की है। उन्होंने श्रीलंका में काफी क्रिकेट खेला है और उनकी वहां से जुड़ी कई अच्छी यादें हैं। जहीर ने कहा कि अब एक मालिक के तौर पर श्रीलंकाई क्रिकेट का हिस्सा बनना उनके लिए बेहद रोमांचक है और वे एंकर जाफना किंग्स के साथ काम शुरू करने के लिए एक्साइटेड हैं। लंका प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट डायरेक्टर सामंथा डोडनवेला ने जहीर खान के जुड़ने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जहीर जैसे कद के व्यक्ति का टीम से जुड़ना पूरी लीग के लिए एक बड़ा बूस्ट है।

विक्रमादित्य करेंगे रैकेटलॉन विश्व चैंपियनशिप में भारत की अगुवाई

एजेंसी, नई दिल्ली। विक्रमादित्य चौफला की अगुवाई में भारतीय टीम रॉटरडम में बृहस्पतिवार से शुरू हो रही रैकेटलॉन विश्व चैम्पियनशिप में लगातार तीसरी बार खिताब जीतने उतरेगी। भारत की छह सदस्यीय टीम का ऐलान रैकेटलॉन भारत खेल संघ ने किया जिसमें चौफला, प्रशांत सेन, मोनिश मशरूवाला, अक्षय गांधी, राघव जटिया और निधि तिवारी शामिल हैं। यह टीम चैलेंज कप में भाग लेगी जिसमें भारत ने पिछले साल खिताब जीता था। रैकेटलॉन अनूठा खेल है जो टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वाश और टेनिस का मिश्रण है और चारों खेलों के कुल स्कोर मिलाकर विजेता का चयन होता है ।

टेस्ट सीरीज से पहले अभ्यास मैच नहीं खेलेगा ऑस्ट्रेलिया : मैकडोनाल्ड

एजेंसी, मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा है कि उनकी टीम अगले वर्ष भारत के खिलाफ होने वाली बहुचर्चित बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट शृंखला से पहले कोई अभ्यास मैच नहीं खेलेगी। उनका मानना है कि उपमहाद्वीप जैसी परिस्थितियों में छोटा तैयारी शिविर टीम के लिए अधिक उपयोगी साबित होगा। पांच टेस्ट मैचों की यह बहुप्रतीक्षित शृंखला 21 जनवरी से नागपुर में शुरू होगी। मैकडोनाल्ड ने 'क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू' से कहा, 'हमें लगता है कि परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इसलिए हम कोई अभ्यास मैच नहीं खेलेंगे। हमारा पूरा ध्यान ऐसी जगह तैयारी करने पर होगा, जहां भारत जैसी परिस्थितियां मिल सकें।' उन्होंने बताया, ''टीम के सामने दो विकल्प हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी तैयारी कर चुका है और 2023 के भारत दौरे से पहले बेंगलुरु में शिविर लगाया था।

राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतरीन रहा भारत का प्रदर्शन

भारत को एक दशक के प्रयासों के नतीजे मिलने लगे : मांडविया

एजेंसी, नई दिल्ली

खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के मनपसंद खेल नहीं होने के बावजूद खिलाड़ियों के असाधारण प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि पिछले एक दशक में सरकार के प्रयासों के नतीजे अब मिलने लगे हैं।

ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में बजट में कटौती के कारण सिर्फ 10 खेल शामिल किये गए थे जिसमें से भारत ने नौ खेलों में भाग लेकर 13 स्वर्ण समेत 39 पदक जीते। खेल मंत्री मांडविया ने बुधवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक में बैठक में ओलंपिक, एशियाई खेल और ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के प्रदर्शन का ब्यौरा दिया। भारत ने ग्लास्गो में जिन खेलों में भाग लिया, उनमें 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 30 और 2018 में गोल्ड कोस्ट में 22 पदक जीते थे। मांडविया ने कहा ,'सरकार ने 2014 से खेलों के क्षेत्र में जितने प्रयास किये हैं, उनके नतीजे अब मिलने लगे हैं । भारत ने 1947 से 2012 तक कुल 21 ओलंपिक पदक जीते थे लेकिन पिछले तीन ओलंपिक में ही 15 पदक मिल चुके हैं । इसी तरह 2022 एशियाई खेलों में पहली बार 100 पदकों का आंकड़ा पार किया।' भारतीय खिलाड़ी अब सितंबर अक्टूबर में जापान में एशियाई खेलों में भाग लेंगे। इसमें निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी जैसी स्पर्धायें शामिल होंगी जिसमें भारत का दबदबा रहता है। खेल मंत्री ने इस प्रदर्शन का श्रेय पिछले एक दशक में खेलों में सरकार की पहल के जरिये खेलों का ईकोसिस्टम तैयार करने को दिया जिसमें खेलो इंडिया योजना, फिट इंडिया मुहिम और अस्मिता लीग जैसी पहल शामिल हैं।

पेरिस ओलंपिक के बाद मुक्केबाजी जारी रखना बड़ी उपलब्धि : लवलीना

एजेंसी, नई दिल्ली। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कहा कि पेरिस ओलंपिक के बाद भी अपने करियर को जारी रखना उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है क्योंकि पिछले एक साल में चोट, आत्मविश्वास की कमी और मुश्किल दौर से गुजरने के बाद उन्होंने दोबारा वापसी की। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के रिकॉर्ड 10 मुक्केबाजी पदक जीतने के बाद खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात के दौरान 28 वर्षीय लवलीना ने पेरिस ओलंपिक के बाद की चुनौतियों को याद किया। वह 2024 ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई थीं। लवलीना ने 'पीटीआई वीडियो' से कहा, 'सबसे पहले तो मेरे लिए इतने लंबे समय तक खेल जारी रखना ही बड़ी बात थी। पेरिस ओलंपिक के बाद कई उतार-चढ़ाव आए। कई बार यह सवाल भी उठा कि मैं आगे खेलना चाहती हूं या नहीं। लेकिन मैंने वापसी की और खेल जारी रखा। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।' तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने वाली लवलीना ने इस बार अपना पहला राष्ट्रमंडल पदक जीता। उन्होंने रजत पदक हासिल किया।

गावित की नजरें अब 100 और 400 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाने पर

एजेंसी, नई दिल्ली

राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण करते हुए 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने के साथ रिकॉर्ड बनाने वाले पैरा एथलीट दिलीप गावित का लक्ष्य अगले महीने जापान में होने वाले पैरा एशियाई खेलों में 100 मीटर और 400 मीटर दोनों स्पर्धाओं में विश्व रिकॉर्ड कामय करने का है।

टी47 वर्ग में हिस्सा लेने वाले गावित ने पैरा खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के दौरान कहा, ''मैं एशियाई खेलों में 100 मीटर और 400 मीटर में विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। 2022 में हांगझोउ एशियाई खेलों में मैंने 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में मैंने पहली बार 100 मीटर में हिस्सा लिया और इन खेलों के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता।'' गावित ने कहा कि उनका लक्ष्य 100 मीटर में 10.28 सेकंड का समय निकालना है, जो भारत के पुरुष वर्ग के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के करीब है। उन्होंने बताया कि पहले वह सामान्य वर्ग की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेते थे और राष्ट्रीय स्तर तथा खेलो इंडिया खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। उस समय उनका मुख्य ध्यान 400 मीटर दौड़ पर था। टी47 वर्ग उन खिलाड़ियों के लिए होता है, जिनके हाथों में किसी प्रकार की परेशानी होती है, जैसे एक हाथ का कट जाना या उसकी कार्यक्षमता कम होना। इसका असर संतुलन, तालमेल और दौड़ने की तकनीक पर पड़ सकता है। गावित का मानना है कि एशियाई खेलों में चुनौती काफी कठिन होगी। उन्होंने कहा, ''मैं 400 मीटर और 100 मीटर दोनों में हिस्सा लूंगा। वहां प्रतिस्पर्धा का स्तर काफी ऊंचा होगा। मेरे कोच उसी के अनुसार मेरी तैयारी कराएंगे।'

भारत–श्रीलंका में 35 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता पर समझौतों का आदान–प्रदान

एजेंसी, नई दिल्ली

श्रीलंका की एक दिन की यात्रा पर गए विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बुधवार को राजधानी कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने आपसी हितों से जुड़े मुद्दों और भारत की सहायता से श्रीलंका में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान दोनों देशों ने 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर की भारतीय रुपये मूल्यवर्ग (आईएनआर) आधारित ऋण सहायता (लाइन ऑफ क्रेडिट) से जुड़े समझौतों का भी आदान–प्रदान किया।

श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि विदेश सचिव विक्रम मिसरी की राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ हुई बैठक में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने तथा भारत की सहायता से श्रीलंका में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक के बाद दोनों पक्षों ने 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रुपये आधारित लाइन ऑफ क्रेडिट से संबंधित समझौतों का आदान–प्रदान किया। यह ऋण सहायता भारत की ओर से चक्रवात 'दित्वाह' के बाद श्रीलंका को दिए गए 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्माण सहायता पैकेज का हिस्सा है। इन ऋण सहायता समझौतों का उपयोग चक्रवात के बाद पुनर्निर्माण कार्यों, आधारभूत ढांचा विकास और आवश्यक सामग्री की खरीद संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

अप्रैल या मई–2027 में आएंगे प्लास्टिक के नोट

एजेंसी, नई दिल्ली। ये प्लास्टिक करेंसी की प्रतीकात्मक फोटो है। पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट अगले साल अप्रैल–मई के बीच लॉन्च होंगे। यह जानकारी आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, यानी एमपीसी की तीन दिन चली बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में कम वैल्यू के पॉलीमर करेंसी नोट जारी किए जाएंगे। इनका मार्केट में सर्कुलेशन और इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया व कनाडा में पॉलीमर करेंसी नोट 30 साल से भी अधिक समय तक सफलतापूर्वक उपयोग में रहे हैं।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले- कम मूल्य वाले नोटों से होगी शुरुआत

बता दें कि भारत में कागजी नोट, विशेषकर 10, 20 और 50 रुपए के छोटे नोट, बहुत जल्द गंदे हो जाते हैं या फटने लगते हैं। आरबीआई के गवर्नर ने कहा– पॉलीमर नोट आने से इनकी उम्र बढ़ेगी, पानी या नमी से ये खराब नहीं होंगे और बार–बार नए नोट छापने का सरकारी खर्च भी कम होगा।

विपक्ष की आवाज सुनने को तैयार नहीं सरकार: वेणुगोपाल

एजेंसी, नई दिल्ली

कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने संसद में जारी गतिरोध के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार जनता और विपक्ष की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहा है, लेकिन सरकार किसी भी विषय पर चर्चा नहीं कराना चाहती।

संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष देश की जनता की आवाज को संसद में उठा रहा है, लेकिन सरकार उसे सुनने के बजाय उससे बच रही है। गृहमंत्री संसद में आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। संसद में जारी गतिरोध का समाधान सरकार को ही निकालना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की। बिहार में छात्रों पर एके 47 चलाई गई। इन घटनाओं पर गृहमंत्री को संसद में जवाब देना चाहिए। विपक्ष केवल इन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। वेणुगोपाल ने राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी पर कहा कि इस मामले में जवाबदेही तय नहीं की गई है और न ही निष्पक्ष जांच कराई जा रही है।

विपक्ष यह जानना चाहता है कि राम मंदिर के चढ़ावे के मामले में क्या हुआ, लेकिन सरकार इस पर चर्चा से बच रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने संसद में ई–20 से जुड़े मुद्दे और जम्मू–कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का विषय भी उठाया है। ये सभी जनहित के मुद्दे हैं, लेकिन सरकार इनमें से किसी पर भी चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है।

220 रुपए तक सस्ता हुआ सोना, चांदी में बदलाव नहीं

एजेंसी, नई दिल्ली

सर्राफा बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान सोने के भाव में गिरावट का रुख नजर आ रहा है, वहीं चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चेन्नई के अलावा देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना आज 200 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 220 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। वहीं चेन्नई में सोने का भाव आज 520 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 570 रुपये प्रति 10 ग्राम तक टूट गया है। कीमत में आई गिरावट के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,43,990 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,44,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर किया।

इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,31,990 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,32,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में बदलाव नहीं होने की वजह से ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज भी 2,34,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,44,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,140 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,43,990 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,31,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,44,040 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,040 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

बाजार | हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर बंद

सेंसेक्स 152 अंक चढ़कर 78,581 पर पहुंचा

एजेंसी, नई दिल्ली

हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। एफपीसी के फैसले का असर शेयर बाजार पर देखने को मिला। सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 9.75 अंक बढ़कर 24,624.65 पर बंद हुआ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार चौथी बार प्रमुख नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने के बाद बुधवार को उतार–चढ़ाव भरे सत्र में बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर बंद हुआ।

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 152.05 अंक या 0.19 प्रतिशत बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। इसके 17 शेयरों में बढ़त, 12 में गिरावट और एक शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ। सूचकांक की शुरुआत तेजी के साथ हुई और सत्र के पहले भाग में इसने 79,055.38 का दिन का उच्चतम स्तर छुआ। हालांकि, दोपहर बाद के सत्र में सूचकांक में गिरावट आई और यह 769.64 अंक गिरकर 78,285.74 के निचले स्तर पर पहुंच गया। सत्र के समापन से पहले ब्लूचिप बैंकिंग, ऑटो और पूंजीगत सामान शेयरों में आई तेजी ने सूचकांक को नुकसान से उबरने में मदद की। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 9.75 अंक या 0.04 प्रतिशत बढ़कर 24,624.65 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान इसने 24,677.60 का उच्च स्तर और 24,497.95 का निम्न स्तर छुआ।

निफ्टी 9.75 अंक बढ़कर 24,624.65 पर हुआ बंद

आरबीआई ने ब्याज दरों को रखा तटस्थ

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया और अपने तटस्थ नीतिगत रुख को बरकरार रखा। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को जून में अनुमानित 6.6 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है। बैंक ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष और व्यापार तनाव से उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद, मजबूत घरेलू मांग, विनिर्माण और सेवा गतिविधियों और मजबूत निर्यात के समर्थन से घरेलू विकास लचीला बना हुआ है।